



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 8, 2015/आश्विन 16, 1937

No. 261]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 2015/ASVINA 16, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2015

अंतिम जाँच परिणाम

विषय : चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सभी प्रकार के प्लास्टिक प्रसंस्करण या इंजेक्शन माउल्डिंग, जिसे इंजेक्शन प्रेसेस के रूप में भी जाना जाता है जिनका क्लेम्पिंग बल 40 टन से कम और 1000 टन से अधिक नहीं होता है, के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णयिक समीक्षा

सं. 15/02/2014-डीजीएडी.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

प्राधिकारी द्वारा दिनांक 8 जुलाई, 2008 की अधिसूचना सं. 14/12/2008-डीजीएडी द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल जाँच की शुरूआत की गई थी। प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जाँच परिणाम दिनांक 10 फरवरी, 2009 की अधिसूचना सं. 14/12/2008-डीजीएडी द्वारा जारी किए गए थे और राजस्व विभाग द्वारा अनंतिम पाटनरोधी शुल्क 12 मई, 2009 की अधिसूचना संख्या 47/2009-सीमाशुल्क द्वारा लगाया गया। प्राधिकारी द्वारा अंतिम जाँच परिणाम दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना सं. 14/12/2008-डीजीएडी द्वारा जारी किए गए थे जिनमें निश्चयात्मक शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी। प्राधिकारी द्वारा अंतिम जाँच परिणाम में की गई सिफारिश के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2010 की अधिसूचना सं. 39/2010-सीमाशुल्क द्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू किया गया था।

3. मै. प्लास्टिक्स मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपने सदस्यों अर्थात् (क) मै. तोशीबा मशीन (चेन्नई) प्रा. लि., (ख) मै. केरोमैटिक मिलाक्रोन इंडिया प्रा. लि. (ग) मै. विंडसर मशीन्स लिमिटेड और (घ) मै. इलेक्ट्रोनिका प्लास्टिक मशीन्स लि. के साथ अधिनियम और नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष विधिवत रूप से साक्षात्कृत आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाठन के जारी रहने और उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने का आरोप लगाया गया है और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे जारी रखने का अनुरोध किया गया है।

4. प्रस्तुत किए गए विधिवत रूप से साक्षात्कृत आवेदन और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार प्राधिकारी ने दिनांक 9 मई, 2014 की अधिसूचना सं. 15/2/2014-डीजीएडी द्वारा निर्णयिक समीक्षा जाँच की शुरूआत की ताकि चीन जन. गण. (जिसे एतदपश्चात संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जा सके और इस बात की जाँच की जा सके कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाठन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की आशंका है।

ख. प्रक्रिया

5. इस जाँच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

- i. प्राधिकारी ने उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों और घरेलू उत्पादकों को दिनांक 9 मई, 2014 की जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की प्रतियां भेजीं। ज्ञात हितबद्ध पक्षों से विहित समय-सीमा के भीतर लिखित में प्रश्नावली का उत्तर देने और उनके विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया। निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रतियां ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की एक सूची के साथ संबद्ध देश के दूतावास को भी भेजी गई तथा उनसे संबद्ध देश से निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय-सीमा के भीतर उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध किया गया।
- ii. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली 6(3) के अनुरूप आवेदक की ओर से प्रस्तुत किए गए आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति ज्ञात निर्यातकों, अन्य घरेलू उत्पादकों और संबद्ध देश के दूतावास को उपलब्ध कराई थी।
- iii. नियमावली के नियम 6(2) एवं 6(4) के अनुसार प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को निर्णयिक समीक्षा की शुरूआत की, सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी और उन्हें पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित में उनके विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया:

 1. की हिंग चेत्रंग की कं. लि.
 2. हुबेर्झ हेंगडा मशीनरी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं.लि.
 3. निंग्बो हेंगरून प्लास्टिक मशीनरी कं. लि.
 4. जिनिंग तांगजिआ मशीनरी कं. लि.
 5. जिंगजियांग जिनयुआत इंटरनेशनल ट्रेड कं.लि.
 6. मिटस्ट्रांग माउल्ड एंड मशीन कं.लि.
 7. मिंगबो इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जोन हायटोंग मशीनरी एंड इक्विपमेंट कं. लि.
 8. हेंगज्ञाउ टेडेरिक मशीनरी कं. लि.
 9. गुआंगज्ञाउ बोर्च मशीनरी कं. लि.
 10. ज्ञेजियांग गोल्डेल ईगल प्लास्टिक्स मशीनरी कं. लि.
 11. लिगुआंग मशीनरी कं. लि.
 12. निंग्बो इहैसिंग मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कं. लि.
 13. किंगडाओ सेनाइलप्लास्टिक्स मशीनरी लि.
 14. ज्ञेंगजिआनगैंग न्यू वांडा मशीनरी कं. लि.
 15. ज्ञेजिआंग ईस्ट झुकलेंग प्लास्टिक्स एंड पाउल्ड इंडस्ट्री कं. लि.

16. झेंगजिआंगेंग किंग मशीन कं. लि.
17. शंघाई जीएस मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कं. लि.
18. सूझोउ फोसिटा साइंस एंड टेक्नॉलॉजी कं. लि.
19. क्रिडाओं रुंजिआ प्लास्टिक मशीनरी कं. लि.
- iv. संबद्ध जॉच की शुरूआत के उत्तर में केवल मै. एंगल मशीनरी (शंघाई) कं. लि. और उसकी सहायक कंपनी एंगल मशीनरी (चांगझू) कं. लि. ने उत्तर दिया है। तथापि कंपनी ने विहित ढंग और तरीके से प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। चाइना प्लास्टिक मशीनरी इंडस्ट्री एसोसिएशन ने भी प्रश्नावली का कोई उत्तर दिए बिना याचिका और जॉच की शुरूआत का उत्तर दिया है।
- v. पाठनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी गईः
- क) इलेक्ट्रॉनिक प्लास्टिक मशीन लि. (ताल मूलशी, पुणे)
 - ख) प्लास्टिक्स मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया(नई दिल्ली)
 - ग) फेरोमैटिक मिलाक्रोन इंडिया प्रा. लि.(अहमदाबाद)
 - घ) विंडसर मशीन्स लिमिटेड (थाणे)
 - ड) तोशीबा मशीन्स प्रा. लि. (चेन्नई),
 - च) भारत बॉक्स फैक्टरी लि. (पंजाब)
 - छ) कुन्सटोकॉम (इंडिया) लि. (नई दिल्ली)
 - ज) सुमि मदरसन ग्रुप (नोएडा)
 - झ) सुप्रीम इंडस्ट्रीज लि. (मुम्बई)
 - ञ) विद्युत मैटालिक्स लि. (महाराष्ट्र)
 - ट) प्रिंस प्लास्टिक्स इंटरनेशनल प्रा. लि. (थाणे)
 - ठ) प्रिंस प्लास्टिक्स इंटरनेशनल प्रा. लि. (मुम्बई)
 - ड) अरुण प्लास्टो माउल्डर्स इंडिया प्रा. लि. (तमिलनाडु)
 - ढ) माउल्डवेल प्रॉडक्ट्स (तमिलनाडु)
 - ण) सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (तमिलनाडु)
 - त) रिया माल्डर्स(चेन्नई)
 - थ) सीजे पॉलीटेक प्रा. लि. (तमिलनाडु)
 - द) टेक प्लास्टिक इंडस्ट्रीज(चेन्नई)
 - ध) शक्ति पॉलीमर्स (तमिलनाडु)
 - न) टूलिंग टैम्पल (तमिलनाडु)
 - ञ) विक्टोरियस इंजीनियरिंग वर्क्स (उ.प्र.)
 - प) ईजाब्स इंफो टेक इंडिया प्रा. लि. (कोयम्बटूर)
 - फ) इलेक्ट्रॉनिका मशीन टूल्स लि. (पुणे)

- ब) मोल्डवेल प्राइवेट इंडिया प्रा. लि. (तमिलनाडु)
- भ) ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफॅक्चर्स एसोसिएशन (मुम्बई)
- vi. उक्त अधिसूचना के उत्तर में किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है।
- vii. ऐसे नियर्यातिक, उत्पादक और अन्य हितबद्ध पक्ष जिन्होंने न तो प्राधिकारी को उत्तर दिया है और न ही इस जाँच से संगत सूचना प्रस्तुत की है, उन्हें असहयोगी हितबद्ध पक्ष माना गया है।
- viii. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से जाँच अवधि समेत विगत तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के ब्योरे की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया था, जो प्राधिकारी को प्राप्त हुए थे। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा और अपेक्षित विक्षेपण की गणना के लिए डीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- ix. सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन की ईष्टतम लागत और उसे बनाने और बेचने की लागत को ज्ञात किया गया है इस बात का पता लगाया जा सके कि पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली अति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा। क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) को पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-॥। में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित किया गया है।
- x. यह जाँच (पीओआई) अक्टूबर, 2012 से शुरू होकर न-दिसम्बर, 2013 तक की अवधि के लिए की गई थी। तथापि, क्षति जाँच में 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012- 2013 की अवधि तथा जाँच की अवधि शामिल है।
- xi. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 17 मार्च, 2015 को आयोजित आम सुनवाई में अपना दृष्टिकोण मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने अनुरोध और उनके बाद खंडनों को लिखित रूप में प्रस्तुत करें।
- xii. इस जाँच के दौरान हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर इस जाँच परिणाम में संगत पाई गई सीमा तक विचार किया गया है। घरेलू उद्योग और सहयोगी उत्पादकों/नियर्यातिकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और आंकड़ों के संबंध में आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया था।
- xiii. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जाँच उनके गोपनीयता के दावे के पर्याप्त होने के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर इस प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय भाग उपलब्ध करायें।
- xiv. जहां भी किसी हितबद्ध पक्ष ने वर्तमान जाँच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना जुटाने से मना किया अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराया या जाँच में अत्यधिक बाधा डाली तो प्राधिकारी ने अपने पास "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर प्रकटन विवरण को दर्ज किया है।
- xv. नियमावली के नियम 16 के अनुसार प्राधिकारी ने 30 जुलाई, 2015 को जारी प्रकटन विवरण के द्वारा को मामले के अनिवार्य तथ्यों प्रकटन किया था और उक्त प्रकटन विवरण के संबंध में हितबद्ध पक्षों से 4 अगस्त, 2015 को टिप्पणियां भी प्राप्त हुईं। तथापि, निर्दिष्ट प्राधिकारी के इसी बीच बदल जाने के कारण पुनः सुनवाई आवश्यक हो गई इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा जाँच पूरा करने की अवधि को 7 नवम्बर, 2015 तक बढ़ा दिया गया।
- xvi. प्राधिकारी ने नए निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष अपने मामले को रखने का सभी हितबद्ध पक्षों को अवसर देने के लिए 19 अगस्त 2015 को एक नई सुनवाई की।
- xvii. प्राधिकारी ने 14 सितम्बर, 2015 को पुनःप्रकटन विवरण भी जारी किया जिसमें सभी हितबद्ध पक्षों की टिप्पणियों के लिए सभी अनिवार्य तथ्य और हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध शामिल थे।
- xviii. 30 जुलाई, 2015 को पहले प्रकटन विवरण 19 अगस्त 2015 को सार्वजनिक सुनवाई के बाद और 14 सितम्बर 2015 को दूसरे प्रकटन विवरण के उत्तर में हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोधों पर इन जाँच परिणामों में उनके संगत होने और विश्वसनीय सूचना/आंकड़ों/साक्ष्य द्वारा समर्थित होने की सीमा तक विचार किया गया और शामिल किया गया है।
- xix. इस निष्कर्ष में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से विचार किये जाने का द्योतक है।

xx. पीओआई के लिए औसत विनियम दर इस प्राधिकारी द्वारा 58.05 रुपया = 1 अमरीकी डॉलर के रूप में लिया गया है।

ग. विचाराधीन उत्पाद का दायरा और समान वस्तु

6. मूल जाँच में विचाराधीन उत्पाद को "सभी प्रकार के प्लास्टिक प्रसंस्करण या इंजेक्शन माउलिंग, जिसे इंजेक्शन प्रेसेस के रूप में भी जाना जाता है जिनका क्लेमिंग बल 40 टन से कम और 1000 टन से अधिक नहीं होता है, जिनका उपयोग प्लास्टिक सामग्रियों के प्रसंस्करण या मोलिंग में किया जाता है" के रूप में परिभाषित किया गया था। तथापि, निम्नलिखित प्रकार के उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया:

 - i. सीमाशुल्क टैरिफ वर्गीकरण सं. 847730 के अंतर्गत वर्गीकृत ब्लो मोलिंग मशीनें;
 - ii. वर्टिकल इंजेक्शन मोलिंग मशीनें;
 - iii. ऐसी सभी इलेक्ट्रिकल मोलिंग मशीनें जिनमें यांत्रिक गतिविधियों जैसे इंजेक्शन, मोल्ड बंद करना, मोल्ड खोलना, इंजेक्शन, स्क्रू ड्राइव आदि को स्वतंत्र सर्वो मोटरों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और जिनमें हाइड्रोलिक यूनिट के बीना डिजिटल नियंत्रण प्रणाली होती है;
 - iv. फुटवियर बनाने के लिए, रोटरी इंजेक्शन के लिए मल्टी कलर/मल्टी-मोल्ड मशीनरी, फुटवियर और फुटवियर के सोल/स्ट्रेप/हील बनाने के लिए मोलिंग मशीनरी इंजेक्शन मोलिंग मशीन जो सीमाशुल्क टैरिफ वर्गीकरण सं. 8453 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं।

7. संबद्ध वस्तु के किसी भी उत्पादक, निर्यातक या आयातक ने प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। तथापि एंजेल मशीन्स ने अपने अनुरोध ने यह तर्क दिया कि एंजेल मशीन्स के "दो प्लेटेन डिजाइन" (1000 क्लेमिंग बल तक के लिए) पूर्व में और जाँच की मूल अवधि में भारत में किसी कंपनी द्वारा निर्मित नहीं हुए हैं। एक घरेलू विनिर्माता ने हाल ही में इस डिजाइन की मशीनें बनाना शुरू किया है और काफी कम इकाइयों का निर्माण किया है। परंतु वे 1000 टन से अधिक की हैं। अंतः निर्दिष्ट प्राधिकारी को सत्यापन करना और विचाराधीन उत्पाद के दायरे से मशीनों की ऐसी श्रेणी को बाहर रखना होगा जिनका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है।
8. अपने प्रकटन के बाद के अनुरोधों में एंजेल ने यह भी तर्क दिया है कि 'दो प्लेटेन' डिजाइन प्रौद्योगिकी में एक विकास है और उसे कार्यनिष्पादन संबंधी अनेक मापदंडों के अनुसार मशीन कार्यनिष्पादन की बड़ी उपलब्धि माना जाता है और इसलिए वह केवल एक विशेषता ही नहीं है क्योंकि ये मशीनें सभी अन्य डिजाइनों की तुलना में काफी उच्चतर हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि समान प्रौद्योगिकी लाइनों पर सभी विद्युतीय मशीनों को जाँच के दायरे से बाहर कर दिया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि घरेलू मशीनें एंजेल की मशीनोंकी तुलना में काफी सस्ती हैं और इसलिए एंजेल की मशीनों के आयात से भारतीय उद्योग को तुकसान नहीं होगा।
9. सीपीपीएमए ने अपने अनुरोध में यह तर्क दिया है कि पीयूसी के दायरे में व्यापक प्रकार की मशीनें शामिल हैं जिससे याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किए गए पाटन और मार्जिनों की गलत गणनाएं होने की संभावना है। यहां तक कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित नहीं किए जाने वाले कतिपय प्रकारों को पीयूसी के दायरे में रखा गया है। प्राधिकारी को ऐसी किस्मों को पीयूसी के दायरे से बाहर रखना चाहिए जो शुल्क के पाँच वर्षों के बाद भी याचिकाकर्ता द्वारा विनिर्मित नहीं होती हैं।
10. घरेलू उद्योग ने अपने अनुरोधों में यह तर्क दिया है कि चूंकि वर्तमान जाँच मौजूदा शुल्कों की निर्णयिक समीक्षा है इसलिए विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जाँच के दायरे के समान ही रहता है। किसी भी तरह निर्दिष्ट प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए एक जैसे विवरणों पर विचार नहीं कर सकते हैं। हितबद्ध पक्षों के लिए उत्पाद के उस प्रकार की पहचान करनी होगी जिसके लिए समान वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं की जाती है।
11. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि वर्तमान जाँच एक निर्णयिक समीक्षा है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद आम तौर पर मूल जाँच के समान ही रहता है। यह भी नोट किया जाता है कि प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनों को क्लेमिंग बलों के अनुसार वर्णित विभिन्न आकारों और क्षमताओं में उत्पादित किया जाता है। घरेलू उत्पादक और विदेशी उत्पादक विभिन्न क्लेमिंग बलों और भिन्न-भिन्न अतिरिक्त विशेषताओं के साथ भिन्न- भिन्न प्रकार की प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनों का निर्माण करते हैं और अलग-अलग क्षमताओं वाली मशीनों का उत्पादों के कतिपय समूह की मालिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। घरेलू उद्योग अलग-अलग क्लेमिंग बलों की मशीनों का उत्पादन करता है और उन सीमाओं के भीतर संबद्ध देश में उत्पादकों द्वारा उत्पादित मशीनें समान वस्तुएँ हैं और तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से पूर्णतः प्रतिस्थापनीय हैं। अंतः ये उत्पाद उनकी क्लेमिंग बल सीमाओं के भीतर परस्पर समान उत्पाद हैं और समान से समान की तुलना के प्रयोजनार्थ अलग-अलग क्षमताओं/क्लेमिंग बलों वाली प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनों को मूल जाँच में अलग-अलग उत्पाद प्रकार माना गया था और संभव सीमा तक समान से समान आधार पर तुलनाएं की गई थी। वर्तमान जाँच में भी इसी पद्धति का प्रयोग करना प्रस्तावित है। अंतः हितबद्ध पक्षों का यह तर्क कि उनके द्वारा विनिर्मित और आपूर्ति कतिपय उत्पाद प्रकारों को जाँच के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए, व्यवहार्य नहीं है।

12. एंजेल मशीन्स के इस तर्क के संबंध में कि दो प्लेटेन इंजेक्शन मालिंग मशीन को दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस मामले को मूल जॉच में भी उठाया गया था और प्राधिकारी इस आधार पर दो प्लेटेन इंजेक्शन मालिंग मशीनों को बाहर करना आवश्यक नहीं समझते हैं कि इंजेक्शन मालिंग मशीन की क्लेम्पिंग इकाई में प्लेटेन्स (2 प्लेटेन्स या 3 प्लेटेन्स) की संख्या इंजेक्शन मालिंग मशीन की उप-अनुरोधियों (क्लेम्पिंग इकाई) का केवल एक भौतिक मापदंड होता है और इसलिए क्लेम्पिंग इकाई में 2 या 3 प्लेटेनों की मौजूदगी का परिणाम अलग-अलग प्रकार की इंजेक्शन मालिंग मशीन नहीं होती है। अतः प्राधिकारी ने क्लेम्पिंग इकाई में प्लेटेनों की संख्या के आधार पर इंजेक्शन मालिंग मशीनों को बाहर रखने की सिफारिश नहीं की। प्रकटन के बाद के अपने अनुरोधों में एंजेल ने अन्तर्गत कार्यनिष्ठादान और कीमत अंतरों के आधार पर इन मशीनों को जॉच से बाहर रखने संबंधी अपने तर्कों को दोहराया है परंतु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जो यह सिद्ध कर सके कि ये मशीनें भौतिक विशेषताओं, तकनीकी और वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता आदि की दृष्टि से संबद्ध वस्तु के समान वस्तु नहीं हैं। अतः प्राधिकारी को अपने दृष्टिकोण का बदलने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है। अतः प्राधिकारी मूल जॉच के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के दायरे की पुष्टि करते हैं।
13. केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2010 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 39/2010-सीमाशुल्क द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के सीमाशुल्क शीर्ष 8477.1000 के अंतर्गत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू किया गया था। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जॉच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं हैं।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

14. समीक्षा के लिए आवेदन भारत में प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनों के उत्पादकों की ओर से प्लास्टिक्स मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (जिसे एतदपश्चात याचिकार्ता या पीएमएआई कहा गया है) ने दायर किया है। उसके चार सदस्य अर्थात् (i) मै. तोशीबा मशीन्स (ii) मै. फेरोमैटिक मिलाक्रोन (iii) मै. विंडसर इंडिया और (iv) मै. इलेक्ट्रोनिका मशीन्स, जो भारत में विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादक हैं और भारत में संबद्ध वस्तु के कुल उत्पाद का 90 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं, ने आवेदन में संगत सूचना प्रदान की है जिसमें संबद्ध देश से पीपीएम के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की मांग की गई है।
15. रिकार्ड के अनुसार, यह नोट किया गया कि मै. फेरोमैटिक मिलाक्रोन इंडिया प्रा. लि. एक चीनी कंपनी अर्थात् मै. मिलाक्रोन प्लास्टिक्स मशीनरी (जिआनगियन) कं. लि. से संबंधित है। यह भी नोट किया जाता है कि मै. तोशीबा मशीन (चेन्नई) प्रा. लि., चीन के एक उत्पादक मै. तोशीबा मशीन (शंघाई) कं. लि. से संबंधित है। तथापि मै. तोशीबा मशीन (शंघाई) कं. लि. एक समूह कंपनी है और वह केवल इंजेक्शन मालिंग मशीनों का विनिर्माण करती है जो प्रस्तावित जॉच की विषय-वस्तु नहीं है।

घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि कानून की यह सुस्थापित स्थिति है कि प्राधिकारी अपने विवेकानुसार ऐसे किसी उत्पादक को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर कर सकता है जो या तो संबद्ध वस्तु के उत्पादक/निर्यातक से संबंधित हो या उसने संबद्ध वस्तु का आयात किया हो। यह बताया गया है कि यद्यपि फेरोमैटिक मिलाक्रोन इंडिया प्रा. लि., मिलाक्रोन प्लास्टिक्स मशीनरी, चीन जो संबद्ध वस्तु का विनिर्माण करती है, से संबंधित है तथापि मिलाक्रो, चीन ने इनमें से किसी मशीन का भारत को निर्यात नहीं किया है और मिलाक्रोन, भारत ने संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। अतः फेरोमैटिक मिलाक्रोन (इंडिया) और तोशीबा मशीन (चेन्नई) को घरेलू उद्योग का हिस्सा माना जाना चाहिए।

16. सीपीपीएम ने अपने अनुरोध में यह तर्क दिया है कि सार्वजनिक वेबसाइट में उपलब्ध सूचना के अनुसार मिलाक्रोन इंडिया के चीन के निर्यातिक के साथ संबंध नियम 2 (ख) के स्पष्टीकरण (i)(ख) के अंतर्गत आता है क्योंकि ये दानों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक तीसरे व्यक्ति अर्थात् मिलाक्रोन एलएलसी जो वास्तव में यूएसए मूल का है द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। अतः प्राधिकारी को संबंधी की प्रकृति और उनकी पात्रता निर्धारित करने के लिए संबंधित याचिकार्ता कंपनी से विस्तृत सूचना मांगनी चाहिए।

17. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि मै. तोशीबा मशीन (चेन्नई) प्रा. लि., मै. तोशीबा मशीन (शंघाई) कं. लि. से संबंधित हैं, तथापि मै. तोशीबा मशीन (शंघाई) कं. लि. केवल इंजेक्शन मालिंग मशीनों का विनिर्माण करती है जो प्रस्तावित जॉच की विषय-वस्तु नहीं है। जहां तक कि मै. फेरोमैटिक मिलाक्रोन इंडिया प्रा. लि. का संबंध है वह मिलाक्रोन एलएलसी, यूएसए की साझी धारिता के जरिए मिलाक्रोन प्लास्टिक्स मशीनरी, चीन से संबंधित है। परंतु मिलाक्रोन, चीन ने भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं किया है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि ये दो घरेलू उत्पादक और याचिकार्ता नियामवली में इस शब्द के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग का हिस्सा माने जाने के पात्र हैं और तदनुसार, पूर्वोक्त सभी चार घरेलू उत्पादकों को इस जॉच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग माना गया है।

इ. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दे

इ.1 नियर्यातकों/आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध

18. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी नियांतक या आयातक ने प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं दिया है। तथापि, चाइना प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनरी एसोसिएशन ने अपने अनुरोध में अन्य बातों के साथ-साथ बताया है :

- कि सीपीएमएआई व्यवसायिक एसोसिएशन की श्रेणी के अंतर्गत आता है और सीपीपीएमए के सभी 38 सदस्य संबद्ध वस्तु के उत्पादक, नियांतक हैं जो इस जाँच में हितबद्ध पक्ष के रूप में उन्हें पात्र बनाने के लिए नियम की दूसरी शर्त को पूरा करते हैं।
- कि सीपीएमएआई ने प्राधिकारी को खंडन और संगत सूचना प्रदान करके पूरे सहयोग की पेशकश की है। इसके सदस्यों द्वारा ईक्युआर प्रस्तुत नहीं किया गया है क्योंकि उन्होंने पीओआई या क्षति अवधि के दौरान भारत को नियांत नहीं किया है।
- कि भारतीय पाटनरोधी नियमों में नियांतक एसोसिएशनों द्वारा प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए कोई प्रपत्र विहित नहीं किया गया है। तथापि, सीपीपीएमए ने चीन में क्षमता, मांग, तीसरे देश को नियांत मात्रा, कीमत आदि जैसी संगत सूचना को अपने लिखित अनुरोध में प्रस्तुत किया है और उनके सत्यापन का प्रस्ताव किया है।
- कि हैसियन सीपीपीएमए का एक सदस्य है और सीपीपीएमए के अनुरोध हैसियन के लिए भी संगत और लागू हैं।
- कि घरेलू उद्योग ने सौदा-वार आयात आंकड़ों ने यह नहीं बताया है कि क्या ऐसी सूचना केवल पीयूसी से संबंधित है या उसमें किसी विशेष सीमाशुल्क उपशीर्ष में बताई गई गैर-पीयूसी मदों सहित सभी सौदे शामिल हैं।
- कि सीपीपीएमए के अनुसार याचिकाकर्ताओं ने सौदावार आंकड़ों में केवल गैर-पीयूसी मदों को उपलब्ध कराया है, उक्त आंकड़ों के अलावा उन्होंने उक्त पीओआई के दौरान 42 मशीनों के आयात को पीयूसी के रूप में अभिज्ञात किया है।
- कि सीपीपीएमए के सदस्यों ने जाँच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का नियांत नहीं किया है। इसी बात से याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आयात संबंधी विवरण विवादित हो जाता है। अतः, याचिकाकर्ता को यह दर्शाना चाहिए कि किस सौदे को विचाराधीन उत्पाद के रूप में अभिज्ञात किया गया है। जब तक ऐसी सूचना को अपरिष्कृत आंकड़ों में अभिज्ञात और चिह्नित नहीं किया जाता है तो सीपीपीएमए और प्राधिकारी भी आयात के उनके दावों के संबंध में याचिकाकर्ता के दावों की प्रमाणिकता की जाँच करने की स्थिति में नहीं होंगे।
- कि आवेदन में नियम 23 में निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाली सूचना नहीं दी गई है। आवेदन में उपलब्ध सूचना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि शुल्क की अवधि समाप्त होने से पाठन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना नहीं है।
- कि सीपीएमएआई ने यह दर्शनी के लिए संगत सूचना प्रदान की है कि चीन जन.गण. में कोई अधिक क्षमता नहीं है। उद्योग 90 प्रतिशत से अधिक के क्षमता उपयोग पर कार्य कर रहा है।
- कि घरेलू उद्योग द्वारा अत्यधिक गोपनीयता बनाई गई है जो पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के विरुद्ध है। अतः प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के लिए भारित औसत लागत और कीमत की सूचना को संचयी रूप से गोपनीय मानने के दावे की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

19. सीपीपीएमए के अलावा मै. एंजेल मशीनरी इंडिया प्रा.लि. ने एंजेल मशीनरी (शंघाई) कं.लि., चीन और एंजेल मशीनरी (चांगजाउ) कं.लि. चीन की ओर से दिए गए अपने संक्षिप्त अनुरोध में अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया है :

- कि एंजेल मशीन्स को आस्ट्रिया स्थित उसके मुख्य कारखाने में डिजाइन किया और विनिर्मित किया जाता है। वे एशिया में भी उक्त उल्लिखित कारखानों में संयोजित की जाती हैं परंतु अधिकांश इंजीनियरी संचाटक पश्चिमी यूरोप (एंजेल आस्ट्रिया, जर्मनी आदि) में विनिर्मित होते हैं।
- कि 1000 मी.टन तक के लिए एंजेल मशीनों के दो प्लेटेन डिजाइन पूर्व में और मूल जाँच की अवधि के दौरान किसी कंपनी द्वारा भारत में नहीं बनाए गए हैं। एक घरेलू विनिर्माता ने हाल में इन डिजाइन की मशीनों का विनिर्माण शुरू किया है और वहुत कम संख्या में विनिर्माण किया है परंतु वह 1000 मी.टन से अधिक का है।
- कि एंजेल से भारत को नियांत किसी भी तरह से स्थानीय उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। हमारी नियांत कीमतें भारतीय विनिर्माताओं से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक हैं। ऐसा पश्चिमी यूरोप (एंजेल आस्ट्रिया, जर्मनी आदि) में डिजाइन और निर्मित संचाटकों के काफी उच्च अवयवों के कारण है।
- कि चीन में एंजेल कारखाने से भारत को एंजेल मशीनों का नियांत आज की तारीख तक 1000 मी.टन से अधिक का रहा है। तथापि, भारत सरकार के “मेक इन इंडिया” अभियान के अंतर्गत और भारत में शीर्ष स्तर के वैश्विक उत्पादकों के प्रवेश से 1000 मी.टन से कम के आकारों में भी उच्च कार्य निष्पादन वाली मशीनों की मांग होगी।

- एंजेल मशीन्स की विशेषता उनकी बारीकी, उच्च कार्यनिष्पादन और प्रोद्योगिकी उन्मुखता है। ऐसे उपभोक्ता जिन्हें इस मूल्यवर्धन की जरूरत होती है वे प्रीमियम देने के लिए तैयार रहते हैं परंतु पुनः उच्च पाटनरोधी शुल्क का भुगतान करना उपभोक्ताओं के लिए काफी मुश्किल है।
- कि एंजेल चीन से 1000 मी. टन से कम की मशीनों का निर्यात करना चाहेगी परंतु पाटनरोधी शुल्कों के कारण ऐसा करना बिल्कुल असंभव है।
- कि एंजेल मशीनरी आस्ट्रिया और एंजेल मशीनरी शंघाई और एंजेल मशीनरी चांगज्ञाउ, चीन के बीच कीमत अंतर लंगभग 15-20 प्रतिशत है ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि आस्ट्रिया में अतिरिक्त लागत चीन की तुलना में काफी अधिक है।
- यह कि एंजेल मशीनरी चीन संयंत्र की 1000 मी. टन से कम क्षमता के लिए संयोजन क्षमता 380 मशीन प्रति वर्ष है। जबकि चीन की घरेलू बाजार की 1000 मी. टन से कम की मशीनों की जरूरत प्रति वर्ष लंगभग 28,350 मशीन हैं।
- कि एंजेल मशीनरी ने 2007 में चीन में संयोजन करना शुरू किया था ताकि पूरे एशिया बाजार और न कि केवल चीन के बाजार पर ध्यान दिया जा सके। यह एशियाई बाजार की मांग को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए था।
- कि एंजेल के पास विश्वभर में 30 से अधिक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं और व्यवसाय से पेशेवर और पारदर्शी एसएपी आधारित लेखांकन और प्रबंधन पद्धति के आधार पर चलाया जाता है जहाँ कीमत निर्धारण एक समान है और अंग्रेजी में प्रकाशित होता है। पूरे एशिया में प्रयुक्त कीमत सूची ही भारत और चीन में प्रयोग की जाती है और कीमत निर्धारण आस्ट्रिया स्थित मुख्यालय में होता है।
- अतः एंजेल मशीनरी (शंघाई) कं.लि., चीन और एंजेल मशीनरी (चांगज्ञाउ) कं.लि. चीन को पाटनरोधी शुल्क से छूट दी जानी चाहिए।

ड 2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

घरेलू उद्योग ने अपने विभिन्न अनुरोधों में अन्य हितबद्ध पक्षों के तर्कों का खंडन किया है और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अनुरोध किया है:

- कि चीन की एसोसिएशन को हितबद्ध पक्ष नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि उसने अपने सदस्यों को प्राधिकारी के साथ सहयोग करने और प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए नहीं कहा है। एसोसिएशन ने न केवल जॉच से संगत कोई सूचना नहीं दी है बल्कि एसोसिएशन ने यह गलत और गुमराह करने वाला विवरण भी दिया कि संगत विधि के दौरान चीन से भारत को पीयूसी का कोई निर्यात नहीं हुआ था।
- कि याचिकाकर्ताओं ने आयातों की पूरी सूची उपलब्ध कराई है जिसमें न केवल पीयूसी बल्कि गैर-पीयूसी भी शामिल हैं और इसलिए याचिका में पूरी सूचना उपलब्ध है।
- कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अत्यधिक गोपनीयता का कोई दावा नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रदान किया है।
- कि हैसियन जो चीन में एक प्रमुख उत्पादक हैं जिन्होंने मूल जॉच में प्राधिकारी से सहयोग किया था ने वर्तमान जॉच में कोई उत्तर नहीं देना पसंद किया है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि हैसियन भारत में संयोजन लाइन की सुविधा स्थापित करने का दावा कर रहा है और वियतनाम, जो जॉच के अधीन एक देश है, में पीयूसी के उत्पादन में कार्यरत है। स्पष्ट रूप से, हैसियन ने चीन में लागू पाटनरोधी शुल्कों से बचने के लिए वियतनाम में संयोजन लाइन की सुविधाएं स्थापित की हैं और अब वियतनाम द्वारा लागू किए जाने वाले पाटनरोधी शुल्कों से बचने के लिए भारत में संयोजन लाइन के प्रचालन स्थापित कर रहा है।
- कि एंजेल द्वारा परिकलित चीन की मांग एसोसिएशन द्वारा दावा की गई मांग से काफी भिन्न है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष सत्यापन योग्य तथ्य नहीं रख रहे हैं और गुमराह करने वाली सूचना दे रहे हैं।
- कि यदि एंजेल यह मानता है कि वस्तुएं चीन के उद्भव की हैं, तो यूरोप का उल्लेख करना असंगत है और यदि वस्तुएं पश्चिमी यूरोप के उद्भव की हैं और चीन में संयोजन की जाती हैं तो लागत और कीमत उतनी कम नहीं हो सकती है जिस कीमत पर भारत में चीन से आयात हो रहा है।
- एंजेल के अनुरोध के उत्तर में घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि निर्यातक द्वारा विहित ढंग और तरीके से कोई उत्तर नहीं दिया गया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी के वक्तव्यों पर आधारित किसी दावे पर विचार नहीं कर सकते हैं। यदि यह माना भी जाता है कि निर्यातक ने भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है तो भी निर्यातक को प्राधिकारी द्वारा विहित ढंग और तरीके से प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करना चाहिए। भारत को और तीसरे देशों

को नियर्ति के लिए जॉच अवधि के लिए सूचना वाले विहित ढंग और तरीके से प्रश्नावली के उत्तर और जो बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली से विधिवत रूप से समर्थित हो, के बिना निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात पर विचार नहीं कर सकते हैं कि क्या पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति कंपनी द्वारा नियर्तियों से नहीं हुई है।

- कि पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद, भारतीय उद्योग बाजार में उचित अवसर नहीं ले पा रहा है और भारतीय बाजार में पाटित आयात जारी हैं। घरेलू उद्योग की मुश्किलें देश में उत्पाद की मांग में शिरावट के कारण और बढ़ गई हैं। इन परिस्थितियों में वर्तमान पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के परिणामस्वरूप संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन के जारी रहने/उसके तेज होने/उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
20. इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने प्रकटन विवरण के बाद की अपनी टिप्पणियों में यह अनुरोध किया है कि प्राधिकारी को हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रदत्त तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर प्रकटन विवरण में निष्कर्ष उपलब्ध कराने चाहिए।

ड. 3 प्राधिकारी द्वारा जॉच

21. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चाइना प्लास्टिक प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (सीपीपीएमए) संबद्ध वस्तु के चीन के उत्पादकों, नियर्तियों की एक व्यवसायिक एसोसिएशन है जिसमें 38 सदस्य हैं। तथापि, इसके किसी सदस्य ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। एसोसिएशन ने भी चीन में संबद्ध वस्तु के उत्पादन और खमताओं, मांग और चीन से नियर्ति के बारे में कठिनपय अनुमान/सूचना के अलावा कोई सार्थक सूचना प्रस्तुत नहीं की है, यह किसी समर्थनकारी दस्तावेजों के बिना है जिससे प्राधिकारी को विभिन्न निर्धारण करने में मदद मिल सके।
22. उक्त के होते हुए भी, जॉच के संबंध में एसोसिएशन द्वारा उठाए गए मुद्दों को नोट किया गया है। प्राधिकारी ने उनके पास उपलब्ध आयात आकड़ों के अनुसार आयात आंकड़ों की जॉच की है ताकि विभिन्न निर्धारणों के लिए विचाराधीन उत्पाद से इतर उत्पाद को बाहर किया जा सके। विचाराधीन उत्पाद को वर्णनों और अन्य ब्योरों के आधार पर व्यवहार्य सीमा तक सौदा-वार आंकड़ों से अभिज्ञात किया गया है और इसलिए अन्य हितबद्ध पक्षों की चिंताओं का पर्याप्त रूप से समाधान किया गया है। तथापि, एसोसिएशन के यह दावे कि संबद्ध वस्तु का नियर्ति चीन से नहीं किया किया गया है रिकार्ड में साक्ष्यों से सिद्ध नहीं होता है क्योंकि प्राधिकारी द्वारा आयात आंकड़ों की जॉच की गई है कि 17 मशीनों का जॉच अवधि के दौरान चीन से आयात हुआ है। आंकड़ों को सार्वजनिक फाइल में भी रखा गया है।
23. जहां तक गोपनीयता संबंधी मुद्दों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी सूचना जो गोपनीय प्रकृति की है और हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई है को प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो प्राधिकारी द्वारा अपनायी गई सामान्य प्रक्रिया के अनुसार गोपनीयता के दावों की पर्याप्त जॉच करने के बाद गोपनीय माना है। संभव सीमा तक गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। अतः हितबद्ध पक्षों की चिंताओं का पर्याप्त रूप से निवारण किया गया है।
24. जहां तक एंजेल मशीन, चीन के अनुरोध को संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसने अब तक 1000 मी.टन से अधिक क्लेमिंग बल की मशीनों का ही नियर्ति किया है, जो इस जॉच में संबद्ध वस्तु नहीं हैं। अतः इस समय वे भारत को संबद्ध वस्तु के नियर्तिक नहीं हैं। भविष्य में नियर्तियों की संभावना में छूट संबंधी अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है। नियमावली में न्यू पर समीक्षा का एक अलग उपबंध है यदि वे भविष्य में संबद्ध वस्तु का नियर्ति करना चाहते हैं तो वे इसका लाभ उठा सकते हैं। अतः उनके द्वारा किए गए अन्य अनुरोध पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।
25. जहां तक घरेलू उद्योग के इस तर्क का संबंध है कि प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रदत्त तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष दिए गए होने चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली का नियम 16 यह उपबंध करता है कि अपने अंतिम जॉच परिणाम देते हुए प्राधिकारी को ऐसे विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों को सभी हितबद्ध पक्षों को अवगत कराएंगे जो उनके निर्णय का आधार हैं। अतः प्रकटन विवरण में सभी अनिवार्य तथ्य और प्राधिकारी द्वारा अपनायी गई प्रस्तावित पद्धति को दिया गया है। अंतिम निष्कर्ष प्रकटन के संबंध में हितबद्ध पक्षों से टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद निकाले गए हैं। चूंकि निष्कर्ष प्रकटन के स्तर पर निकाले नहीं गए थे, इसलिए वे प्रकटन विवरण का हिस्सा नहीं हो सकते हैं।
26. पाटन और क्षति निर्धारण आदि के संबंध में हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अन्य सभी अनुरोधों का संबंधित खंडों में समाधान किया गया है।

च. वर्तमान पाटन और पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का निर्धारण

च.1 विधिक स्थिति

29. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क (5) में प्रावधान है कि :-

“इस धारा के अंतर्गत लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को यदि उसे पहले नहीं हटाया जाता है तो वह उसे लागू किए जाने की तारीख से पाँच वर्षों तक लागू रहेगा।

बशर्ते कि यदि केन्द्र सरकार की किसी समीक्षा में, यह राय हो कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और क्षति होने की संभावना है तो वह समय-समय पर शुल्क की अवधि में अगले पाँच वर्षों के लिए वृद्धि कर सकती है और ऐसी आगामी अवधि उसे बढ़ाए जाने के आदेश की तारीख से लागू होगी।

बशर्ते यह भी कि जहां ऐसी समीक्षा पाँच वर्षों की पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पहले पूरी नहीं हो जाती है वहां पाटनरोधी शुल्क ऐसी किसी समीक्षा के परिणाम के लम्बित होने तक एक वर्ष तक की आगामी अवधि तक लागू रहेगा।”

30. तदनुसार, कोई निर्णायक समीक्षा इस बात की जाँच करने के लिए की जाती है कि:

- क्या पाटनरोधी शुल्क के लागू होने के बाद भी पाटन जारी है और यदि हां तो क्या उसके जारी रहने की संभावना है।
- यदि पाटन जारी नहीं रहा है तो क्या यदि पाटनरोधी शुल्कों को हटाया जाता है तो क्या पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
- क्या घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होना जारी है और यदि हां तो क्या यदि शुल्क को हटाया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने की संभावना है।
- ऐसे मामलों में जहां घरेलू उद्योग को क्षति होना जारी नहीं है वहां क्या यदि पाटनरोधी शुल्क को हटाया जाता है तो क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

31. अतः प्राधिकारी ने इस बात की जाँच करने से पहले कि क्या यदि शुल्क को हटाया जाता है तो पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और ऐसी स्थिति में क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है से इस बात की जाँच की है कि क्या संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का पाटन जारी है और क्या घरेलू उद्योग को ऐसे पारित आयातों के कारण वास्तविक क्षति होना जारी है।

च.2 पाटन के जारी रहने की जाँच : सामान्य मूल्य, निर्यात कीमतों और पाटन मार्जिनों का निर्धारण

32. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन से संबद्ध वस्तु के किसी भी निर्यातक ने उस देश से संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं दिया है। केवल सीपीपीएमए और प्रतिवादी आयातक ने तर्क दिया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को क्षति और पाटन मार्जिन के लिए समान तुलना हेतु किस्म-वार तुलना करनी चाहिए।

33. घरेलू उद्योग ने अपने अनुरोधों में यह तर्क दिया है कि चूंकि चीन एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है इसलिए संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का निर्धारण उस देश में प्रचलित कीमत के आधार पर नहीं किया जा सकता है और इसलिए उसका परिकलन होना चाहिए। चीन में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया है कि बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक प्रतिवादी निर्यातक/कंपनी और उसका सूपूर्ण समग्ररूप से इसका दावा न करें। बतामिन मामले में बाजार अर्थव्यवस्था के लिए कोई दावा नहीं किया गया है। चीन के किसी भी निर्यातक ने न तो प्रश्नावली का उत्तर दिया है और न ही बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा किया है। मूल जाँच में प्राधिकारी ने चीन के किसी निर्यातक को बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार प्रदान नहीं किया था और चीन में सामान्य मूल्य की गणना यथासंशोधित उक्त नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार तर्कसंगत लाभ के साथ चीन में संबद्ध वस्तु की अनुमानित उत्पादन लागत के आधार पर की थी। अतः याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी को वर्तमान जाँच में चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए उसी पद्धति पर विचार करना चाहिए।

34. घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया है कि उक्त परिस्थितियों में चीन में सामान्य मूल्य को (क) भारत में कीमत और (ख) भारत में उत्पादन लागत जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और लाभ सहित विधिवत रूप से समायोजित किया जाए के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। चीन में सामान्य मूल्य को भारत में विधिवत रूप से समायोजित उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित करना चाहिए।

35. याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में प्राधिकारी के पूरवर्ती निर्धारण में अपनाई गई पद्धति के आधार पर अलग-अलग क्लेम्पिंग बलों (उत्पाद प्रकारों) वाली मशीनों के सामान्य मूल्यों का अलग-अलग अनुमान प्रस्तुत किया है और यह अनुरोध किया है कि प्राधिकारी ने पूर्वर्ती जाँच में इस मामले की विस्तार से जाँच की थी और इस निष्कर्ष पर पंहुचे थे कि भारित औसत स्तर पर पाटन मार्जिन का निर्धारण इस मामले में उचित नहीं होगा और इसलिए उस मामले में पाटन मार्जिनों को अलग-अलग क्लेम्पिंग बल उत्पाद किस्म स्तर पर निर्धारित किया गया था। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित अंतिम जाँच परिणामों को सेस्टेट में कोई चुनौती नहीं दी गई। अतः पहले अपनाई गई निर्धारण पद्धति वैध सिद्ध हुई।

36. चीन से किसी उत्पादक/निर्यातक ने विहित ढंग और तरीके से सूचना देकर सहयोग नहीं किया है। घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया कि यदि यह माना भी जाता है कि भारत को किसी कंपनी द्वारा कोई निर्यात नहीं किया गया तो उसका यह अर्थ नहीं होता है कि कंपनी को निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर देने की जरूरत नहीं है। कंपनी को फिर भी प्रश्नावली को उत्तर देना होगा क्योंकि किसी निर्णायक समीक्षा में वास्तविक पाटन और उसकी संभावना दोनों महत्वपूर्ण हैं। घरेलू उद्योग यह तर्क देता है कि चीन जन. गण. से निर्यातक भारत में संबद्ध वस्तु का पाटन करना जारी रखे हुए हैं और पाटन मार्जिन काफी अधिक और निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

37. सीपीएमआईए ने प्राधिकारी के समक्ष अपने अनुरोध में यह तर्क दिया है कि कम मात्रा के साथ भारी पाटन मार्जिन का होना एक निराधार दावा है। आयात आंकड़ों को सही करना दर्शाता है कि चीन जन.गण.से कोई आयात नहीं हुआ है। केवल इसी आधार पर याचिकार्ता द्वारा बताए गए जारी पाटन का कोई सामला नहीं है। सीपीपीएमए ने यह भी तर्क दिया है कि प्राधिकारी को पाटन मार्जिन और धृति मार्जिन की किस्म-वार तुलना/निर्धारण की काफी कड़ी जाँच करनी चाहिए। किस्म-वार पीयूसी की किस्म-वार समान वस्तु की उचित और सही तुलना से वर्तमान मामले में ऋणात्मक पाटन और धृति मार्जिन प्रदर्शित होगा।

38. पहले प्रकटन विवरण के संबंध में अपनी टिप्पणियों में सीपीएमआईएने पहले प्रकटन में अपनाए गए आयात आंकड़ों में कठिपय खामियां बताई हैं। इस बात पर ध्यान दिलाया गया है कि प्रकटन विवरण में 10, 59,453/- रुपये प्रति मशीन की औसत सीआईएफ कीमत पर पीओआई के दौरान चीन जन.गण. से 17 पीपीएम के आयातों को दर्शाया गया है। आयात आंकड़ों में आधार वर्ष और पीओआई से तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के बीच कीमत में संगत वृद्धि हुई है और तत्काल पीओआई के दौरान कीमत में भारी गिरावट आई है और एक बार फिर पीओआई अवधि के तत्काल बाद भारी वृद्धि हुई है। यह अनुरोध किया गया है कि उनके द्वारा सौदावार आयात आंकड़ों की कड़ी जाँच स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि अनेक सौदे पीयूसी के नहीं हैं और अनेक गैर पीयूसी मदों को गलत ढंग से पीयूसी मान लिया गया है और इसके परिणामस्वरूप पीओआई के दौरान पीयूसी की सामान्यतः कम आयात कीमत हुई है और केवल जाँच अवधि के दौरान गिरावट उल्लेखनीय है और उपचार नहीं किया गया है।

39. इस संबंध में, सीपीएमआईए ने यह सिद्ध करने के लिए संबंधित मशीनों के उत्पाद कैटेलॉग प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि कुछ मशीनों के संबंध में विनिर्माताओं की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, कि मशीनें या तो काफी कम क्षमता की मशीनें हैं या मशीनों की उप-संयोजन हैं और विचाराधीन उत्पाद नहीं हैं।

40. हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रदत्त सकारात्मक साक्ष्य को देखते हुए निर्धारण के लिए प्रयुक्त आयात आंकड़ों की आगे जाँच की गई है और यह पाया गया है कि पूर्ववर्ती प्रकटन में 60, 75 और 100 एमटी के क्लेमिंग बल वाली के रूप में अभिज्ञात मशीनें 1 से 2 एमटी या संघटकों के क्लेमिंग बल वाली वास्तविक मशीनें हैं। अतः आंकड़ों को सुधारा गया है और चयनित आयात सूची का इस प्रकटन में प्रयोग किया गया है।

च. प्राधिकारी द्वारा जाँच और सामान्य मूल्य का निर्धारण

41. जाँच शुरूआत के स्तर पर प्राधिकारी ने इस मान्यता के साथ कार्यवाही की कि चीन जन.गण. एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है और चीन से उत्पादक/निर्यातकों को जाँच शुरूआत की सूचना का उत्तर देने और उनके बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में निर्धारण के लिए संगत सूचना प्रदान करने की सलाह दी। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8(3) में निर्धारित मापदंडों के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की मान्यता की खंडन करने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को एमईटी प्रश्नावली की प्रतिया भेजी। प्राधिकारी ने चीन की सरकार से भी चीन में उत्पादकों/निर्यातकों को संगत सूचना देने की सलाह देने का अनुरोध किया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूर्व के वर्षों में चीन जन.गण. को भारत और डब्ल्यूटीओं के अन्य सदस्यों द्वारा पाटनरोधी जाँचों में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है। उक्त स्थिति को देखते हुए और चीन की किसी नियांतक कंपनी द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की मान्यता के खंडन के अभाव में प्राधिकारी वर्तमान जाँच में चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानना उचित समझते हैं और चीन जन.गण. के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण के लिए नियमावली के अनुबंध-I के पैरा-7 के अनुसार कार्रवाई करने का प्रस्ताव करते हैं। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा-7 में उपबंध है कि:

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तवित रूप से संदर्भ अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित युंगाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नावत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जाँच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जाँच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में विना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।"

42. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी हितबद्ध पक्ष ने ऊपर उल्लिखित पैरा-7 में पहले दो विकल्पों के अनुसार किसी तीसरे देश में या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को लागत और कीमत के आधार पर चीन जन.गण. में सामान्य मूल्य की गणना के लिए प्रतिनिधि के रूप में समुचित तीसरे देश के चयन के लिए कोई सार्थक सूचना प्रदान नहीं की है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद में अलग-अलग क्लेमिंग बलों के संगत अनेक उत्पाद किसमें शामिल हैं। अतः किसी तीसरे देश से उसके उत्पाद के प्रकारों की पहचान के लिए उनकी लागत और कीमत के ब्योरों के बिना भारत को तीसरे देश या किसी प्रतिनिधि देश से आयात कीमत के आधार पर उत्पाद के सामान्य मूल्य का निर्धारण उचित नहीं है। अतः उक्त प्रावधान के अनुसार चीन में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए किसी अन्य देश से कीमत को अपनाया नहीं जा सकता है। अतः प्राधिकारी ऊपर उल्लिखित नियमावली में प्रदत्त तीसरे विकल्प के अनुसार चीन में उत्पाद का सामान्य मूल्य निर्धारित करना उचित मानते हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी ने उत्पाद के प्रत्येक प्रकार के सामान्य मूल्य का परिकलन भारत में उत्पादन लागत जमा उसकी संगत प्रक्रिया के अनुसार एक तर्कसंगत लाभ पर विचार करते हुए किया है।

43. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अलग-अलग क्लेम्पिंग बलों वाली मशीनों की संबद्ध लागतें और कीमतें क्लेम्पिंग बल और उत्पाद विवरण के अनुसार भिन्न-भिन्न होती हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार/आकार तथा प्रयोग से सिद्ध नहीं करते हैं कि वे समान उत्पाद नहीं हैं। जॉच अवधि के दौरान भारत में केवल विभिन्न क्लेम्पिंग बल वाले नीचे उल्लिखित उत्पाद प्रकारों/मशीनों का आयात किया गया है। अतः समान आधार पर उचित तुलना के लिए सामान्य मूल्यों का इन उत्पाद प्रकारों के लिए निर्धारण किया गया है। जहां भी घरेलू उद्योग समान क्लेम्पिंग बल वाले समान उत्पाद प्रकार का उत्पादन नहीं करता है वहां निकटतम कम क्लेम्पिंग बल वाली मशीन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य को निर्धारित करने की एक सर्वक नीति अपनाई गई है ताकि कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने वाले किसी अंतर के लिए पर्याप्त स्थान रखकर समान स्तर की तुलना की जा सके।

44. तदनुसार, चीन से जॉच अवधि के दौरान आयातित प्रत्येक उत्पाद प्रकार के लिए परिकलित सामान्य मूल्य निम्नानुसार जात करने का प्रस्ताव है:

उत्पाद प्रकार/क्लेम्पिंग बल (टन)	परिकलित सामान्य मूल्य (सीएनवी) रूपये प्रति नग	परिकलित सामान्य मूल्य सीएनवी (अम.डा./नग)
120	****	****
125	****	****
128	****	****
150	****	****
380	****	****

च. 4 निर्यात कीमत

45. चूंकि संबद्ध देश के किसी निर्यातक ने ऐसी कोई सूचना प्रदान नहीं की है जिसका उपयोग निर्यात कीमत की गणना में किया जा सके इसलिए प्राधिकारी डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार भारत में आयात की सीआईएफ कीमत के आधार पर संबद्ध देश से सभी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं। इस संबंध में प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षों के इन तर्कों के नोट किया कि विचाराधीन उत्पाद की उचित ढंग से पहचान की जानी चाहिए। डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों की सावधानीपूर्वक जॉच की गई है और केवल वही मशीनें जो विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा के भीतर आती हैं, पाटन मार्जिन और अन्य निर्धारणों के लिए ध्यान में ली गई हैं।

46. तदनुसार, कारखाना-द्वार कीमत जात करने के लिए संबद्ध देश में संबंधित निर्यातकों से किसी ठोस सूचना के अभाव में सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार निर्यात कीमत का समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पततन व्ययों, कमीशन, अंतरदेशीय परिवहन और बैंक प्रभार के लिए लागू समायोजनों के साथ डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों से तुलनीय क्लेम्पिंग बलों के साथ उत्पाद प्रकारों की सीआईएफ कीमत के आधार पर चीन जन. गण. से निर्यातकीमत परिकलितकरने का प्रस्ताव निम्नानुसार है:

उत्पाद प्रकार/क्लेम्पिंग बल (टन)	संख्या	निर्यात कीमत (रूपये) प्रति मशीन	निर्यात कीमत (अम.डा.) प्रति मशीन
120	8	****	****
125	1	****	****
128	2	****	****
150	1	****	****
380	1	****	****
कुल/भारित औसत	13	****	****

च. 5 पाटन मार्जिन

47. समग्र रूप से इस उत्पाद के लिए पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ उत्पाद किस्म स्तर पर पहले पाटन मार्जिनों को अलग-अलग उत्पाद प्रकारों के लिए यथोक्त परिकलित कारखाना-द्वार सामान्य मूल्य की व्यापार के उसी स्तर पर कारखाना-द्वार निर्यात कीमत के साथ तुलना करके ज्ञात किया गया है। तत्पश्चात, उत्पाद के लिए समग्र रूप से भारित औसत पाटन मार्जिन निम्नानुसार बनता है:

उत्पाद प्रकार/क्लेम्पिंग बल (टन)	नगों की संख्या	परिकलित सामान्य मूल्य (अम.डा./मशीन)	कारखाना-द्वार निर्यात कीमत अम.डा./मशीन	पाटन मार्जिन अम.डा./मशीन	पाटन मार्जिन %
120	8	****	****	****	****
125	1	****	****	****	****
128	2	****	****	****	****
150	1	****	****	****	****
380	1	****	****	****	****
कुल/भारित औसत	13	****	****	****	55-65 प्रतिशत

48. उक्त आकलन से पता चलता है कि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं का भारत में पाटित कीमतों पर प्रवेश करना जारी है और पाटन का मार्जिन काफी अधिक है।

49. प्राधिकारी संबद्ध वस्तु के पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का निम्नानुसार आकलन करने का प्रस्ताव करते हैं:

च. पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

50. यह निर्धारित करने के बाद कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पाटित कीमतों पर निर्यात किया जा रहा है प्राधिकारी ने शुल्क हटाये जाने पर पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जाँच की है।

च.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

51. घरेलू उद्योग ने अपने विभिन्न अनुरोधों में अन्य वातांके साथ-साथ यह तर्क दिया है कि

- क) कि समाचार रिपोर्टों के अनुसार, चीन में इन मशीनों के एक अग्रणी उत्पादक और निर्यातिक हैसियन इंटरनेशनल ग्रुप, चीन ने हाल में रिकार्ड इंजेक्शन मालिंग मशीनों की आपूर्ति की है। 2012 में हैसियन ने लगभग 22,000 मशीनों की आपूर्ति की है। लगभग 32.2 प्रतिशत बिक्रियां 130 से अधिक देशों को निर्यात के लिए थीं।
- ख) कि प्लास्टिक्स प्रसंस्करण मशीनरी के लिए वैश्विक मांग के वार्षिक रूप से 6.0 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है जो 2015 में 28.9 बिलियन तक पंडुच जाएगी, जबकि 2005 से 2010 में गिरावट की प्रवृत्ति रही थी। इस पूर्वानुमान के अनुसार चीन का 2015 तक समस्त अतिरिक्त वैश्विक मांग के 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा होने का अनुमान है क्योंकि विकासशील देशों से लाभ प्लास्टिक्स प्रसंस्करण उपकरण बाजार की बुद्धि की चालक शक्ति बन जाएगा।
- ग) यह कि हैसियन ने चीन में लागू पाटनरोधी शुल्क से बचने के लिए वियतनाम में संयोजन संबंधी सुविधाओं को स्थापित किया है और अब वह वियतनाम द्वारा लागू किए जाने वाले संभावित पाटनरोधी शुल्क से बचने के लिए भारत में संयोजन संबंधी प्रचालन स्थापित करना चाहता है।
- घ) कि यदि चीन के उत्पादकों के पास कोई आधिक्य क्षमताएं नहीं होती तो उनके उत्पादक भारत में संयोजन संबंधी प्रचालन शुरू नहीं करते और न ही एसोसिएशन या दूतावास ने वर्तमान कार्यवाही में प्रतिवाद ही किया होता।
- इ) कि चीन की एसोसिएशन, ने सुनवाई के समय यह बताया था कि चीन का उत्पादन लगभग 30000 मशीनें हैं और घरेलू खपत लगभग 25000 है। यह बिल्कुल भी संभव नहीं है जब हाल की अवधि में एक ही कंपनी का उत्पादन 30000 मशीनें हैं। स्पष्ट रूप से, एसोसिएशन ने सुनवाई के दौरान गुमराह करने वाला विवरण दिया था।

- च) कि चीन विचाराधीन उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक और नियर्यातिक है और चीन में उत्पादकों के पास भारी आधिक्य उत्पादन क्षमताएं हैं और चीन के उत्पादक काफी नियर्यातोन्मुखी हैं।
- छ) कि चीन की सरकार और एसोसिएशन ने दावा किया कि चीन में कोई आधिक्य क्षमता नहीं है और चीन और तीसरे देश में वर्तमान मांग उद्योग की वर्तमान क्षमताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। यदि यह सच है तो चीन के उत्पादक भारत में संयोजन संबंधी प्रचालन नहीं करते और न तो एसोसिएशन और न ही दूतावास ने वर्तमान कार्यवाही का विरोध किया होता। स्पष्ट रूप से जाँच का प्रतिवाद केवल भारतीय बाजार में पाठन को तेज करने के लिए ही किया जा रहा है।
- ज) कि संबद्ध वस्तु के एक सबसे बड़े उत्पादक के रूप में चीन की स्थिति के साथ संबद्ध वस्तु के एक लाभकारी, तेजी से बढ़ते हुए बाजार के रूप में भारत की स्थिति चीन से भारत में पाठन में वृद्धि होने के लिए स्थिति को बिलकुल अनुकूल बना देती है।
- झ) यह कि एंगल द्वारा परिकलित चीन की मांग इस संघ द्वारा दावा की गई मांग से बिलकुल अलग रूप में है। यह स्पष्ट से यह दर्शाता है कि पक्षकार इस प्राधिकारी के समक्ष सत्यापन योग्य तथ्यों को नहीं ला रहे हैं और भ्रामक सूचना दे रहे हैं।
- ञ) यह कि एक ओर एंगल और इस संघ ने दावा किया है कि चीन से कोई आयात नहीं हुआ है। दूसरी ओर एंगल ने दावा किया है कि इसके मूल्य की सूची वही है जो भारत और चीन के लिए है। यह तर्क स्पष्ट रूप से विरोधाभासी है।
- ट) यह कि पूर्व की जाँच और वर्तमान याचिका में निर्धारित की गई पाठन मार्जिन बहुत अधिक है और यह स्पष्ट रूप से पाठन रोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में पाठन के जारी रहने की संभावना को दर्शाता है।

52. चीन की सरकार और सीपीएमआईए के दावों पर प्रश्न उठाते हुए कि चीन में कोई आधिक्य क्षमता उपलब्ध नहीं है और चीन और तीसरे देशों में वर्तमान मांग उद्योग की वर्तमान क्षमताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, घरेलू उद्योग ने पहले प्रकटन संबंधी अपनी टिप्पणियों में तर्क दिया है कि यदि यह चीन की सरकार का मामला होता तो एसोसिएशन ने इस कार्यवाही का विरोध नहीं किया होता और चीन से उत्पादकों ने भारत में संयोजन लाइन की स्थापना नहीं की होती। इस जाँच का विरोध पाठन के तेज होने के कारण किया जा रहा है।

53. घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया है कि यद्यपि एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने सुनवाई के समय निर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचित किया कि चीन में पीयूसी का उत्पादन लगभग 30000 मरीनें हैं और घरेलू खपत एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के मुकाबले लगभग 25000 मरीनें हैं जो चीन में पीयूसी की उत्पादन 78,998 और क्षमता 86000 बताई गई है। प्राधिकारी को प्रदत्त सूचना जो याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध नहीं कराई गई की तुलना में सार्वजनिक सुनवाई के दौरान, जहां याचिकाकर्ता उपस्थित थे, में ऐसा भारी भटकाव याचिकाकर्ताओं और निर्दिष्ट प्राधिकारी को गुमराह करने की एसोसिएशन की मंशा को उजागर करता है। अतः प्राधिकारी को ऐसी सूचना को नहीं मानना चाहिए और एसोसिएशन को असहयोगी मानना चाहिए।

54. घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया है कि एसोसिएशन द्वारा प्रदत्त सूचना से यह देखा जाएगा कि चीन में आधिक्य क्षमताएं मौजूद हैं और चीन में मांग कुल उपलब्ध क्षमताओं का केवल 80 प्रतिशत है। भारत में मांग केवल 2760 होने के कारण चीन भारत में पूरी मांग को आसानी से पूरा कर सकता है और इसी के साथ अन्य देशों को नियर्यात कर सकता है। पाठनरोधी शुल्क को हटाने पर उत्पादकों और नियर्यातकों के उनकी आधिक्य क्षमता का भारत को नियर्यात में उपयोग करने की संभावना अथवा उसके बार बार न होने को दर्शने के लिए दी है।

छ. 2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण

55. सी पी एम आई ए ने अपनी आम सुनवाई के बाद के अनुरोध में उनके पास सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के रूप में निम्नलिखित सूचना वर्तमान शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में पाठन और हानि की संभावना अथवा उसके बार बार न होने को दर्शने के लिए दी है।

क्र. सं.	विवरण	पी ओ आई वार्षिक रूप में	पी ओ आई (15 माह में)
1	चीन में इस उत्पाद की मांग	मात्रा संख्या में	मात्रा संख्या में
	सी पी एम आई ए के सदस्यों द्वारा घरेलू विक्री	****	****
	सी पी एम आई ए के गैर सदस्यों द्वारा घरेलू विक्री (अनुमानित)	****	****
	अन्य देशों से चीन में आयात (अनुमानित)	****	****
	कुल	68,310	85,388

2	चीन में इस उत्पाद की क्षमता		
	सी पी एम आई ए के सदस्यों की क्षमता	****	****
	सी पी एम आई ए के गैर सदस्यों की क्षमता (अनुमानित)	****	****
	कुल	86,000	1,07,500
3	चीन में इस उत्पाद का उत्पादन		
	सी पी एम आई ए के सदस्यों द्वारा उत्पादन	****	****
	सी पी एम आई ए के गैर सदस्यों द्वारा उत्पादन (अनुमानित)	****	****
	कुल	78,998	98,747
4	पी ओ आई के दौरान भारत में निर्यात		
	सी पी एम आई ए के सदस्यों द्वारा निर्यात	शून्य	शून्य
	सी पी एम आई ए के गैर सदस्यों निर्यात	शून्य	शून्य
5	पी ओ आई के दौरान अन्य देशों में निर्यात		
	सी पी एम आई ए के सदस्यों द्वारा निर्यात	****	****
	सी पी एम आई ए के गैर सदस्यों द्वारा निर्यात	****	****
	कुल	12,598	15,748
6	तीसरे देशों को निर्यात का मूल्य		
	सी पी एम आई ए के सदस्यों के अनुसार निर्यात मूल्य अमरीकी डॉलर	****	****
	सी पी एम आई ए के सदस्यों के अनुसार औसत निर्यात मूल्य प्रति मशीन अमरीकी डॉलर (एफ ओ बी चीन जन गण)	****	****
7	क्षमता का उपयोग	92%	92%

56. सी पी एम आई ए ने तर्क दिया है कि उपर्युक्त आंकड़े दर्शते हैं कि चीन जन गण में कोई अधिक क्षमता नहीं है। यह उद्योग पहले से ही उपर्युक्त आदर्शतम स्तर पर कार्य कर रहा है और यह भी कि चीन की समग्र घरेलू मांग केवल चीन के उत्पादकों द्वारा पूरी नहीं की जाती है। चीन में उसी उत्पाद का आयात होता है। वर्तमान स्तर से अधिक क्षमता के उपयोग को बढ़ाने की संभावनाओं का कोई दावा चालाकी भरे तर्क से कम नहीं है। महत्वपूर्ण रूप से तीसरे देशों को पेशकश किए गए मूल्य भारत में अवतरित स्तरों पर घरेलू उद्योग के अहानिकर मूल्य और निवल विक्री प्राप्ति से बहुत अधिक होंगे। ऐसा कोई कारण नहीं है कि जो चीन के उत्पादकों को अपना सामान उस मूल्य पर बेचने के लिए मजबूर करे जो अन्य देशों में उन्हें मिल रहे मूल्य से कम हो।

57. सीपीएमआईए ने यह भी तर्क दिया है कि उपर्युक्त आंकड़े तीसरे देशों को कम मूल्य पर निर्यात जिसे पाटन रोधी शुल्क को रद्द करने की स्थिति में भारत में भेजा जा सकता है अथवा कोई अतिरिक्त या अधिक क्षमता के अभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। जब इसे घरेलू उद्योग की मजबूत स्थिति के साथ देखा जाता है तब यह वर्तमान मामले में पाटन और हानि की संभावना अथवा उसके बार बार होने की न्यूनतम संभावना को भी दरकिनार करता है।

58. प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए पहले प्रकटन विवरण के उत्तर में सीपीएमआईए ने अपने इस तर्क को दोहराया है कि चीन के उत्पादक ईंटतम स्तर से ऊपर काम कर रहे हैं और तीसरे देशों में उन्हें उच्चतर कीमतें मिल रही हैं। चूंकि याचिकाकर्ता के स्वयं के आंकड़ों में ही भारत में घरेलू मांग में गिरावट प्रदर्शित होती है इसलिए चीन के निर्यातकों के लिए इसका लाभकारी होना कल्पना से परे है।

च. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

59. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि चीन से आयात की मात्रा जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक कम हो गई है और पी ओ आई के दौरान आयात की मात्रा कम है किर भी अनुमानित पाटन मार्जिन आयात के अंकड़ों के आधार पर बहुत अधिक है। इसलिए, प्राधिकारी ने अपने पास उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखकर तथा घरेलू उद्योग एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों के उपर्युक्त अनुरोधों के अनुसार संबद्ध वस्तुओं के पाटन के जारी रहने की संभावनाओं की जांच की है।

60. प्राधिकारी सी पी एम आई ए और घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुत किए गए अनुरोधों को नोट करते हैं। सी पी एम आई ए ने अपने सदस्यों और गैर सदस्यों के अनुमानित अंकड़ों के डाटा के आधार पर चीन में प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनों की उत्पादन क्षमताओं, उत्पादन मात्रा और मांग के बारे में कुछ सूचना दी है। लेकिन इन अंकड़ों के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं है और न ही विभिन्न क्षमताओं का कोई व्यौरा दिया गया है, जिससे इस बात की जांच की जा सके कि क्या ये आंकड़े इस जांच में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित हैं अथवा नहीं। हालांकि, ये सकल आंकड़े भी दर्शति हैं कि चीन की क्षमता सी पी एम आई ए द्वारा दर्शायी गई घरेलू मांग से लगभग 36 प्रतिशत अधिक है और कुल उत्पादन का लगभग 16 प्रतिशत निर्यात किया जा रहा है। लगभग 10 प्रतिशत अतिरिक्त क्षमताएं भी हैं यद्यपि संघ ने दावा किया है कि उद्योग अपने आदर्शतम स्तर पर कार्य कर रहा है। इसलिए निर्यात करने की क्षमता की उपलब्धता और क्षमता उन्मुखीकरण इस संघ द्वारा दिए गए अंकड़ों में भी दिखता है। इसके अलावा, मैसर्स हैटन के संबंध में आंकड़े, जो चीन में इन मशीनों का प्रमुख उत्पादक और निर्यातों में से एक हैं और जो सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है, दर्शता है कि इस समूह में पिछले वर्ष के 22,000 के आंकड़ों से बहुत 2013 में लगभग 27,000 मशीनें भेजी हैं और उनका निर्यात 25 प्रतिशत से अधिक हो गया है। यह चीन के उत्पादकों की निर्यात गहनता को दर्शता है।

61. इसके अलावा इस संघ द्वारा दर्शाये गए भारत को भावी मूल्य के संकेत के रूप में तीसरे देशों को निर्यात का मूल्य स्तर स्तर पर है। जांच के अधीन उत्पाद में व्यापक मूल्य अंतर के साथ क्षमताओं की एक व्यापक श्रेणी है। इसलिए इस संघ द्वारा सकल स्तर पर दिए गए मूल्य के स्तर के संबंध में सूचना भारत में इन सामानों के निर्यात का संभावित मूल्य परिदृश्य को सार्वक रूप से समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस प्राधिकारी द्वारा विश्लेषण किए गए आयात के आंकड़े दर्शते हैं कि अलग अलग आकारों की कुछ मशीनों का आयात चीन से भारत में पी ओ आई के दौरान किया गया है और आयात के आंकड़ों के अनुसार मूल्य यह दर्शते हैं कि ये सामान भारतीय बाजार में अपेक्षाकृत बहुत कम मूल्य पर प्रवेश कर रहे हैं और यह पाया गया था कि निर्यात को पाटित मूल्य पर किया गया है। इसलिए उचित संकेत यह है कि यदि शुल्कों को हटा दिया जाए तब चीन के उत्पादक भारतीय बाजार में सामान्य मूल्य स्तर पर और अधिक मशीनों का निर्यात कर पाएंगे। इसके अलावा, इस प्राधिकारी द्वारा जांच किए गए पी ओ आई के बाद के आयात आंकड़े दर्शते हैं कि उस अवधि में आयात में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद प्राधिकारी का यह मत है कि यदि शुल्कों को हटा दिया जाता है तब पाटन के जारी रहने अथवा उसके बार बार होने की संभावना है।

ज. हानि का निर्धारण और कारणात्मक संबंध; और घरेलू उद्योग को हानि के जारी रहने अथवा उसके बार बार रहने की संभावना

ज. 1 कानूनी स्थिति

62. जैसा कि पूर्व के भाग में उल्लेख किया गया है, एक निर्णयिक समीक्षा जांच में हानि की जांच के संबंध में प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह निम्नलिखित की जांच करे :

- क्या घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण हानि होना जारी है यदि हां तो क्या शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को हानि होते रहने की संभावना है, अथवा
- उन मामलों में जहां घरेलू उद्योग को लगातार हानि नहीं हुई है, क्या पाटन रोधी शुल्कों को हटाये जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को हानि फिर से होने की संभावना है।

63. इसलिए यह प्रस्ताव है कि सबसे पहले इस जांच की ओर बढ़ा जाये कि क्या घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण बहुत अधिक हानि होते रहने की संभावना है। उसके बाद संबद्ध देश से शुल्कों के हटाये जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को हानि के जारी रहने अथवा उसके बार बार होने की संभावना की जांच की गई है। घरेलू उद्योग को पर्याप्त हानि होने की जांच उसी तरीके से की जा रही है, जैसा कि पाटन रोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध- ॥ और पाटन रोधी करार के अनुच्छेद 3 में दिया गया है।

ज. 2 घरेलू उद्योग को वर्तमान हानि और कारणात्मक संबंध की जांच

ज. 2 .1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

64. हानि और कारणात्मक संबंध के बारे में अपने विभिन्न अनुरोधों में घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ साथ यह अनुरोध किया है :

- i. कि समीक्षा जांच का समग्र उद्देश्य यह देखने के लिए नहीं है कि क्या पाटन रोधी शुल्क लगाये जाने की कोई आवश्यकता है बल्कि यह देखने के लिए है कि क्या पाटन रोधी शुल्क के जारी रहने के अभाव में यह जारी रहेगी और घरेलू उद्योग को हानि होगी।
- ii. कि चीन, मलेशिया, फिलीपींस, ताईवान और वियतनाम से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटन रोधी शुल्क लगाने के बाद भारत में विचाराधीन उत्पाद का पाटन शुरू हुआ है। घरेलू उद्योग ने इन देशों से आयातों पर पाटन रोधी शुल्कों के लगाये जाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी इस समय यह जांच कर रहे हैं यद्यपि जांच के अधीन अन्य याचिका में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में अपेक्षाकृत बहुत अधिक टन की मशीनें भी शामिल हैं।
- iii. यह कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है। ऑटो क्षेत्र के विकास में भी लगभग 16 प्रतिशत की गिरावट आई है जिसके कारण इस क्षेत्र में प्रयोग की गई मशीनें निष्क्रिय हो गई हैं। इसके फलस्वरूप इन मशीनों का उपयोग पैकेजिंग और अन्य क्षेत्रों के लिए किया जा रहा है। इस प्रकार से जबकि ऑटो क्षेत्र में मांग में गिरावट के फलस्वरूप इस क्षेत्र में मांग में कमी आई है साथ ही इसने अन्य क्षेत्रों में भी मांग में कमी पैदा की है।
- iv. वर्तमान अवधि के दौरान आयात की कम मात्रा (क) एक ओर पाटन रोधी शुल्क लगाये जाने और (ख) अन्य देशों में सुविधाएं स्थापित कर अन्य देशों से निर्यात करते की चीन की प्रमुख उत्पादकों की क्षमता के कारण है।
- v. यह कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में चीन जन गण से तथा भारतीय बाजार में अन्य देशों से पाटित आयातों की सतत मौजूदगी के कारण पाटन रोधी शुल्क के बने रहने के बावजूद सुधार नहीं हुआ है।
- vi. यह कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2011-12 और उसके बाद 2012-13 में इन अनुमानों को ध्यान में रखकर बाजार में विकास की प्रत्याशा में अपनी क्षमताओं में भी वृद्धि की है तथापि दुर्भाग्यवश इन उपभोक्ताओं द्वारा उत्पादन किए जा रहे उत्पादों की मांग में बहुत अधिक कमी देखी गयी है, जिसके फलस्वरूप विचाराधीन उत्पाद की मांग में पिछले 4 वर्षों में बहुत अधिक गिरावट आई है।
- vii. यह कि भारतीय बाजार में पाटित आयातों की सतत मौजूदगी से घरेलू उद्योग इस बाजार में बने रहने के उद्देश्य से, उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं रह गया था सिवाय इसके कि वह आदर्शतम सूल्य से कम पर अपने सामान को बेचें। घरेलू उद्योग को लागत में वृद्धि के अनुपात में अपने मूल्य बढ़ाने से रोका गया था।
- viii. यह कि आयात से घरेलू उद्योग के मूल्य में बहुत अधिक कटौती हो रही थी। उसके अलावा आयात से घरेलू मूल्य स्थिर हो रहा था।
- ix. यह कि घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन उत्पादन, घरेलू विक्री, क्षमता का उपयोग, लाभ, निवेश पर आय, नकदी के प्रवाह के संबंध में बेहतर हो गई। घरेलू उद्योग पर पाटन का परिणामी प्रभाव बहुत अधिक प्रतिकूल हो गया है।
- x. यह कि घरेलू उद्योग को संबंधित अवधि के दौरान हानि हुई है। केवल यह बात कि वर्तमान अवधि में घरेलू उद्योग को हानि अन्य देशों से पाटित आयातों के कारण हुई है, का यह अर्थ नहीं होता है कि चीन से घरेलू उद्योग को हानि पाटन रोधी शुल्क के हटाये जाने की स्थिति में नहीं होगी।
- xi. यह कि चीन से आयात वर्तमान में जांच के अधीन देशों से तथा तीसरे देशों से आयात मूल्य की तुलना में कम मूल्य पर हुई है। यह स्पष्ट रूप से इस बात को प्रमाणित करता है कि घरेलू उद्योग को पाटन रोधी शुल्कों के हटाये जाने की स्थिति में बहुत अधिक गहन हानि होगी।
- xii. यह कि विचाराधीन उत्पाद एक पूंजीगत उत्पाद मद है और इसलिए घरेलू उद्योग से यह अपेक्षित है कि वह अपनी क्षमता के विस्तार की योजना भावी संभावना को ध्यान में रखकर करे। उस समय सभी भावी अनुमान बहुत अच्छे और आशाओं से पूर्ण लग रहे थे तथापि, इस उत्पाद की मांग में बहुत अधिक गिरावट आई है और इसलिए घरेलू उद्योग को अब अन्य शुल्कों से पाटन तथा मांग में कमी दोनों से नुकसान हो रहा है।
- xiii. यह कि यदि किसी खास प्रकार की मांग नहीं है तब यह हो सकता है कि घरेलू उद्योग उस उत्पाद का उत्पादन नहीं करेगा। यदि भविष्य में किसी देश में उत्पाद की मांग हो, तब घरेलू उद्योग उसे अनुपातिक रूप से पूरा करेगा।

ज. 2 .2 उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों एवं हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध

65. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अपने अनुरोध में तर्क दिए हैं :

 - i. कि कोई हानि अथवा सतत हानि घरेलू उद्योग को चीन जन गण से कथित पाटित आयातों के कारण नहीं हुई है।

- ii. कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या चीन जन गण से पी ओ आई के दौरान सतत आयात हुआ है और उससे घरेलू उद्योग को कोई हानि हुई है। याचिका में दी गई सूचना के अनुसार आयात में वर्तमान पी ओ आई में 949 से घटकर 42 मशीनें हो गई हैं। यद्यपि, संबद्ध उत्पाद की मांग में मूल मामले की पी ओ आई की तुलना में वर्तमान पी ओ आई के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई है, आधार वर्ष तथा 2010-11 की तुलना में मांग 3634 से घटकर 2794 मशीनें हो गई हैं। मांग में यह गिरावट लगभग 23 प्रतिशत है।
- iii. कि घरेलू उद्योग की क्षमता मूल मामले की पी ओ आई की तुलना में वर्तमान पी ओ आई के दौरान बढ़कर 647 प्रतिशत हो गई और आधार वर्ष 2010-11 की तुलना में 34 प्रतिशत तक बढ़ी है जबकि मांग में लगभग 23 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग का उत्पादन वर्तमान पी ओ आई के दौरान घटकर 12 प्रतिशत हो गया है। घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग संयंत्र की क्षमता में भारी वृद्धि के कारण पी ओ आई के दौरान कम हो गई है।
- iv. कि वर्तमान पी ओ आई के दौरान घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की विक्री की मात्रा में मूल मामले के पी ओ आई की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। लेकिन आधार वर्ष 2010-11 की तुलना में इसमें 18 प्रतिशत तक गिरावट आई थी। हालांकि, इसी अवधि के दौरान मांग में 23 प्रतिशत तक गिरावट आई थी। इसलिए कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को सतत हानि नहीं हुई है।
- v. कि इस याचिका के अनुसार घरेलू उद्योग की निवल विक्री प्राप्ति अहानिकर मूल्य से अधिक रही है इसलिए घरेलू उद्योग को अपने निजी दावे के अनुसार कोई सतत पर्याप्त हानि नहीं हुई है।
- vi. कि इस याचिका में उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन ने गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाया जबकि चीन जन गण से कथित आयात बहुत मामूली अथवा नगण्य थे और चीन के आयात पर 174 प्रतिशत तक पाटन रोधी शुल्क लग रहा है। तीसरे देश का आयात मूल्य भी (जैसे वियतनाम और ताईवान जैसे प्रमुख देश) घरेलू उद्योग द्वारा पेशकश किये गये मूल्य की तुलना में बहुत अधिक था। यदि घरेलू उद्योग को तब भी पर्याप्त हानि हो रही थी तो उसका कारण भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयात के अलावा कोई अन्य हो सकता है। इस प्रकार से भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयात और घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन के बीच कोई संबंध नहीं है।
- vii. कि हानि यदि कोई हो अन्य कारणों जैसे मांग में गिरावट, याचिकाकर्ता के पास भारतीय मांग को देखते हुए बहुत अधिक क्षमता आदि हो सकती है और चीन जन गण से आयात के अन्य कारणों से हानि अथवा संभावित हानि का कारण बताने के लिए किए जा रहे किसी प्रयास को इस प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जाना चाहिए।
- viii. कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को हानि और पाटन मार्जिन निर्धारित करने के उद्देश्य से प्रकार-वार तुलना करनी चाहिए।

66. प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए पहले प्रकटन विवरण की उनकी टिप्पणियों में सीपीएमआईए ने तर्क दिया है कि घरेलू कीमतें याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई पीयूसी की पहुच कीमत से अप्रभावित है जैसा कि प्रकटन विवरण से स्पष्ट है। यह भी तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में इन वर्षों के दौरान काफी वृद्धि हुई है यद्यपि उत्पाद की मांग में कुछ गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की विक्री कीमत प्रकटन विवरण के अनुसार क्षतिरहित कीमत से अधिक थी जो सिद्ध करता है कि घरेलू उद्योग को कोई कीमत संबंधी क्षति नहीं हुई है।

ज. 2 .3 प्राधिकारी द्वारा जांच

67. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों के आरोप में यह प्राधिकारी संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण हानि की संभावना के पहलुओं की जांच करने की कार्रवाई शुरू करने के पूर्व घरेलू उद्योग को वर्तमान हानि, यदि कोई हो, कि जांच करने की कार्रवाई करते हैं।

68. अनुबंध-II के असाथ पठित पाटन रोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि हानि के निर्धारण में “.... समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में पाटित आयातों की मात्रा, मूल्यों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संबंधित तथ्यों पर विचार करने के बाद” उन कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को हानि का संकेत देते हैं। मूल्यों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करने में यह आवश्यक माना गया है कि इस बात की जांच की जायेगी क्या भारत में समान वस्तु के मूल्य की तुलना में पाटित आयातों द्वारा बहुत अधिक मूल्य में कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों का प्रभाव अन्य प्रकार से बहुत अधिक मात्रा में मूल्यों पर दबाव डालेगा अथवा मूल्यवृद्धि को रोकेगा जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक है तक हुआ होता।

69. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, प्राधिकारी उपर्युक्त नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार उन सूचकांकों पर विचार करते हैं जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो, जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, विक्री की मात्रा, भंडार, लाभप्रदता, निवल विक्री प्राप्ति, पाटन का आकार एवं मार्जिन आदि।

70. वर्तमान हानि विश्लेषण के उद्देश्य से प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की मात्रा और मूल्य प्रभाव तथा मूल्यों और लाभप्रदता पर इसका प्रभाव पाठन और हानि, यदि कोई हो, के बीच कारणात्मक संबंध और हानि की मौजूदगी की जांच करने के लिए जांच की है।

71. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं पर वर्तमान में संबद्ध देश से पाठन रोधी शुल्क लग रहा है और पाठन रोधी जांच मलेशिया, फ़िलीपींस, ताईवान और वियतनाम से एक व्यापक क्षमता रेंज के साथ प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनों के कथित पाठन के लिए शुरू की गई है। इसलिए प्राधिकारी ने संबद्ध देश के संबंध में पाठन रोधी शुल्क को वापस लिए जाने पर संभावित परिवृद्धि सहित हानि का निर्धारण और कारणात्मक संबंध के लिए अन्य स्रोतों के साथ संबद्ध देश से आयातों की मात्रा और मूल्य के प्रभाव पर विचार किया है। तदनुसार, पाटित आयातों की मात्रा और मूल्य के प्रभाव की जांच नीचे दिए गए अनुसार वर्तमान प्रभाव का आकलन करने के लिए किया गया है:

क) पाटित आयातों के मात्रा का प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

i. संबद्ध देश के आयात की मात्रा और हिस्सा

72. प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों को नोट करते हैं कि पी ओ आई के दौरान चीन से संबद्ध वस्तुओं का कोई नियंत नहीं हुआ है। विभिन्न स्रोतों से आयातों की मात्रा और मूल्य की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से लेन देन-वार आंकड़ों पर विश्वास किया है और विचाराधीन उत्पाद की पहचान करने के लिए उत्पाद विवरण के आधार पर अलग अलग लेन देन की जांच की गई है। इस जांच के अनुसार हानि की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के लिए सारांश में आयात आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	पी ओ आई (अक्टूबर 12- दिसं. 13)	पी ओ आई (वार्षिक रूप में)	आयात में हिस्सा (पी ओ आई) %	जन. - जून 14 (पी ओ आई के बाद) वार्षिक रूप में
संबद्ध देश चीन जन गण	सं.	73	23	26	13	10	1.06%	40
जांच के अधीन देश	सं.	194	315	374	488	390	39.97%	368
मलेशिया	सं.	102	87	107	134	107	10.97%	122
थाईलैंड	सं.	19	0	0	11	9	0.90%	2
वियतनाम	सं.	0	77	226	248	198	20.31%	174
फ़िलीपींस	सं.	73	151	41	95	76	7.78%	70
अन्य देश	सं.	1235	1090	637	716	573	58.97%	482
कुल आयात	सं.	1502	1428	1037	1,217	974	100.00%	890

73. उपर्युक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, पी ओ आई सहित हानि की जांच की अवधि के दौरान चीन से संबद्ध वस्तुओं का आयात हुआ है यद्यपि, संछया में कमी आई है। हालांकि, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और फ़िलीपींस इसके विरुद्ध अलग पाठन रोधी जांच चल रही है, से उसी अवधि के दौरान बहुत अधिक आयात हुआ है। कुल मिलाकर ये आयात कुल आयात का लगभग 41 प्रतिशत होता है।

ii. मांग एवं बाजार हिस्सा

74. घरेलू उद्योग और भारत में संबद्ध वस्तुओं में संबद्ध देश की मांग और बाजार हिस्से का आकलन घरेलू उद्योग की उत्पादन और वृद्धि तथा आयात को ध्यान में रखकर किया गया है।

मांग	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	पी ओ बाई (अक्टूबर 12- दिसं. 13)	पी ओ बाई (वार्षिक रूप में)	जन.-जून 14 (पी ओ बाई के बाद) वार्षिक रूप में
घरेलू उद्योग की विक्री	सं.	1,990	1,940	1,737	2,026	1,621	1934
	प्रवृत्ति	100	97	87		81	97
अन्य भारतीय उत्पादकों की विक्री	सं.	199	194	174	203	162	193
	प्रवृत्ति	100	97	87		81	97
संबद्ध देश	सं.	73	23	26	13	10	40
	प्रवृत्ति	100	32	36		14	55
जांच के अधीन देश	सं.	194	315	374	488	390	368
	प्रवृत्ति	100	162	A92	251	201	190
अन्य देश	सं.	1235	1090	637	716	573	482
	प्रवृत्ति	100	88	52	58	46	39
कुल मांग/ खपत	सं.	3,691	3,562	2,948	3,446	2,757	3,017
	प्रवृत्ति	100	97	80		75	82

75. उपर्युक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग की मांग और विक्री 2012-13 से कम होनी शुरू हो गई थी और मांग में आधार वर्ष की तुलना में पी ओ आई में लगभग 25 प्रतिशत की गिरावट आई है। संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद की आयात की मात्रा भी कुछ वर्षों में कम हुई है। हालांकि, 2011-12 में संबद्ध देश से आयात में अचानक गिरावट हुई है और स्पष्ट रूप से पाठन रोधी शुल्क के प्रभाव के कारण हुई है क्योंकि अन्य स्रोतों से आयात की प्रवृत्ति उस वर्ष में कोई बड़ी गिरावट को नहीं दर्शाती। घरेलू उद्योग की विक्री में गिरावट हुई है तथा आधार वर्ष की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत तक अन्य घरेलू उत्पादकों की विक्री में गिरावट हुई है जो मांग में गिरावट के प्रभाव के कारण प्रतीत होती है।

76. जहां तक मांग के परिदृश्य का प्रश्न है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग सामान्य आर्थिक मंदी से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है और विशिष्ट रूप से पिछले कुछ वर्षों के दौरान उद्योग क्षेत्र के अँटो संघटक में मांग में कमी के कारण हुई है, जो इन मशीनों का एक बहुत बड़ा प्रयोग करता है। हालांकि, यह एक वैश्विक घटना है अतः प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीन उद्योग हर जगह दबाव में है और इस कारण से इन क्षमताओं का उपयोग करने के लिए अनेक स्रोतों से पाठन शुरू हुआ है। मांग का एक बहुत बड़ा भाग का स्थान संबद्ध देश सहित अनेक स्रोतों से पाठित आयातों द्वारा लिया गया है।

77. मांग में सामान्य प्रवृत्तियों की जांच घरेलू बाजार में अनेक कम्पनियों के बाजार हिस्से में प्रवृत्ति के साथ साथ किया गया है।

बाजार हिस्सा	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	पी ओ बाई (वार्षिक रूप में)	जन. - जून 14 (पी ओ बाई के बाद) (वार्षिक रूप में)
घरेलू उद्योग की विक्री	%	54%	54%	59%	58.8%	64%
अन्य भारतीय उत्पादकों की विक्री	%	5%	5%	6%	5.9%	6%
संबद्ध देश	%	2%	1%	1%	0.4%	0.5%
जांच के अधीन देश	%	5%	9%	13%	14.2%	14%
अन्य देश	%	33%	31%	22%	20.8%	16%
कुल मांग/ खपत	%	100%	100%	100%	100%	100%

78. उपर्युक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में पी ओ आई के दौरान वृद्धि हुई है यद्यपि, स्वतंत्र रूप में बिक्री में बहुत अधिक गिरावट आई है। यह आकस्मिक प्रवृत्ति मांग में गिरावट के कारण देखी गयी है। संबद्ध देश से आयात की मात्रा और हानि की जांच की अवधि के दौरान इसका बाजार हिस्सा बहुत मामूली है। शुल्क लगाये जाने के बाद संबद्ध देश से खाली किये गये बाजार के हिस्से का स्थान जांच के अधीन देशों द्वारा लिया गया है तथा इन आयातों का कुल बाजार हिस्सा कुल मांग का लगभग 14.5 प्रतिशत है।

79. चूंकि संबद्ध देश से आयात बहुत कम है इसलिए घरेलू उद्योग को वर्तमान हानि का आकलन करने के लिए मात्रा के मानदंडों के संबंध में हानि की जांच भासक और अनुपयुक्त होगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि यह निर्णायक समीक्षा जांच है अतः हानि की जांच की अवधि के दौरान आयात की मात्रा शुल्क के हटाये जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग की स्थिति और आयात की संभावित स्थिति की सही नहीं दर्शा सकता है।

ख) पाटित आयातों का मूल्य प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

80. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग पर मूल्यों पर प्रभाव की जांच मूल्य में कटौती, कम मूल्य पर बिक्री, मूल्य पर दबाव आदि के संबंध में किया गया है। इस विश्लेषण के प्रयोजन से घरेलू उद्योग की उत्पादन की लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एन एस आर) और अहानिकर मूल्य (एन आई पी) की तुलना संबद्ध देश संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के अवतरित मूल्य से की गई है।

81. अहानिकर मूल्य का निर्धारण घरेलू उद्योग के लिए इस प्राधिकारी की सतत प्रथा के अनुसार की गई है जिसमें पी ओ आई के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पादन की लागत पर उपयुक्त रूप से विचार किया गया है। चूंकि मशीनों की लागत और मूल्य दबाव बल पर निर्भर करते हुए अलग-अलग होता है अतः पृथक अहानिकर मूल्यों का निर्धारण एक उचित तुलना के लिए अलग अलग क्षमताओं हेतु किया गया है। तदनुसार, मूल्य कटौती और कम मूल्य पर बिक्री के प्रभावों का विश्लेषण अलग-अलग क्षमता स्तर पर किया गया है जो नीचे दिया गया है :

i. मूल्य कटौती का प्रभाव

82. मूल्य कटौती का निर्धारण प्रयोक्त मशीन के लिए घरेलू उद्योग के भारित औसत निवल बिक्री प्राप्ति (कलेम्पिंग फोर्स टनेज के आधार पर) के साथ जांच की समग्र अवधि में संबद्ध देश से पाटित आयातों के भारित अवसर अवतरित मूल्य से तुलना करते हुए की गई। इस उद्देश्य से अवतरित आयात मूल्य की गणना डी जी सी आई एंड एस आयात के आंकड़ों में सूचित किए गए मूल्य में 1 प्रतिशत हैंडलिंग चार्ज तथा लागू सीमा शुल्क को जोड़कर की गई है।

83. घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति का निर्धारण करने के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग द्वारा पेशकश की गई किसी छूट, डिस्काउंट, कमीशन आदि तथा भुगतान किया गया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को कुल बिक्री प्राप्ति से घटाकर किया गया है। मूल्य कटौती के निर्धारण के उद्देश्य से संबद्ध देश से आयात की भारित औसत अवतरित मूल्य की तुलना पी ओ आई के लिए निर्धारित घरेलू उद्योग की अहानिकर बिक्री मूल्य से की गई है।

कलेम्पिंग फोर्स (पी. ए.)	मशीनों की संख्या	निवल बिक्री मूल्य रु./ मशीन	अवतरित मूल्य रु./ मशीन	मूल्य कटौती (रु./ मशीन)	मूल्य कटौती (%)
120	8	****	****	****	****
125	1	****	****	(****)	(****)
128	2	****	****	(****)	(****)
150	1	****	****	****	****
380	1	****	****	****	****
कुल/ भारित औसत	13	****	****	****	30-40 %

84. उपर्युक्त आंकड़े मूल्य कटौती को दर्शाते हैं, जिसमें लागू पाटन रोधी शुल्क को शामिल नहीं किया गया है, जो अनेक उत्पाद प्रकारों के लिए बहुत अधिक है तथा भारित औसत कटौती स्तर भी बहुत अधिक घनात्मक है।

ii. मूल्य कटौती प्रभाव

85. मूल्य कटौती हानि के आकलन का एक महत्वपूर्ण सांकेतक है; इस प्रकार से प्राधिकारी ने प्रत्येक उत्पाद प्रकारों के लिए संबद्ध वस्तुओं का अहानिकर मूल्य तय किया है तथा उसकी तुलना मूल्य की कटौती की सीमा को तय करने के लिए उत्पाद प्रकार के स्तर पर आयात किए गए सामानों के अवतरित मूल्य से किया है। पाटित आयात का मूल्य कटौती प्रभाव की जांच करने के लिए, लागू पाठन रोधी शुल्क पर विचार किए बिना आयात का अवतरित मूल्य की तुलना समान उत्पाद प्रकारों के लिए निर्धारित अहानिकर मूल्य के साथ किया गया है, जो निम्नानुसार है:

कलेस्पिंग फोर्स (भी. ट.)	मशीनों संख्या	निवल विक्री मूल्य रु./ मशीन	पंहुच मूल्य रु./ मशीन	कम कीमत पर विक्री (रु./ मशीन)	मूल्य कटौती (%)
120	8	****	****	****	
125	1	****	****	****	
128	2	****	****	****	
150	1	****	****	****	
380	1	****	****	****	
कुल/ भारित औसत	13	****	****	****	25-35%

86. उपर्युक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि पाटित आयातों का अवतरित मूल्य अधिकतर उत्पाद प्रकारों के लिए घरेलू उद्योग के अहानिकर मूल्य से बहुत कम है और भारित औसत मार्जिन भी बहुत अधिक है।

iii. मूल्य दबाव, दमन के प्रभाव

87. इस बात की जांच करने के लिए कि क्या घरेलू कीमतें संबद्ध देश से पाटित आयातों के मौजूद रहने के कारण दबाव में आई हैं अथवा इसका दमन किया गया है, घरेलू उद्योग की भारित औसत विक्री प्राप्ति की प्रवृत्ति की तुलना भारित औसत स्तर पर विक्री की लागत और अवतरित मूल्य से की गई है।

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	पी औ बाई (वार्षिक रूप से)	जन.- जून 14 (पी औ बाई के बाद) वार्षिक रूप से
विक्री की लागत	रु./ सं.	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	मूच्चकांक	100	112	125	125	120
निवल विक्री प्राप्ति	रु./ सं.	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	मूच्चकांक	100	103	112	111	106
पाठन रोधी शुल्क के विना आयात का अवतरित मूल्य	रु./ सं.	17,92,987	21,50,412	21,80,647	13,95,407	27,13,504
प्रवृत्ति	रु./ सं.	100	120	122	64	151

88. उपर्युक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि जबकि विक्री की भारित औसत लागत में हानि की जांच की अवधि में बहुत अधिक वृद्धि हुई है फिर भी भारित औसत विक्री मूल्य उसी दर से नहीं बढ़ी है जो मूल्य पर दबाव का संकेत देता है।

89. हालांकि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की लागत और मूल्य क्षमता और अन्य विन्यास पर निर्भर करते हुए बहुत अधिक अलग-अलग होती है और इसलिए भारित औसत आधार पर किसी प्रकार की तुलना स्थिति को सार्थक रूप से समझने में सहायता नहीं दे सकता है।

ज. 3. घरेलू उद्योग के अन्य आर्थिक मानदंडों की जांच

90. पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध-।। में यह अपेक्षा है कि हानि के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर पाठित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। इसके अलावा नियमावली में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाठित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संबंधित आर्थिक कारकों का एक उद्देश्यपरक और विना किसी पक्षपात के मूल्यांकन शामिल होना चाहिए और इसमें उन सूचकांकों को भी शामिल करना चाहिए जिसकी विक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो, और इसमें उन कारकों को भी शामिल किया जाना चाहिए जो घरेलू मूल्य, पाटन के मार्जिन का आकार; नकद प्रवाह, माल भंडार, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूँजी निवेश प्राप्त करने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो।

91. जैसा कि ऊपर दिया गया है घरेलू उद्योग से संबंधित हानि के विभिन्न मानदंडों की जांच नीचे दिये गये अनुसार की गई है :

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और विक्री पर वास्तविक और संभावित प्रभाव

92. नीचे दी गई तालिका हानि की जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और विक्री को दर्शाता है।

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	पी ओ आई (अक्टू. 12-दिसं. 13) (वार्षिक रूप से)	जन. - जून 14 (पी ओ आई के बाद) वार्षिक रूप से
क्षमता	सं.	3,650	4,200	4,600	4,600	4,600
उत्पादन	सं.	2,260	2,229	2,053	1,997	2,380
उपयोग क्षमता	%	62	53	45	43	52
विक्री मात्रा						
घरेलू	सं.	1,990	1,940	1,737	1,621	1,934
निर्यात	सं.	****	****	****	****	****
	प्रवृत्ति	100	121	123	149	190
कुल विक्री	सं.	****	****	****	****	****
	प्रवृत्ति	100	99	99	88	106

93. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन रोधी शुल्क लगाये जाने के बाद घरेलू उद्योग ने 2011-12 में अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि 2004-05 और 2010-11 के बीच प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनों के लिए मांग बहुत अधिक थी और इसने इस अवधि के दौरान अच्छी वृद्धि दर्ज की है। प्लास्ट इंडिया रिपोर्ट 2012 में दिए गए विभिन्न प्रयोक्ता उद्योग की संभावना के आधार पर मांग के अनुमानों के अनुसार प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनों की मांग 2020 तक प्रतिवर्ष लगभग 1,50,000 मशीनों के स्तर तक पहुंच जाने की आशा थी। उद्योग में हो रहे विकास पर विचार करते हुए इस देश में इस उत्पाद के लिए संभावित विकास पर विचार करते हुए, भारत में प्रमुख पी पी एम उत्पादकों ने पर्याप्त नए निवेश करते हुए अपनी क्षमताओं का विस्तार किया। हालांकि, दुर्भाग्यवश सामान्य आर्थिक मंदी के कारण, इन मशीनों के उपभोक्ताओं विशिष्ट रूप से ऑटो संघटक क्षेत्र के उपभोक्ताओं द्वारा उत्पादन की जा रही उत्पादों की मांग में बहुत अधिक गिरावट आई जिसके परिणामस्वरूप विचाराधीन उत्पाद की मांग में पिछले 4 वर्षों में बहुत अधिक गिरावट आई। इसके फलस्वरूप उत्पादन और घरेलू विक्री प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई थी। पी ओ आई के बाद की अवधि में घरेलू उद्योग का उत्पादन, विक्री और क्षमता उपयोग में बहुत अधिक सुधार हुआ है। हालांकि, वह आधार वर्ष के स्तर से कम है।

ख. लाभ/ हानि, नकदी का प्रवाह, नियोजित पूँजी पर आय, माल सूची, उत्पादकता पर वास्तविक और संभावित प्रभाव

94. घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन लाभप्रदता के मापदंडों के संबंध में नीचे दिए गए अनुसार है :

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	पी ओ बाई (अक्टू. 12-दिसं. 13) (वार्षिक रूप से)	जन. - जून 14 (पी ओ बाई के बाद) वार्षिक रूप से
लाभ/ हानि	रु. लाख में	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	43	21	19	12
कर एवं व्याज के पूर्व लाभ/ हानि	रु. लाख में	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	50	26	23	17
नकद लाभ	रु. लाख में	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	49	31	28	24
नियोजित पूँजी	रु. लाख में	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	138	166	182	171
नियोजित पूँजी पर आय	%	****%	****%	****%	****%	****%
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	36	16	13	10

95. उपर्युक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि यद्यपि घरेलू उद्योग का घरेलू प्रचालन संपूर्ण हानि की जांच की अवधि के दौरान लाभप्रद रहा है तथापि, कंपनी का निवल लाभ और नियोजित पूँजी पर आय में वर्ष 2012-13 से बहुत अधिक गिरावट आई है। नकद लाभ में भी हानि की अवधि के दौरान बहुत अधिक गिरावट आई है।

ग. रोजगार और मजदूरी पर वास्तविक एवं संभावित प्रभाव

96. नीचे दिए गए रोजगार और मजदूरी के संबंध में आंकड़े दर्शाते हैं कि रोजगार और मजदूरी में वृद्धि हुई है यद्यपि उत्पादकता कम अथवा अधिक उतनी ही रहती है। प्राथिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग व्यापक क्षमताओं की प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनों का उत्पादन करता है और उनमें से कुछ मशीनों को इस जांच में शामिल नहीं किया गया है। अतः रोजगार और मजदूरी के संबंध में सूचना विचाराधीन उत्पाद के संबंध में इस उद्योग की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से नहीं दर्शा सकता है।

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	पी ओ बाई (अक्टू. 12-दिसं. 13) (वार्षिक रूप से)	जन. - जून 14 (पी ओ बाई के बाद) वार्षिक रूप से
रोजगार	सं.	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	107	108	107	110
मजदूरी	रु. लाख में	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	128	142	156	177
उत्पादकता	सं./दिन	6	6	6	6	7
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	100	100	100	105

घ. माल सूची पर वास्तविक और संभावित प्रभाव

97. घरेलू उद्योग का माल भंडार पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है और यह स्थिर रहा है जैसा कि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है :

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	पी ओ आई (बक्ट्. 12 - दिसं. 13)	पी ओ आई (बक्ट्. 12 - दिसं. 13) वार्षिक रूप से	जन. - जून 14 (पी ओ आई के बाद) वार्षिक रूप से
माल सूची	सं.	****	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	200	120	360	360	280

ज. 4. कारणात्मक संबंध

98. नियमावली में प्राधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वह पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई हानि और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध की जांच करे। प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात कारकों से घरेलू उद्योग को हानि हो सकती थी। निम्नलिखित मुद्दों को प्राधिकारी के ध्यान में लाया गया है और उसकी जांच गैर कारण विश्लेषण के लिए उपलब्ध सूचना के अनुसार की गई है।

(i) तीसरे देशों से आयात :

99. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं का आयात भारतीय बाजार में अनेक देशों से हो रहा है और इन देशों में से कुछ देशों से आयात बहुत अधिक हो रहा है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए एक आवेदन के आधार पर कुछ देशों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच शुरू की है। यद्यपि, उस जांच में विचाराधीन उत्पाद का कार्य क्षेत्र अपेक्षाकृत व्यापक है, इसमें इस जांच में भी विचाराधीन उत्पाद को शामिल किया गया है। इन देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात के आंकड़े दर्शाते हैं कि वे आयात पी ओ आई के दौरान कुल आयात का लगभग 40 प्रतिशत हुआ। चूंकि ये कथित रूप से पाटित मूल्य पर हुआ है अतः घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन इन आयातों के संचयी प्रभाव के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता था। अन्य देशों से आयात जिन्हें पाटित किया हुआ नहीं कहा जा सकता है, आयात का लगभग 58 प्रतिशत होता है और अपेक्षाकृत अधिक मूल्य पर हुए हैं।

(ii) मांग में संकुचन :

100. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष से घरेलू बाजार में उत्पाद की मांग में बहुत अधिक गिरावट हुई थी। हालांकि घरेलू उद्योग में यह तर्क दिया है कि संबद्ध वस्तुओं का बहुत अधिक उपयोग इलेक्ट्रिकल, पैकेजिंग, मेडिकल, होम एप्लाइनेशन और ऑटो क्षेत्र में किया जाता है। ऑटो क्षेत्र के विकास में इस अवधि के दौरान लगभग 16 प्रतिशत की गिरावट आई है, जिसके कारण इस क्षेत्र में उपयोग की गई मशीनें या तो निष्क्रिय हैं अथवा उनका उपयोग पैकेजिंग और अन्य क्षेत्रों के लिए किया जाता है। इस प्रकार से जबकि ऑटो क्षेत्र में मांग में कमी से इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम मांग हुई है। साथ ही इसमें अन्य क्षेत्रों में भी मांग में गिरावट के लिए परिस्थितियां पैदा की हैं।

(iii) खपत की पद्धति:

101. किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा यह दर्शने के लिए कोई सूचना नहीं दी गई है कि घरेलू उद्योग की स्थितियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले अन्य प्रतियोगी उत्पादन की तुलना में विचाराधीन उत्पाद के खपत की पद्धति में कोई पर्याप्त परिवर्तन हुआ है।

(iv) प्रतियोगिता की स्थिति :

102. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच ने यह नहीं दर्शाया है कि प्रतियोगिता की स्थितियां अथवा व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियों घरेलू उद्योग को दावा की गई हानि के लिए जिम्मेदार हैं।

(v) प्रौद्योगिकी में विकास :

103. किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा यह दर्शने के लिए कोई सूचना नहीं दी गई है कि इंजेक्शन मोलिंडिंग अथवा नई पीढ़ी की मशीनों के विकास में कोई पर्याप्त वृद्धि हुई है जिससे घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

(vi) घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य निष्पादन

104. घरेलू उद्योग के निर्यात की मात्रा में हानि की जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। हालांकि, पूर्व के भाग में हानि का विश्लेषण घरेलू उद्योग के घरेलू कार्य निष्पादन के आधार पर हुआ है। घरेलू और निर्यात बाजारों में मूल्य और लाभप्रदता को इस प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली हानि के आकलन करने के प्रयोजन से अलग अलग रखा गया है।

ज. हानि और कारणात्मक संबंध पर निष्कर्ष

105. उपर्युक्त विश्लेषण दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में उत्पादन, विक्री और क्षमता उद्योग में गिरावट; लाभ और निवेश पर आय में गिरावट के कारण हानि की जांच की अवधि के दौरान अंशिक रूप से गिरावट आई है। संबद्ध देश से आयात की गई संबद्ध वस्तु यद्यपि उनकी संख्या बहुत कम है, से घरेलू उद्योग की कीमतों में पर्याप्त रूप से कटौती होना जारी है तथा इसका घरेलू उद्योग की विक्री मूल्य पर बहुत अधिक मूल्य कटौती प्रभाव हुआ है। हालांकि, संबद्ध देश से आयात की मात्रा इस समय बहुत कम है और पी ओ आई के दौरान पाटन रोधी शुल्क लागू है अतः पाटित आयातों की मात्रा और मूल्य के प्रभाव इस अवधि के दौरान बहुत अधिक नहीं प्रतीत होता है। जैसा कि पूर्व में नोट किया गया है, अनेक कारकों को मिलाकर जैसे कथित रूप से पाटित कीमतों पर तृतीय स्रोतों से आयातों की बहुत अधिक मात्रा, संबद्ध देश से पाटित आयात और घरेलू मांग में कमी से ऐसा लगता है कि इन्होंने जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

ज. हानि और हानि के मार्जिन का आकार

106. पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध ।।। के अनुसार इस प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं का अहानिकर मूल्य की तुलना पी ओ आई के दौरान हानि के मार्जिन के निर्धारण के लिए संबद्ध देश से इन निर्यातों के अवतरित मूल्य से की गई है और इस प्रकार तय किया गया हानि मार्जिन नीचे दिया गया है :

कलेम्पिंग फोर्स (पी. ट.)	मशीनों संख्या	एन बाई पी (रु./ मशीन)	बवतरित मूल्य रु./ मशीन	हानि मार्जिन (रु./ मशीन)	हानि मार्जिन (%)
120	8	****	****	****	
125	1	****	****	****	
128	2	****	****	****	
150	1	****	****	****	
380	1	****	****	****	
कुल/भारित औसत	13	****	****	****	25-35%

ट. हानि के जारी रहने अथवा उसके बार बार होने की संभावना

107. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह एक निर्णयिक समीक्षा जांच है और इस जांच का केन्द्र शुल्कों के हटाये जाने की स्थिति में हानि के संभावित परिदृश्य की जांच करना है। यद्यपि, कुल वर्तमान हानि न हुई हो और/अथवा कारणात्मक संबंध न हो। पूर्व के भाग में पाटन के जारी रहने अथवा उसके बार बार होने की संभावना के होने के संबंध में यह सिद्ध किया गया है कि पाटन से शुल्कों के वापस लिये जाने की स्थिति में संबद्ध देश से बार बार होने की संभावना है। चूंकि, संबद्ध देश के लिए वर्तमान आयात मामूली हैं और ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इसका घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। प्राधिकारी शुल्कों के हटाये जाने की स्थिति में पाटित आयातों के कारण हानि के फिर से होने की संभावना की जांच करने के लिए कार्यावाही करती है।

ट. 1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

108. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि पाटन रोधी शुल्क को समाप्त किए जाने से पाटन और परिणामी हानि के जारी रहने अथवा इसके फिर से होने की संभावना है। इसके अलावा, यह दावा किया गया है कि समीक्षा जांच का समग्र उद्देश्य यह देखने के लिए नहीं है कि क्या पाटन रोधी शुल्क लगाये जाने की कोई आवश्यकता है बल्कि यह देखने के लिए है कि क्या पाटन रोधी के जारी रहने के अभाव में यह जारी रहेगी और घरेलू उद्योग को हानि होगी और क्या घरेलू उद्योग को बहुत अधिक हानि होना जारी रहेगा अथवा घरेलू उद्योग को हानि फिर से होगी यदि शुल्कों को हटाया जाता है। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने आगे निम्नलिखित अनुरोध किया है:

- कि चीन अन्य देशों नामतः मलेशिया, फिलीपींस, ताईवान और वियतनाम से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटन रोधी शुल्क लगाने के बाद भारत में विचाराधीन उत्पाद का पाटन शुरू हुआ है। घरेलू उद्योग ने इन देशों से आयातों पर पाटन रोधी शुल्कों के लगाये जाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी इस समय यह जांच कर रहे हैं यद्यपि जांच के अधीन अन्य याचिका में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में अपेक्षाकृत बहुत अधिक टन की मशीनें भी शामिल हैं। घरेलू उद्योग को आशा है कि इस जांच से इन देशों से पाटन का मौजूद होना सिद्ध होगा, जिससे घरेलू उद्योग को हानि हुई है;
- यह कि विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देश से पाटित मूल्य पर भारत में निर्यात किया जाना जारी है और वर्तमान पीओआई में पाटन मार्जिन और हानि का मार्जिन दोनों सकारात्मक और पर्याप्त हैं। ये आयात पाटन रोधी शुल्क के लागू रहने के बावजूद घरेलू उद्योग की कीमतों में कटाई कर रहे हैं। आयात का अवतरित मूल्य घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य से न केवल कम है बल्कि घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत से भी कम है;
- यह कि पाटन रोधी शुल्क के समाप्त किये जाने की स्थिति में चीन से आयात का अवतरित मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री मूल्य से बहुत कम होगा। इसलिए भारतीय उत्पादकों को पाटन रोधी शुल्कों को हटाये जाने की स्थिति में बहुत अधिक मात्रा का नुकसान होगा;
- यह कि चीन के उत्पादक पाटन का सहारा लिये बिना इस उत्पाद का निर्यात करने में सक्षम नहीं हैं और यदि चीन के उत्पादक पाटन का सहारा लेते हैं तब घरेलू उद्योग को बहुत अधिक हानि होगी;
- यह कि चीन का अनुमान 2015 तक सभी अतिरिक्त वैश्विक मांग का 40 प्रतिशत से अधिक है क्योंकि विकासशील देशों में लाभ प्लास्टिक प्रसंस्करण उपकरण बाजार विकास के लिए गति देने वाला बल होता है। चीन विचाराधीन उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है तथा चीन के उत्पादक बहुत अधिक निर्यात केन्द्रित हैं;
- यह कि विचाराधीन उत्पाद के लिए बाजार ने भारत में मांग में कुछ गिरावट को देखा है। इसके अलावा, चीन के उत्पादकों को अपने घरेलू बाजार में इस उत्पाद के लिए मांग में गिरावट की समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। इस प्रकार से पाटन रोधी शुल्कों को हटाये जाने की स्थिति में, चीन के उत्पादक भारतीय बाजार की ओर बढ़ेगे और ऐसा इस देश में उत्पाद की पर्याप्त मांग को देखते हुए होगा। अतः पाटन रोधी शुल्क को समाप्त करने के फलस्वरूप चीन के उत्पाद की मांग में बहुत अधिक वृद्धि होगी और उससे घरेलू उद्योग को और अधिक हानि होगी।
- यह कि जिस मूल्य पर संबद्ध वस्तुओं का आयात किया जा रहा है वह उस मूल्य से बहुत अधिक कम है जिस पर इन सामानों की बिक्री घरेलू बाजार में की जा रही है। अतः शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में, निर्यातक भारतीय बाजार में अपने उत्पादन को और अधिक बढ़ायेंगे क्योंकि इनके पास पहले से ही बहुत अधिक क्षमताएं हैं और वास्तव में वे पर्याप्त रूप से कम कीमतों पर तृतीय देश को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं;
- यह कि भारतीय बाजार अत्यधिक मूल्य संबद्धनशील हैं। उपभोक्ता मूल्य पर सबसे अधिक विचार करने के बाद अपनी खरीद के बारे में निर्णय लेते हैं। ऐसा मामला होने के कारण इस बाजार में संबद्ध देश से इस प्रकार की कम मूल्य पर आयात की उपलब्धता से निश्चित रूप से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

109. घरेलू उद्योग ने पहले प्रकटन विवरण पर अपनी टिप्पणियों में यह बताया है कि वर्तमान मामले के निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण, शुल्क की राशि निम्नलिखित कारणों की वजह से मूल जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित शुल्क के समान रहनी चाहिए।

- i. संबद्ध देश से आयातों की मात्रा कमतर स्तर तक कम हो गया है और ऐसी कम मात्रा के आधार पर निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन शुल्कों को हटाये जाने पर संभावित पाटन मार्जिन या क्षति मार्जिन को प्रदर्शित नहीं करेगा। ऐसे मार्जिनों पर आधारित पाटनरोधी शुल्क पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति पर रोक लगाने में सक्षम नहीं होगा।
- ii. उत्पादकों और निर्यातकों ने जानबूझकर वर्तमान जांच में उत्तर नहीं देने को चुना है क्योंकि वे भली-भांति जानते हैं कि उससे उच्चतर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन होंगे। संबद्ध देश में निर्यातकों/उत्पादकों ने ऐसोसिएशन के माध्यम से जांच के प्रति सरलता से अपना विरोध जताया है जबकि अपनी कीमत संबंधी कोई सूचना नहीं दी है।
- iii. मूल जांच, जब उत्पादकों और निर्यातकों ने सहयोग किया और अपने आकड़े दिए हैं, में निर्धारित मार्जिनों के आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाना अधिक उचित और उनकी वास्तविक कीमत को अधिक प्रदर्शित करेगा और पाटन पर रोक लगाने में समर्थ होगा।
- iv. निर्यातकों और उत्पादकों को उनके असहयोग के परिणामस्वरूप कम पाटनरोधी शुल्क का पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए।

- v. नियमों में इस निर्धारण की व्यवस्था है कि क्या पाटनरोधी शुल्कों को आगे बढ़ाया जाए। इसका अर्थ एक निर्णय है कि क्या शुल्क को आगे बढ़ाया जाए या नहीं। यद्यपि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने व्यवहार में पाटनरोधी शुल्क की राशि में परिवर्तन करने के लिए इस अवसर का उपयोग किया है परंतु जहाँ मामला पाटन की संभावना पर आधारित है, ऐसा अवसर उपलब्ध नहीं है।
- vi. कनाडा, अमरीका और यूरोप जैसे तीसरे देशों द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया इस बात का निर्णय लेना है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की अवधि बढ़ाई जाए अथवा नहीं। ये देश पीओआई में भारी आयात होने पर और पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन (ईसी) मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों से कम होने पर भी पाटनरोधी शुल्क की राशि को बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं।
- vii. ऐसे पूर्ववर्ती मामले हुए हैं जिनमें निर्दिष्ट प्राधिकारी ने समीक्षा के मामले में मूल जॉचों में निर्धारित पाटन मार्जिन से कम मार्जिन होने के बावजूद निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उनकी संबंधित मूल जॉच में अनुशंसित शुल्क के बराबर शुल्क की राशि को बढ़ाये गया है।
110. घरेलू उद्योग ने यह भी बताया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के सीआईएफ मूल्य के प्रतिशत के रूप में पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए (शुल्क के मूल्यानुसार) क्योंकि इस उत्पाद पर इस समय पहले ही मूल्यानुसार पाटनरोधी शुल्क लागू है। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद में विभिन्न क्लेम्पिंग बलों के संगत अनेक उत्पाद प्रकार शामिल हैं। विभिन्न क्लेम्पिंग बलों वाली मशीनों की संबद्ध लागत और कीमत क्लेम्पिंग बल और विशेषताओं पर निर्भर करती है। उत्पाद की क्षमता और कीमत के अनुसार उसमें भारी अंतर है। अतः इस मामले में संदर्भ कीमत या नियत शुल्क के अनुसार पाटनरोधी शुल्क उचित नहीं होगा।

ट. 2 उत्पादकों/ नियर्यातकों/ आयातकों/ बन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

111. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अपने अनुरोध में यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता को हानि के फिर से होने की संभावना का दावा केवल अनुमान पर आधारित है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अन्य बातों के साथ यह तर्क दिया है :

- यह कि याचिकाकर्ता द्वारा हानि की संभावना के अपने दावे के समर्थन में दिया गया एक मात्र आधार चीन में अत्यधिक क्षमता और भारतीय बाजार की आकर्षकता है। यह दर्शाया भी नहीं गया है कि किस प्रकार से वास्तव में कोई ऐसी अत्यधिक क्षमता शुल्कों के अभाव में भारत में परिवर्तित किया जायेगा;
- यह कि मात्र अत्यधिक क्षमता के दावे में बहुत अधिक कमियां हैं और यह सी पी एम आई ए द्वारा दिए गए वास्तविक आंकड़ों के आलोक में निरस्त कर दिया गया है। वास्तव में याचिकाकर्ता के लिए यह दर्शाना आवश्यक था कि किस प्रकार से कोई ऐसी अतिरिक्त क्षमता पाटन रोधी शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में भारत में परिवर्तित किया जायेगा जो इस याचिका में पूर्ण रूप से गायब है। याचिकाकर्ता द्वारा अपने दावे के समर्थन में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है;
- यह कि उनके दावे का समर्थन करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि किस प्रकार से याचिकाकर्ता को हानि फिर से होगी यदि शुल्कों को हटा लिया जाता है। मूल्य की आकर्षकता मात्र एक काल्पनिक विचार है जिसके आधार पर भारत में प्रयोक्ता उद्योग को एक अन्य पांच वर्षों की अवधि के लिए शुल्कों के अतिरिक्त बोझ से लादा नहीं जा सकता है;
- यह कि इस आवेदन में स्वयं इस बात को मान लिया गया है कि संबद्ध वस्तुओं की बिक्री न केवल कीमतों का कार्य है बल्कि अन्य कारक भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जैसे मशीन की विशेषता/उर्जा व्यवहार की क्षमता आदि में विकास। अतः मूल्य की आकर्षकता का तर्क अपने आप में अस्वीकार्य है और यह धारा 9क (5) के संबंध में शुल्कों की अवधि को बढ़ाने के लिए आधार नहीं बन सकता है।
- यह कि चीन जन गण में कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं है और चीन में इस उत्पाद के लिए घरेलू मांग बहुत मजबूत है। इसके अलावा, चीन जन गण से तृतीय देश में नियर्यात घरेलू उद्योग के एन एस आर और एन आई पी की तुलना में बहुत अधिक मूल्य पर है। चीन के उत्पादक पहले से ही क्षमता उपयोग के मामले में आदर्शतम स्तर से अधिक पर कार्य कर रहे हैं और इस बात को दर्शाने के लिए प्रमाण का कोई कारण भी नहीं है कि संबद्ध वस्तुओं को शुल्कों को हटाये जाने की स्थिति में पाटिट मूल्य पर भारत में भेजा जायेगा;
- यह कि संभावना की जांच को इस तथ्य के आधार पर देखे जाने की आवश्यकता है जैसा यह है और न कि उस आधार पर जो याचिकाकर्ता का अतिशयोक्ति और अप्रमाणित आशंका हो;
- यह कि भारतीय मांग ने सतत गिरावट दर्शायी है जबकि घरेलू उद्योग ने नियर्यात बाजार को लक्ष्य बनाते हुए पर्याप्त रूप से अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है। घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध भारतीय मांग की तुलना में अतिरिक्त क्षमता 40 प्रतिशत के करीब है और घरेलू उद्योग की निर्धारित लागत पर उसके प्रभाव को चीन जन गण से कथित आयात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।

112. सीपीएमआईए ने पहले प्रकटन विवरण संबंधी अपनी टिप्पणियों में तर्क दिया कि प्रकटन विवरण दर्शाता है कि घरेलू उद्योग मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की अवधि समाप्त होने के संदर्भ में पाटन और क्षतिकी संभावना को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दे सका है जबकि सीपीएमआईए जिसने सत्यापन की पेशकश की है, द्वारा प्रदत्त आकड़े वर्तमान शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति की कोई संभावना नहीं दर्शाते हैं। चीन के उत्पादक ईष्टटम स्तर से अधिक पर प्रचालन कर रहे हैं और वे तीसरे देशों के बाजारों में काफी अधिक कीमत प्राप्त कर रहे हैं। चूंकि याचिकाकर्ता के आकड़े ही यह दर्शाते हैं कि भारत में घरेलू मांग में गिरावट दर्शाते हैं, इसलिए चीन के

निर्यातकों के लिए वह लाभकारी नहीं हो सकता है। अतः मौजूदा उपायों की अवधि समाप्त होने पर पाटन और क्षति की कोई संभावना नहीं होने को दर्शने वाले तथ्यों के आधार पर प्राधिकारी के समक्ष वर्तमान मामले में संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने देना चाहिए।

ठ. क्षति और क्षति की संभावना के संबंध में 14 सितम्बर, 2015 को जारी दूसरे प्रकटन विवरण के संबंध में हितबद्ध पक्षों की टिप्पणियां

113. प्राधिकारी ने 14 सितंबर, 2015 को दूसरा प्रकटन विवरण जारी किया जिसमें प्राधिकारी के समक्ष मामले के अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन और सभी हितबद्ध पक्षों से टिप्पणियां आमंत्रित की गईं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि दूसरे प्रकटन विवरण पर अपनी टिप्पणियों में सभी पक्षों ने अधिकांशतः इस जांच से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में अपनी संबंधित स्थिति को दोहराया है। इन मुद्दों पर संबंधित खंडों में पर्याप्त रूप से विचार किया गया है और संक्षिप्तता के लिए उन्हें दोहराया नहीं गया है।

ड. क्षति के जारी रहने और उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के संबंध में प्राधिकारी के विचार

114. प्राधिकारी ने पाटन रोधी शुल्क को वापिस लिये जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को हानि के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना के संबंध में इस जांच के अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण को नोट किया है और आगे यह नोट करते हैं कि इस उद्योग को संबद्ध देश से पाटित आयातों यद्यपि उसकी मात्रा कम है, सहित अनेक कारकों के कारण बहुत अधिक हानि होना जारी है।

115. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि वर्तमान आयात मात्रा संबद्ध देश से बहुत कम है तथापि, जांच के अधीन अन्य देशों से आयात की मात्रा बहुत अधिक है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि विभिन्न कारकों की वस्तुनिष्ठ जांच पर आधारित पूर्ववर्ती खंडों में पाटन के जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति होने की स्पष्ट संभावना सिद्ध हुई है। घरेलू उद्योग को हानि के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना के परिदृश्य की जांच के लिए निम्नलिखित कारकों की जांच की गई है।

(क) वर्तमान और विगत पाटन मार्जिन का स्तर

116. वर्तमान और ऐतिहासिक पाटन मार्जिन का स्तर प्रवृत्ति के जारी रहने की संभावना का द्योतक है और इस कारण से हानि होने की संभाव्यता दर्शाता है कि संबद्ध वस्तुओं के लिए मूल और वर्तमान जांच में दोनों में पाटन का मार्जिन अधिक यद्यपि वर्तमान पी ओ आई के दौरान संबद्ध देश से आयात की मात्रा लागू पाटन रोधी शुल्क के प्रभाव के कारण बहुत कम है। यह दर्शाता है कि संबद्ध देश पर पाटन रोधी शुल्क संबद्ध देश से व्यापक स्तर पर पाटित आयातों को रोकने में सफल रहा है जिसके कारण मांग सहित अनेक कारकों, जिसके बारे में पूर्व में चर्चा की गई है, के कारण फिर से बदतर स्थिति होने के पूर्व घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में कुछ सुधार हुआ है।

117. इसके अलावा प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू मांग को पूरा करने के लिए क्षमता धारण करने वाले घरेलू उद्योग के बावजूद, आयात की पर्याप्त मात्रा बहुत अपेक्षाकृत कम कीमतों पर कुछ अन्य देशों से आ रही है और ये आयात भी जांच के अधीन हैं। अतः बहुत अधिक संभावना है कि जैसे ही शुल्कों को हटा लिया जायेगा चीन जन गण से तुलनीय कीमत पर आयात शुरू हो जायेगा। इन कीमतों पर घरेलू उद्योग के मूल्यों में कटौती और कम मूल्य पर विक्री बहुत अधिक होगी जो लाभप्रद कीमत प्राप्त करने से इसे रोकेगा।

(ख) भारतीय बाजार की मूल्य की आकर्षकता

118. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि मूल्य इस तरह के उत्पादों जो पूँजीगत सामान हैं, के लिए खरीद के बारे में निर्णय करने के लिए एक मात्र निर्धारक मानदंड नहीं है जहां विशेषताएं और उर्जा क्षमताओं आदि भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मूल्य एक प्रमुख दृष्टिकोण रह जाता है। जब सामान तुलनीय विशेषताओं के होते हैं तब मूल्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि चीन से निर्यात किए गए सामान अपने संबंधित क्षमता रेंज में भारतीय उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जा रही वस्तुओं की विशेषताओं से तुलनीय नहीं हैं। इस कारण से चीन से वर्तमान मूल्य का स्तर, पाटन रोधी शुल्क का आकार और तुलनीय उत्पाद प्रकारों के लिए वर्तमान घरेलू मूल्य स्तर दर्शाता है कि भारतीय बाजार इन शुल्कों के समाप्त होने पर अपने मूल्यों का समायोजन करने के लिए संबद्ध देश में उत्पादकों के लिए आकर्षक रहेगा और अभी भी घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती होना जारी रहेगा। इस प्रकार से पाटन रोधी शुल्क के समाप्त होने के साथ इस बात की प्रबल संभावना है कि घरेलू उद्योग के लाभप्रद मूल्य से कम मूल्य पर चीन से संबद्ध वस्तुओं के आयात में बहुत अधिक वृद्धि होगी, जिससे घरेलू उद्योग को हानि के फिर से होगी अथवा उससे और अधिक होगी।

(ग) वैश्विक मांग – आपूर्ति का परिदृश्य

119. घरेलू उद्योग तथा चीन के संघ द्वारा प्रस्तुत सूचना यद्यपि उसे साक्ष्यों से सिद्ध नहीं किया गया है, दर्शाता है कि चीन के बाजार में मांग और आपूर्ति का स्पष्ट संतुलन नहीं है अर्थात् मांग से बहुत अधिक क्षमताएं हैं। जांच के अधीन अन्य देशों से आयात की मात्रा और प्रवृत्ति भी यह दर्शाती है कि उन देशों में अत्यधिक क्षमताएं हैं। विशेष रूप से डाउन स्ट्रीम उत्पाद लाइन के लिए कम मांग का परिदृश्य जिसके लिए इन मशीनों का उपयोग किया जाता है, में इस बात की स्पष्ट संभावना है कि वैश्विक कंपनियों द्वारा लागू की जा रही

आक्रामक बाजार प्रवेश नीतियां अपने बाजार से और उत्पादन लाइनों को पाटित मूल्यों पर भी सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करेंगी और उनके बाजार प्रवेश नीतियों द्वारा मूल्य के स्तर प्रभावित होंगे, जिसके फलस्वरूप घरेलू कीमतों पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(च) पी ओ आई के बाद आयात की प्रवृत्तियां

120. पी ओ आई के बाद की अवधि के आयात का भी विश्लेषण बढ़े हुए आयातों की संभावना और परिणामी हानि की संभावना का आकलन करने के लिए प्रवृत्तियों को देखने हेतु किया गया है। ये आंकड़े दर्शते हैं कि यद्यपि शुल्क लागू था, उसके बावजूद पी ओ आई के बाद की अवधि में संबद्ध देश से आयात की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई है जबकि मांग में आंशिक सुधार हुआ है।

(ड) हानि के जारी रहने वथवा उसके फिर से होने की संभावना का समग्र आकलन

121. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को पहले से ही मांग में कमी के साथ साथ कथित पाटित मूल्य पर अनेक स्रोतों से बढ़े हुए आयात के कारण कम क्षमता उपयोग का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान उत्पादन और मूल्य स्तर पर घरेलू उद्योग को पहले से ही अपने वित्तीय परिणाम में बहुत अधिक गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। अतः शुल्क के समाप्त किये जाने की स्थिति में पाटित मूल्यों पर संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि से घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग और लाभप्रदता पर और अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अतः घरेलू उद्योग को हानि जो अभी भी निम्न मांग स्थिति सहित अनेक कारकों के कारण प्रभावित होना जारी है, से शुल्कों के समाप्त होने पर और अधिक हो जाने की संभावना है।

(ड) निष्कर्ष :

122. उठाये गये मुद्दों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराये गये तथ्यों जैसा कि इस निष्कर्ष में रिकार्ड किया गया है, की जांच करने के बाद प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि चीन से संबद्ध वस्तुओं का लगातार पाटन हो रहा है यद्यपि आयात की मात्रा कम है और घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन संबद्ध देश से पाटित आयातों के प्रभाव और हाल के वर्षों में मांग में गिरावट के साथ साथ जांच के अधीन देशों से कथित पाटित आयातों के कारण वर्तमान हानि की अवधि में बदतर हुआ है। पाटन जारी रहने की संभावना है और घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन वर्तमान पाटन रोधी शुल्क को हटाये जाने की स्थिति में बदतर होने की संभावना है।

(इ) भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

123. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य तौर पर पाटन रोधी शुल्कों का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई हानि को समाप्त करना है, ताकि भारतीय बाजार में खुली और स्वच्छ प्रतियोगिता की स्थिति फिर से लाई जा सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटन रोधी उपायों को लागू किये जाने से किसी भी प्रकार से संबद्ध देश से आयात पर रोक नहीं लगेगी और इस कारण से यह उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तुओं की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं ढालेगा।

(ए) सिफारिशें :

124. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की गई थी और इसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा निर्णायकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सकारात्मक सूचना और सत्यापन योग्य साक्ष्य शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में पाटन और हानि के जारी रहने की संभावना तथा पाटन, हानि और कारणात्मक संबंध के विभिन्न पहलुओं पर देने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जांच की जाने बाद यह सिद्ध करने के बाद कि पाटन और हानि जारी है और इसे जारी रहने अथवा इसके फिर से होने की संभावना है, प्राधिकारी इसे आवश्यक और उपयुक्त समझता है कि इसके नीचे निर्धारित रूप और तरीके से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन रोधी शुल्क के समय को बढ़ाये जाने की सिफारिश करते हैं।

125. प्राधिकारी द्वारा अपनाए जा रहे अपेक्षाकृत कम शुल्क के नियम के संबंध में, प्राधिकारी पाटन रोधी शुल्क को पाटन के मार्जिन और इस निष्कर्ष में जांच के अधीन अवधि में इस प्रकार से निर्धारित हानि का मार्जिन से जो भी कम हो, के बराबर पाटन रोधी शुल्क को लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के हानिकर प्रभावों को दूर किया जा सके। तदनुसार, सीमाशुल्क अधिनियम के अनुसार, वस्तुओं के आकलन योग्य मूल्य के प्रतिशत रूप में इसके साथ अनुबंधित शुल्क तालिका के कॉलम 9 में दर्शायी गई राशि के अनुसार संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से पांच वर्षों की आगामी की अवधि के लिए लगाये जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	उपशीर्षक अथवा शुल्क मद	सामानों का विवरण	विनिर्देशन	उत्पत्ति देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	माप की इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	8477.1000	प्लास्टिक प्रसंस्करण अथवा इजेक्शन मोल्डिंग मशीन	40 टन के बराबर अथवा उससे अधिक और 1000 टन के बराबर अथवा उससे कम का क्लेम्पिंग फोर्स	चीन जन गण राज्य	चीन जन गण राज्य	कोई भी	कोई भी	29	%
2	- वही -	- वही -	- वही -	चीन जन गण राज्य	चीन जन गण राज्य को छोड़कर कोई अन्य	कोई भी	कोई भी	29	%
3	- वही -	- वही -	- वही -	चीन जन गण राज्य को छोड़कर कोई अन्य	चीन जन गण राज्य	कोई भी	कोई भी	29	%

126. केन्द्र सरकार के आदेशों के विरुद्ध जो इस सिफारिश से उत्पन्न हो सकता है, इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष किया जा सकता है।

127. प्राधिकारी इस अधिनियम के संगत प्रावधानों और इस नियमावली तथा इस संबंध में समय समय जारी की गई आम सूचना के अनुसार समय पर इसमें सिफारिश किये गये अनुसार निश्चयात्मक उपाय को जारी रखने, उसमें संशोधन करने अथवा उसे समाप्त करने की आवश्यकता की समीक्षा कर सकता है। यदि उसे किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा इस उद्देश्य से निर्धारित समय सीमा के अनुसार दायर नहीं किया जायेगा तो इस प्रकार की समीक्षा के लिए कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

ए. के. भल्ला, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

[DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES]

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2015

Final Finding

Subject: - Sunset Review of Anti-Dumping duty on imports of all kinds of plastic processing or injection-moulding machines, also known as injection presses, having clamping force not less than 40 tonnes and not more than 1000 tonnes, originating in, or exported from the People's Republic of China.

No. 15/02/2014-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the Rules);

A. Background of the case:

2. The original investigation concerning imports of the subject goods from the subject country was initiated by the Authority vide Notification No. 14/12/2008- DGAD dated 8th July, , 2008. The Preliminary Finding was issued by the

Authority vide Notification No. 14/12/2008-DGAD dated 10th February, 2009 and the provisional anti-dumping duty was imposed by the Department of Revenue vide Notification No. 47/2009-Customs on 12th May, 2009. The Final Findings Notification was issued by the Authority vide Notification No. 14/12/2008-DGAD dated the 31st December, 2009, recommending imposition of definitive duty. On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings, a definitive antidumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 39/2010-Customs dated 23rd March, 2010 on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

3. M/s. Plastics Machinery Manufacturers Association of India, along with its members, viz. (a) M/s. Toshiba Machine (Chennai) Pvt. Ltd., (b) M/s. Ferromatik Milacron India Pvt. Ltd, (c) M/s. Windsor Machines Limited and (d) M/s. Electronica Plastic Machines Ltd have filed a duly substantiated application before the Authority, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from Subject Country and consequent injury to the domestic industry and have requested for review and continuation of the anti-dumping duties, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

4. In view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority initiated a sunset review investigation, vide Notification No.15/2/2014-DGAD, dated 9th May, 2014, to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the China PR (hereinafter also referred to as the subject country) and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

B. Procedure:

5. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

- i. The Authority sent copies of the initiation notification dated 9th May, 2014 to the embassy of the subject country in India, known exporters from the subject country, known importers and other interested parties, and the domestic producers, as per available information. The known interested parties were requested to file the questionnaire responses and make their views known in writing within the prescribed time limit. Copies of the letter and questionnaires sent to the exporters were also sent to embassy of the subject country along with a list of known exporters/producers, with a request to advise the exporters/producers from the subject country to respond within the prescribed time.
- ii. Copy of the non-confidential version of the application filed on behalf of the applicant was made available to the known exporters, other domestic producers and the embassy of the subject country in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules.
- iii. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating the sunset review to the following known producers/exporters in the subject country and gave them opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rules 6(2) & 6(4) of the Rules:
 1. Kee Hing Cheung Kee Co., Limited
 2. Hubei Hengda Machinery Import & Export Co., Ltd
 3. Ningbo Hengrun Plastic Machinery Co., Ltd
 4. Jining Tongjia Machinery Co., Ltd
 5. Jingjiang Jinyuan International Trade Co., Ltd.
 6. Mitstrong Mould & Machine Co., Ltd.
 7. Ningbo Economic & Technological Development Zone Haitong Machinery Equipment Co., Ltd.
 8. Hangzhou Tederic Machinery Co., Limited
 9. Guangzhou Borch Machinery Co., Limited
 10. Zhejiang Golden Eagle Plastics Machinery Co., Ltd.
 11. Liguang Machinery Co., Ltd
 12. Ningbo Haixing Machinery Manufacturing Co., Ltd
 13. Qingdao Sanyl Plastics Manchinery Ltd.
 14. Zhangjiangang New Wanda Machinery Co., Ltd.
 15. Zhejiang East Zhouqlang Plastics & Mould Industry Co., Ltd.
 16. Zhangjiangang King Machine Co Ltd

- 17. Shanghai GS Machinery Manufacture Co., Ltd.
- 18. Suzhao Fosita Science and Technology Co., Ltd.
- 19. Quindao Runjia Plastic Machinery Co., Ltd..
- iv. In response to the initiation of the subject investigation, only M/s. ENGLE Machinery (Shanghai) Co. Ltd & their sister company Engel Machinery (Changzhou) Co. Ltd., China, have responded. However the company has not filed any questionnaire response in the form and manner prescribed. China Plastic Machinery Industry Association (CPMIA) has also filed comments to the petition and initiation of the investigation without filing any questionnaire response.
- v. Questionnaires were sent to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Anti-dumping Rules:
 - (a) Electronic Plastic Machine Ltd.(Tal Mulshi, Pune)
 - (b) Plastics Machinery Manufacturers Association of India. (New Delhi)
 - (c) Ferromatik Milacron India Pvt. Ltd. (Ahmedabad)
 - (d) Windsor Machines Ltd. (Thane)
 - (e) Toshiba Machines Pvt. Ltd. (Chennai)
 - (f) Bharat Box Factory Ltd. (Punjab)
 - (g) Kunstocom (India) Ltd. (New Delhi)
 - (h) Sumi Motherson Group (Noida)
 - (i) Supreme Industries Ltd.(Mumbai)
 - (j) Vidyut Metallics Ltd (Mharashtra)
 - (k) Prince Plastics International Pvt. Ltd. (Thane)
 - (l) Prince Plastics International Pvt. Ltd. (Mumbai)
 - (m) Arun Plasto Moulders India Pvt. Ltd. (Tamil Nadu)
 - (n) Mouldwell Products (Tamil Nadu)
 - (o) Salzer Electronics Ltd. (Tamil Nadu)
 - (p) Riya Moulders (Chennai)
 - (q) CJ Polytech Pvt. Ltd. (Tamil Nadu)
 - (r) Tech Plastic Industries (Chennai)
 - (s) Sakkthi Polymers (Tamil Nadu)
 - (t) Tooling Temple (Tamil Nadu)
 - (u) Victorious Engineering Works (U.P)
 - (v) Ejobs Info Tech India Pvt. Ltd. (Coimbatore)
 - (w) Electronica Machine Tools Ltd. (Pune)
 - (x) Moldwell Products India Pvt. Ltd. (Tamil Nadu)
 - (y) All India Plastic Manufactures Association (Mumbai)
- vi. In response to the above notification, none of the importers/ users has filed importer questionnaire response.
- vii. Exporters, producers and other interested parties who have not responded to the Authority, nor supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties.
- viii. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years, including the period of investigations, which was received by the Authority. The Authority has, relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis.
- ix. Optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to

- remove injury to Domestic Industry. The NIP has been determined by the Authority in terms of the principles laid down under Annexure III to the Anti-dumping Rules.
- x. Investigation was carried out for the period starting from October, 2012 – December, 2013 (POI). However, injury examination was conducted for a period from 2010-11, 2011-12, 2012-13 and POI.
 - xi. In accordance with Rule 6(6) of the Anti-dumping Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 17th March, 2015. The parties, which presented their views in the oral hearings, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
 - xii. The submissions made by the interested parties during the course of the investigation have been considered by the Authority, wherever found relevant, in this disclosure. Verification to the extent deemed necessary was carried out in respect of the information & data submitted by the domestic industry and the co-operating producers/exporters.
 - xiii. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
 - xiv. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded the disclosure statement on the basis of the facts available.
 - xv. In terms of Rule 16 of the Rules the Authority disclosed the essential facts of the case through a disclosure statement issued on 30th July, 2015 and the comments to the said disclosure was also received from the interested parties on 4th August, 2015. However, due to change in the Designated Authority in the meanwhile, necessitating a fresh hearing, the period for completion of the investigation was extended by the Central Govt. till 7th November, 2015.
 - xvi. The Authority held a fresh hearing on 19th August, 2015 to provide an opportunity to all interested parties to present their case before the new Designated Authority.
 - xvii. The Authority also issued a fresh disclosure statement on 14th September, 2015, incorporating all essential facts and submissions made by the interested parties for comments of all interested parties.
 - xviii. Submissions made by the interested parties in response to the first disclosure statement dated 30th July, 2015 and post public hearing dated 19th August, 2015 and the second disclosure statement dated 14th September, 2015 have been considered and incorporated in this finding to the extent they were considered relevant and backed by reliable information/data/evidence.
 - xix. *** in this finding represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
 - xx. The average exchange rate of 1US\$ = Rs 58.05 prevailing during the POI has been adopted by the Authority in this finding.

C. Scope of Product under consideration and like article:

6. The product under consideration in the original investigation was defined as “all kinds of plastic processing or injection moulding machines, also known as injection presses, having clamping force not less than 40 tonnes and not more than 1000 tonnes (clamping force), used for processing or moulding of plastic materials.” The following types of products are however, excluded from the scope of the product under consideration:

- i. Blow moulding Machines classified under Customs Tariff Classification No. 847730;
- ii. Vertical injection moulding machines;
- iii. All electric injection moulding machines wherein the mechanical movements such as injection, mould closing, mould opening, ejection, screw-drive, etc. are controlled by independent servo motors and having digital control system and without Hydraulic Unit;
- iv. Multi-colour/multi-mould machinery for making footwear, Rotary injection moulding machinery for making footwear and footwear sole/strap/heel injection moulding machine classified under the Customs Tariff Classification No. 8453.

7. None of the producers, exporters or importers of the subject goods has filed any questionnaire response. However, Engel Machines in its submissions, has argued that “Two Platen Design” of Engel machines (for up to 1000MT clamping force) has not been made in India by any company in the past and during the original period of investigation. One domestic manufacturer has started recently manufacturing machines with this design and manufactured very few

numbers. But those are of more than 1000 Tonne. Therefore, DA has to verify and exclude such category of machines which are not produced by the DI, from the scope of PUC.

8. In its post disclosure submissions Engel has further argued that the ‘two platen’ Design is an evolution of technology and is considered a milestone of machine performance in terms of several performance parameters and therefore, cannot be simply a feature as performance of these machines is much higher compared to all other designs. It has been further argued that all electric machines have been excluded from the scope of the investigation on similar technology improvement lines. It has been further argued that domestic machines are much cheaper compared to the Engel’s machines and therefore, import of Engels machines would not damage Indian Industry.

9. CPMIA, in its submission, has argued that the scope of PUC covers wide types of machines which highlight the chances of wrong calculations of dumping and margins claimed by the petitioners. Even certain types included in the scope of PUC are not produced by the petitioner. The Authority should exclude such types of PUC which has never been manufactured by the petitioner even after five years of duty from the scope of PUC.

10. The domestic industry, in its submissions, has argued that the present investigation being for sunset review of existing duties, the scope of the product under consideration remains the same as that of original investigations. In any case, the DA cannot consider generic statements made by the interested parties with regard to the scope of the product under consideration. Interested parties are required to identify a product type for which like article is not produced by the domestic industry.

11. The Authority notes that the present investigation being a sunset review, the product under consideration should normally remain the same as in the original investigation. It is also noted that the plastic processing machines are manufactured in various sizes and capacities described in terms of clamping forces. The domestic producers as well as the foreign producers manufacture different types of plastic processing machines with different clamping forces and different additional features and the machines with different capacities are used for moulding certain group of products. Domestic industry produces machines with different clamping forces and within those ranges the machines produced by the producers in the subject country are like articles and clearly technically and commercially substitutable. Therefore, these product types are *inter se* like products within their clamping force ranges and for the purpose of like to like comparison Plastic Processing Machines of different capacities/clamping forces were treated as different product types in the original investigation and comparisons were made on like to like basis to the extent possible. The same methodology is proposed to be used in the present investigation. Therefore, arguments of the interested parties that certain product types manufactured and supplied by them should be excluded are not tenable.

12. As far as the arguments of Engel Machines that ‘Two Platen’ Injection Moulding Machine should be excluded from the scope, the Authority notes that the issue was raised in the original investigation also and the Authority did not consider it necessary to exclude two plated injection moulding machines on the ground that the number of platens (2 platens or 3 platens) in the clamping unit of injection moulding machine is merely a physical parameter in one of the sub-assemblies (Clamping unit) of the injection moulding machine and therefore existence of 2 or 3 platens in the clamping unit does not result in different types of injection moulding machine. Therefore, the Authority did not recommend the exclusion of injection moulding machines on the basis of number of platens in clamping units. Engel has reiterated its arguments in the post disclosure submissions for exclusion of these machines on the grounds of improved performance and price differentials for but has not provided any evidence which could establish that these machines are not like articles to the subject goods in terms of physical characteristics, technical and commercial substitutability etc. Therefore, Authority does not find any reason to deviate from its earlier stand in this investigation. Accordingly, the Authority confirms the scope of the product under consideration as in the original investigation.

13. The definitive Anti-dumping Duty has been imposed by the Central Government vide Customs Notification No.39/2010-Customs dated 23rd March, 2010 under the Customs Head 8477.1000 of the first schedule of the Customs Tariff Act, 1975. The, customs classification is indicative only and not binding on the scope of the present investigation.

D. Domestic Industry and Standing:

14. The application for the review has been filed by Plastics Machinery Manufacturers Association of India (hereinafter referred to as petitioner or PMMAI) on behalf of the producers of Plastic Processing Machines in India. Four of its members,(i) M/s. Toshiba Machines; (ii) M/s. Ferromatic Milacron; (iii) M/s. Windsor India; and (iv) M/s. Electronica Machines, who are domestic producers of the product under consideration in India, and commanding over 90% of the total production of the subject goods in India, have provided relevant information in the application seeking continuation of anti dumping duty in force on imports of PPMs from subject country.

15. As per the records, it is noted that M/s. Ferromatik Milacron India Pvt. Ltd. is related to a Chinese company named M/s. Milacron Plastics Machinery (Jiangyin) Co. Ltd. It is also noted that M/s. Toshiba Machine (Chennai) Pvt. Ltd. is related to a Chinese producer namely M/s. Toshiba Machine (Shanghai) Co. Ltd. However, M/s. Toshiba Machine (Shanghai) Co. Ltd. is a group company and manufactures only electric injection moulding machines which is not a subject matter of proposed investigation.

16. The domestic industry has submitted that it is an established position of law that the Authority may, in its discretion, exclude a producer who is either related to the producer/exporter of the subject goods or imported the subject goods, within the scope of domestic industry. It has been submitted that though Ferromatic Milacron India Pvt. Ltd. is related to Milacron Plastics Machinery, China who manufactures the subject goods Milacron, China has not exported any of these machines to India and Milacron, India has not imported subject goods. Therefore, Ferromatic Milacron (India) and Toshiba Machine (Chennai) should be treated as part of the domestic industry.

17. CPMIA, in its submissions, has argued that as per information available in the public domain that Milacron India's relation to Chinese exporter falls under explanation (i) (b) of Rule 2 (b) under as both of them are directly or indirectly controlled by a third person i.e., Milacron LLC which is apparently based in USA. Therefore, the Authority should call detailed information from the concerned petitioner company to determine the nature of relation and their eligibility.

18. The Authority notes that though M/s. Toshiba Machine (Chennai) Pvt. Ltd. is related to M/s. Toshiba Machine (Shanghai) Co. Ltd., M/s. Toshiba Machine (Shanghai) Co. Ltd. manufactures only electric injection moulding machines, which is not a subject matter of proposed investigation. As far as M/s. Ferromatic Milacron India Pvt. Ltd is concerned, it is related to Milacron Plastics Machinery, China through common holding of Milacron LLC, USA. But Milacron, China has not exported the subject goods to India. Therefore, the Authority holds that these two domestic producers and petitioners are eligible to be treated as part of the domestic industry within the meaning of the term in the Rules and accordingly, all the four domestic producers as above have been treated as the domestic industry for the purpose of this investigation.

E. Other Issues raised by the domestic industry and other interested parties:

E.1 Submissions made by exporters/importers and other interested parties

19. The Authority notes that none of the exporters or importers has filed any questionnaire response. However, China Plastic Processing Machinery Association, in its submissions, has *inter alia* submitted :

- That CPMAI falls under the category of business association and all 38 members of the CPMIA are producers, exporters of the subject goods which fulfils the second condition in Rule to qualify them as interested party to this investigation;
- That CPMIA has offered full cooperation by providing rebuttals and relevant information to the Authority. EQR was not filed by its members because they did not export to India during POI or injury period;
- That Indian Antidumping Rules do not prescribe any format for filing questionnaire response by the Exporter's Associations. However, CPMIA has provided relevant information such as capacity in China, demand, third country export volume, price, etc. in its written submissions and offered the same for verification;
- That Haitian is a member of CPMIA and CPMIA's submissions are relevant and applicable to Haitian also;
- That the domestic industry has not mentioned in the transaction-wise imports data whether such information pertains to PUC only or covers all the transactions including non-PUC items reported in a particular customs subheading;
- That according to CPMIA petitioners have provided only non-PUC items in transaction wise data; apart from the said data they identified imports of 42 machines to be PUC during the said POI;
- That the Members of CPMIA have not exported the subject goods to India during the POI. This alone puts the credibility of import statement submitted by the petitioner in question. Therefore, the petitioner should be directed to show which transactions are identified as the product under consideration. Unless such transactions are identified and earmarked in the raw data itself CPMIA and also the Authority would not be in a position to examine the authenticity of the claims of the petitioner with regard to their claims of import;
- That the application does not contain information to satisfy the conditions set out in Rule 23. The information available in the application clearly shows that the expiry of the duty is not likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry;
- That CPMAI has provided relevant information to show that there is no excess capacity in China PR. The industry is operating above 90% capacity utilisation;
- That excessive confidentiality maintained by the DI which is against the provisions of AD Rules. Therefore, Authority should not to allow the claim of the petitioner to treat weighted average cost and price information cumulatively for the domestic industry as confidential.

20. Apart from CPMIA, M/s. Engel Machinery India Pvt. Ltd., in its brief submission on behalf of Engel Machinery (Shanghai) Co. Ltd, China and Engel Machinery (Changzhou) Co. Ltd. China, has *inter alia* argued

- That Engel machines are designed and manufactured at its main factory in Austria. They are also assembled in Asia at the above mentioned factories but most engineered components are manufactured in Western Europe (Engel Austria, Germany, etc);
- The two platen design of Engel machines for up to 1000MT has not been made in India by any company in the past and during the original period of investigation. One domestic manufacturer has started recently manufacturing machines with this design and manufactured very few numbers but that is more than 1000MT;
- That in no way Engel export to India causes injury to the local industry. Our export prices are at least 50% higher than the Indian manufacturers. This is due to a very high content of components designed and made in Western Europe (Engel Austria, Germany etc);
- That Engel machines from Engel factory in China to India till date have been all above 1000MT. However, under the Government of India “Make in India” campaign and the entry of Top line Global producers to India, there will be demands for high performance machines also in the below 1000 MT sizes;
- Engel machines feature precision, high performance and technology orientation. Customers who require this value addition are prepared to pay the premium but again to pay on top anti dumping duty is very difficult for the customers;
- That Engel would like to export machines below 1000MT from China but due to the antidumping duties it is quite impossible to do so;
- That Price difference in between Engel Machinery Austria & Engel Machinery Shanghai or Engel Machinery Changzhou, China is approx. 15-20% this is just because of overhead cost is much higher in Austria than in China;
- That Engel Machinery China plant assembly capacity for below 1000 MT machines per annum is 380 machines, whereas China domestic market requirement for below 1000 MT machines per annum is about 28,350 machines;
- That Engel Machinery had started assembling in China in 2007 to focus on entire Asia market and not only in China market. This is to cater for the Asian market in a better way;
- That Engel has over 30 fully owned subsidiaries worldwide and the business is run on a professional and transparent SAP based accounting and management platform where pricing is uniform and published in English. The price list used in all of Asia is also the one used in India and China and the pricing is fixed by the headquarter in Austria;
- Therefore, Engel Machinery (Shanghai) Co. Ltd, China and Engel Machinery (Changzhou) Co. Ltd., China should be exempted from the antidumping duty.

E.2 Submissions by the Domestic Industry:

21. The domestic industry, in its various submissions, has refuted the arguments of the other interested parties and has *inter alia* submitted:
- That the Chinese Association should not be treated as an interested party as it has not preferred to make its members to cooperate with the Authority and file questionnaire response. Not only the Association preferred not to give any information relevant to the investigation; but also, the Association made false and misleading statement that there were no exports of the PUC from China to India during the relevant period;
 - The Authority had specifically raised certain queries to the Association at the time of hearing regarding their membership, production and capacity and exports to third countries etc. which they have miserably failed to provide. CPMIA has also not filed any meaningful information, except certain estimation/information about the production and capacities, demand of the subject goods in China and exports from China, without any supporting documents.
 - That the petitioners have provided complete list of imports which includes not only the PUC but also non PUC and therefore, complete information is available in the petition;
 - That nothing excessive has been claimed confidential by the petitioners. The petitioners have provided sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis;
 - That Haitian, one of the major producers in China, who had cooperated with the Authority in the original investigation, has preferred not to file any response in the present investigation. This is despite the fact that Haitian is claiming to set up assembly line facility in India and is engaged in production of PUC in Vietnam, one of the countries under the investigation. Evidently, Haitian has set up assembly line facilities in Vietnam to avoid anti

dumping duties imposed on China and now setting up assembly line operation in India to avoid anti dumping duties that may be imposed by Vietnam;

- That the Chinese demand calculated by Engle is substantially different from demand claimed by the Association. This clearly shows that the parties are not bringing verifiable facts before the Authority and are giving misleading information;
- That if Engle considers that the goods are of Chinese origin, reference to Western Europe is irrelevant and if goods are substantially Western Europe origin and are being assembled in China, the cost and price cannot be as low as the price at which goods are being imported from China;
- In response to Engel's submissions the domestic industry has argued that no response, in the form and manner prescribed, has been filed by the exporter. The Designated Authority cannot consider a claim merely based on statements. Even if it is considered that the exporter has not exported the product under consideration to Indian market, even then, the exporter is obliged to file questionnaire response in the form and manner prescribed by the Authority. In the absence of questionnaire response in the form and manner prescribed containing information for the POI for exports to India as well third countries and duly supported by market economy questionnaire response, the Designated Authority cannot consider whether dumping and consequent injury to the domestic industry is not likely from exports by the company;
- That despite the existing anti dumping duty, the Indian industry could not get fair market opportunity with the imposition of anti dumping duty and the Indian market continued to witness dumped imports. Difficulties for the domestic industry got compounded by the decline in demand for the product in the Country. Under these circumstances, cessation of present anti dumping duty would result in continuation/intensification/recurrence of dumping of subject goods from subject country.

22. Further to the above, the domestic industry, in its comments to the first disclosure statement, has submitted that the Authority should provide conclusions in the disclosure statement based on facts and evidence provided by the interested parties.

E.3 Examination by the Authority:

23. The Authority notes that China Plastic Processing Manufacturers Association (CPMIA) is a business association of Chinese producers, exporters of the subject goods with a membership of 38 members. However, none of its members has filed any questionnaire response. The Association has also not filed any meaningful information, except certain estimation/information about the production and capacities, demand of the subject goods in China and exports from China, without any supporting documents, to help the Authority in various determinations.

24. Notwithstanding the above, the issues raised by the Association with regard to the investigation have been noted. The Authority has examined the import data as per the import statistics available with it to exclude products other than the products under consideration for various determinations. The product under consideration has been identified from the transaction-wise data to the extent it was feasible based on the descriptions and other details and therefore, the concerns of the other interested parties have been adequately addressed. However, the claims of the Association that the subject goods have not been exported from China is also not borne out of the evidence on record as the import statistics examined by the Authority shows that 17 machines have been imported from China during the POI. The data has also been placed in the Public File.

25. As far as confidentiality issues are concerned, the Authority notes that Information which are confidential in nature and provided by the interested parties on confidential basis have been treated so wherever warranted after due examination of the confidentiality claims as per the general practice followed by the Authority. To the extent possible, parties providing information on confidential basis are directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. Therefore, the concerns of the interested parties have been adequately addressed.

26. As far as submissions of Engel Machine, China is concerned, the Authority notes that it has so far exported only machines above 1000 MT clamping force, which are not the subject goods in this investigation. Therefore, they are not exporters of the subject goods to India at the moment. The submissions of exemption in anticipation of exports in future cannot be considered. There is a separate provision of new shipper review under the Rules which they may avail if they wish to export the subject goods in future. Therefore, other submissions made by them do not merit consideration at this moment.

27. As far as the arguments of the domestic industry that the disclosure statement should also contain conclusions drawn by the Authority based on the facts and evidence provided by the interested parties the Authority notes that the Rule 16 of the Rules provides that before giving its final findings the Authority shall inform all interested parties of the essential facts under consideration which form the basis for its decision. Therefore, the disclosure statement contains all essential facts and the methodologies proposed to be adopted by the Authority. Final conclusions are drawn after getting the comments of the interested parties to the disclosure. Since conclusions are not drawn at the stage of the disclosures, it cannot be a part of the disclosure statement.

28. All other submissions made by the interested parties with regard to dumping and injury determination etc. have been addressed in their respective sections in this finding.

F. Determination of current Dumping and likelihood of continuation or recurrence of dumping:

F.1 Legal Positions

29. Section 9A (5) of Customs Tariff Act, 1975 provides that:-

"The anti dumping duty imposed under this Section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition:

Provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension;

Provided further that where a review initiated before the expiry of the aforesaid period of five years has not come to a conclusion before such expiry, the Anti dumping duty may continue to remain in force pending the outcome of such a review for a further period not exceeding one year."

30. Accordingly, a sunset review investigation is to examine:

- Whether the dumping continues after imposition of the antidumping duty and if so, whether it is likely to continue;
- In cases where dumping did not continue, whether the dumping would recur in the event of revocation of anti dumping duties;
- Whether the domestic industry continued to suffer material injury and if so, whether injury to the domestic industry is likely to continue if the duties are removed;
- In cases where the domestic industry has not suffered continued injury, whether injury to the domestic industry is likely to recur in the event of revocation of anti dumping duties.

31. Therefore, the Authority has first proceeded with the examination whether dumping of the subject goods continues from the subject countries and whether the domestic industry continues to suffer material injury on account of such dumped imports before examining whether dumping is likely to continue or recur if the duties are revoked, and injury is likely to continue or recur in such a situation.

F.2 Examination of Continuation of Dumping: Determination of Normal Values, Export Prices and Dumping Margins:

32. The Authority notes that none of the exporters of the subject goods from China has submitted any questionnaire response for determination of Normal values and export price of the subject goods from that country. Only the CPMIA and the responding importer have argued that the Designated Authority should resort to type wise comparison for a like to like comparison in order to determine injury and dumping margin.

33. The domestic industry, in its submissions, has argued that China being a non market economy, normal value of the subject goods cannot be determined on the basis of price prevailing in that country and therefore, needs to be constructed. With regard to determination of a normal value in China the domestic industry, has inter alia argued that market economy status cannot be granted unless the responding exporter/company and its group as a whole make a claim. In the present case, there is no claim for market economy treatment. None of the Chinese exporters have filed questionnaire response, nor claimed market economy treatment. In the original investigations, the Authority had not granted market economy treatment to any of the exporters from China and determined the normal value in China on the basis of the constructed normal value based on the estimated cost of production of the subject goods in China with reasonable profit in terms of Para 7 & 8 of the Annexure 1 to the said Rules as amended. Therefore, the petitioner has argued that the Authority should consider the same methodology to calculate the normal value for China PR in the current investigation.

34. It has been further argued by the domestic industry that under the above circumstances the normal value in China can be determined on the basis of (a) price in India, and (b) cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses and profit.

35. The petitioners, in their petition, have provided estimates of separate normal values of machines having different clamping forces (product types) based on the methodology adopted in the previous determination of the Authority and have submitted that the Authority had examined the issue in detail in the previous investigation and had concluded that dumping margin determination at weighted average level would not be appropriate in this case and therefore, dumping margins were determined in that case at product type level for each different clamping force. There is no challenge to the final findings notified by the Designated Authority before CESTAT. Therefore, determination methodology adopted earlier has been validated.

36. None of the producers/exporters from China have cooperated with the information in the form and manner prescribed. The domestic industry has further submitted that even if it is considered that there was no export by a company to India, the same does not imply that the company need not file questionnaire response. The company is still required to file questionnaire response, as it is both actual dumping and likelihood that are important in a sunset review. Domestic industry argues that exporters from China PR are continuing to dump the subject goods in the Indian market and the dumping margins are significant and above *de minimis* levels.

37. CPMIA, in its submissions before the Authority, has argued that the allegation of significant dumping margin coincided with low volume is an unfounded claim. Correcting the import data would show no import from China PR. Based on this alone there is no case for continued dumping made up by the petitioner. CPMIA has further argued that the Authority should subject the type wise comparison/determination of dumping margin and injury margin to very strict scrutiny. A fair and accurate comparison of PUC type wise to like article type wise will show negative dumping and injury margin in the present case;

38. In its comments on the first disclosure statement CPMIA has brought certain discrepancies in the import data adopted in the first disclosure. It has been pointed out that the disclosure statement shows an import of 17 PPMs from China PR during the POI at an average CIF price of Rs10, 59,453/- per machines. The import data shows consistent increase in price between base year and immediate previous year to the POI and thereafter a huge dip in price during the POI and once again significant increase in the immediate post POI period. It has been submitted that closer scrutiny of the transaction-wise import data by them clearly shows many of such transactions are not of PUC and various Non PUC items have been wrongly construed as PUC and this has resulted in unusually low import price for the PUC during the POI and the dip only during the POI is also very notable and the same needs to cured.

39. In this connection CPMIA has submitted the product catalogues of the respective machines, as available in the website of the manufacturers in respect of few machines, to establish that the machines are either very small capacity machines or are components or sub-assemblies of the machinery and not the product under consideration.

40. In view of this positive evidence provided by the interested parties the import data used for determination have been subjected to further scrutiny and it is found that machines identified as having clamping force 60, 75 and 100 MT in the earlier disclosure are actually machines with clamping forces of 1 to 2 MT or components. Therefore, the data has been corrected and the pruned import list has been used in this disclosure.

F.3 Examination by the Authority and Determination of Normal Values:

41. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption that China PR is a non-market economy country and advised the producers/exporters in China to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of their market economy status. The Authority sent copies of the MET questionnaire to all the known producers/exporters for rebutting presumption of non-market economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the Rules. The Authority also requested Government of China to advise the producers/exporters in China to provide the relevant information. However, none of the Chinese producers/exporters has filed response. The Authority notes that in the past years China PR has been treated as a non-market economy country in anti-dumping investigations by India and other WTO Members. In view of the above position and in the absence of rebuttal of non-market economy presumption by any Chinese exporting company, the Authority considers it appropriate to treat China PR as a non-market economy in the present investigation and proceeds with para-7 of Annexure-I to the Rules for determination of normal value in case of China PR. Para 7 of Annexure I of the Anti-dumping Rules provide that:

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."

42. Authority notes that none of the interested parties have provided any meaningful information for selection of an appropriate third country as a surrogate for construction of the normal value on the basis of cost and prices in that country or price from such country to other countries, including India as the normal value in China as per the first two alternatives in the Para-7 referred above. The Authority further notes that the product under consideration includes a number of product types, corresponding to different clamping forces. In view of the above, it is not appropriate to determine the Normal Value of the product based on the import price from third countries to India or a surrogate country without their cost and price details for the product types identified. Hence prices from no other country could be adopted for determination of the Normal value in China as per the above provision. Therefore, the Authority finds it appropriate

to determine the normal value of the product in China as per the third alternative provided in the Rules referred above. Thus, the Authority has constructed the normal values of each product type by taking into account cost of production in India plus a reasonable profit as per its consistent practice.

43. The Authority notes that the associated costs and prices of machines with different clamping forces vary depending upon the clamping force and configurations. The different types/ sizes however, do not establish that they are not like products. Only below mentioned product types/ machines with different clamping forces have been imported to India during the POI. Therefore, for fair comparison on like to like basis the Normal Values have been determined for these product types. Wherever the domestic industry did not produce a matching product type with identical clamping force a conservative approach has been adopted by determining the normal value based on the cost of the machine with nearest lower clamping force to enable like to like comparison after making due allowance for any differences that affect price comparability.

44. Accordingly, the constructed normal values for each product type imported during the POI from China have been determined as follows:

Product Types/ Clamping Force (Tons)	Constructed Normal Value (CNV)	Constructed Normal Value CNV
	Rs Per Piece	(US\$/ Piece)
120	****	****
125	****	****
128	****	****
150	****	****
380	****	****

F.4 Export Prices:

45. As none of the exporters of the subject country has provided any information that can be used for determination of the export price, the Authority proposes to determine the export prices for all exporters from subject country on the basis of CIF price of imports to India as per DGCI&S data. In this regard the Authority has noted the arguments of the interested parties that the product under consideration should be appropriately identified. The DGCI&S data has been carefully examined and only those machines which fall within the definition of the product under consideration have been taken into consideration for dumping margin and all other determinations.

46. Accordingly, export prices from the China PR have been determined on the basis of CIF price of product types with comparable clamping forces from the DGCI&S data with applicable adjustments for Ocean freight, Marine insurance, Port expenses, Commission, Inland transportation and Bank Charges as per best information available, in the absence of concrete information from the respective exporters in the subject country, to arrive at the ex-works prices as follows:

Product Types/ Clamping Force (Tons)	Numbers	Export Price (Rs) Per Machine	Export price (USD) Per Machine
120	8	****	****
125	1	****	****
128	2	****	****
150	1	****	****
380	1	****	****
Total/Weighted average	13	****	****

F.5 Dumping Margins:

47. For the purpose of determination of dumping margin for the product as a whole first dumping margins at product types level have been worked out by comparing the ex-works normal values constructed as above for individual product types with the corresponding ex-works export prices at the same level of trade. Thereafter weighted average dumping margin has been worked out for the product as whole as follows:

Product Types/ Clamping Force (Tons)	No of Pieces	Constructed Normal Value (US\$/ Machine)	Ex-Works Export Price US\$/ Machine	Dumping Margin US\$/Machine	Dumping Margin %
120	8	****	****	****	
125	1	****	****	****	
128	2	****	****	****	
150	1	****	****	****	
380	1	****	****	****	
Total/Weighted Average	13	****	****	****	55-65%

48. The above assessment indicates that the subject goods continue to enter the Indian market, from China PR, at dumped prices and the margin of dumping is significant though the volume is low.

49. The Authority has also assessed the likelihood for continuation or recurrence of dumping of the subject goods as follows:

G. Likelihood of Continuation or Recurrence of Dumping:

50. Having determined that the subject goods are being exported from the subject country at dumped prices the Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of dumping in the event of revocation of the duty.

G.1 Views of the Domestic Industry:

51. The domestic industry, in its various submissions, has inter alia argued:

- (a) That according to News Reports, Haitian International Group, China, one of the leading producers and exporters of these machines in China has delivered a record injection moulding machines in recent years. In 2012 the Haitian delivered about 22,000 machines. Approximately 32.2% of sales was for export to over 130 countries;
- (b) That global demand for plastics processing machinery is forecast to rise by 6.0% annually, reaching USD 28.9 billion in 2015, reversing the declines experienced in the 2005 to 2010 period. As per this forecast China is projected to account for over 40% of all additional global demand up to 2015 as gains in developing nations become the driving force for plastics processing equipment market growth;
- (c) That Haitian has set up assembly line facilities in Vietnam to avoid anti dumping duties imposed on China and is now setting up assembly line operation in India to avoid anti dumping duties that may be imposed by Vietnam
- (d) That if the Chinese producers do not have any surplus capacities, their producers would not have undertaken assembly line operations in India; nor the Association or the Embassy would have contested the present proceedings.
- (e) That the Chinese association, at the time of hearing, stated that the Chinese production was about 30,000 machines and domestic consumption was about 25,000. This is simply not possible when production of one company alone in the recent period must be more than 30,000 machines. Evidently, the association made a misleading statement at the time of hearing.
- (f) That China is a largest producer and exporter of the product under consideration and the producers in China are holding huge surplus production capacities and the Chinese producers are highly export centric;
- (g) The Govt. of China and the Association claimed that there is no surplus capacity available in China and the current demand in China and third countries are sufficient to meet the current capacities of the industry. If that is true the Chinese producers would not have undertaken assembly line operations in India; neither the Association nor the Embassy would have contested the present proceedings. Evidently, the investigation is being opposed only with a view to intensify dumping in the Indian market;
- (h) That China's position as one of the biggest producer of subject goods in the world coupled with India's position as a lucrative, rapidly growing market for subject goods makes the situation ripe for increased dumping in India from China;
- (i) That Chinese demand calculated by Engle is substantially different from demand claimed by the Association. This clearly shows that the parties are not bringing verifiable facts before the Authority and are giving misleading information;

- (j) That on the one hand, Engle and the Association has claimed that there are no imports from China. On the other hand, Engle has claimed that its price list is the same for India and China. The argument is clearly contradictory
- (k) That Dumping Margin determined in previous investigations and present petition are significant and clearly shows likelihood of continuation of dumping in the event of cessation of anti dumping duty;

52. Disputing the claims of the Govt. of China and CPMIA that there is no excess capacity available in China and the current demand in China and third countries are sufficient to meet the current capacities of the industry, the domestic industry in its comments to the first disclosure has argued that had that been the case the Govt. of China and the Association would not have opposed this proceeding and the producers from China would not have set up assembly line in India. The investigation is being opposed with a view to intensify dumping.

53. The domestic industry further argues that while the representatives of Association informed the Designated Authority at the time of hearing that the production of PUC in China was about 30000 machines and the domestic consumption was about 25000 machines as against the figures submitted by the Association which indicates production of PUC in China as 78,998 Nos and Capacity as 86000 Nos. Such huge deviation in the information provided by the Association during the public hearing, where the petitioners were present, compared to the information provided to the Authority, which was not provided to the petitioners; clearly indicates the intentions of the Association to misguide the petitioners and Designated Authority. Therefore, the Authority should discard such information and treat the Association as non cooperative.

54. The domestic industry further argues that it would be seen from the information provided by the Association that there exist excess capacities in China and the demand in China is only 80% of the total available capacities. With demand in India to be only 2,760 Nos, China can easily cater the whole demand in India and at the same time exports to other countries. In the event of revocation of anti-dumping duty, producers and exporters are likely to utilize their excess capacities to export to India.

G.2 Views of other interested Parties:

55. CPMIA, in its post-public hearing submissions has provided the following information as best available information with them to show no likelihood or recurrence of dumping and injury in the event to expiry of present duties.

Sl. No.	Particulars	POI Annualized	POI (15 Months)
1	Demand for the Product in China	Volume in Nos	Volume in Nos
	Domestic Sales by members of CPMIA	****	****
	Domestic Sales by non members of CPMIA (Estimated)	****	****
	Imports from other countries to China (Estimated)	****	****
	Total	68,310	85,388
2	Capacity for the Product in China		
	Capacity of the members of CPMIA	****	****
	Capacity of non members of CPMIA (Estimated)	****	****
	Total	86,000	1,07,500
3	Production of the Product in China		
	Production by members of CPMIA	****	****
	Production by non members of CPMIA (Estimated)	****	****
	Total	78,998	98,747
4	Export to India during POI		
	Exports by members of CPMIA	Nil	Nil
	Exports by non members of CPMIA	Nil	Nil

5	Exports to other countries during POI		
	Exports by members of CPMIA	****	****
	Exports by non members of CPMIA	****	****
	Total	12,598	15,748
6	Export Price to Third Countries		
	Export value as per members of CPMIA US\$	****	****
	Average Exports price as per members of CPMIA US\$ per machine (FOB China PR)	****	****
7	Capacity Utilization	92%	92%

56. CPMIA has argued that the above data shows that there is no excess capacity in China PR. The industry is already operating at above optimal levels and also entire Chinese domestic demand is not met by the Chinese producers alone. There are imports of the same product into China. Any claims of probabilities of increasing capacity utilization beyond the present levels would be nothing short of an absurd and skewed argument. Importantly, the prices offered to third countries would be much higher than the net sales realisation and non-injurious price of the domestic industry at the landed levels in India. There is no reason whatsoever for the Chinese producers to sell their goods at a price less than what they are achieving in other countries.

57. CPMIA further argues that the above data clearly shows absence of any excess or surplus capacity or low priced exports to third countries which can be diverted to India in the event of revocation of anti dumping duties. This when seen along with the robust position of the domestic industry, rules out even the minute possibility of likelihood or recurrence of dumping and injury in the present case.

58. In response to the first disclosure statement issued by the Authority CPMIA has reiterated its arguments that the Chinese producers are operating above optimal level and they are achieving higher price in third countries. Since the petitioner's data itself shows decline in domestic demand in India, it cannot remain lucrative for the Chinese exporters even by a figment of imagination.

G.3 Examination by the Authority:

59. The Authority notes that though the volume of imports from China has dropped significantly during the investigation period and volume of import during the POI is low, the estimated dumping margin based on the import data is substantial. Therefore, Authority has examined the likelihood of continuation of dumping of the subject goods taking into account facts available before it and as per the above submissions of the Domestic industry and the other interested parties.

60. The Authority notes the submissions made on behalf of the CPMIA and the domestic industry. CPMIA has provided certain information about the production capacities, production volumes and demand of the plastic processing machines in China purportedly based on the data of its members and estimated figures for the non-members. But these figures are not supported by any evidence and without breakup of various capacities to examine whether the figures pertain to the product under consideration in this investigation or not. However, even this aggregate data indicates that Chinese Capacity is approximately 26% higher than the domestic demand as indicated by CPMIA and about 16% of the total production is being exported. There are also about 10% spare capacities, though the Association claims that the industry is operating at optimal level. Therefore, availability of capacity to export and export orientation is visible even in the data provided by the Association. Moreover, data in respect of M/s. Haitan, one of the major producer and exporters of these Machines in China, available in public domain, indicates that this group delivered about 27,000 machines in 2013, far exceeding previous year's figure of 22,000 and their exports have exceeded 32% mark. This indicates export intensity of the Chinese producers.

61. Further the price level of exports to third countries, as an indication of future price to India, indicated by the Association is at the gross level. The product under investigation covers a wide range of capacities with wide price variation. Therefore, the information on the price level provided by the Association at the gross level do not provide any meaningful understanding of the likely price scenario of export of the goods to India. The import data analysed by the Authority indicates that few machines of different sizes have been imported into India from China during the POI and the prices as per the import statistics indicates that these goods are entering the Indian market at much lower prices and the exports were found to be at dumped prices. Therefore, there is reasonable indication that if the duties are removed the Chinese producers shall be able to export more machines to the Indian market at similar price levels. Further, the post POI import data examined by the Authority shows a significant increase in import in that period. Considering all these aspects the Authority is of the view that the dumping is likely to continue or recur if the duties are removed.

H. Determination of Injury and Causal Link; and Likelihood of Continuation or recurrence of Injury to the domestic industry:

H.1 Legal Position

62. As stated in the previous sections in a sunset review investigation, with regard to injury examination the Authority is required to examine:

- Whether the domestic industry continues to suffer injury due to dumped imports and if so, whether injury to the domestic industry is likely to continue if the duties are revoked; or
- In cases where the domestic industry has not suffered continued injury, whether injury to the domestic industry is likely to recur in the event of revocation of anti dumping duties.

63. Therefore, the Authority first proceeds with the examination whether the domestic industry continues to suffer material injury on account of dumped imports from the subject country. Thereafter, the likelihood of continuation or recurrence of injury to the domestic industry, in the event of revocation of the duties from the subject country, has been examined. Examination of material injury to the domestic industry is in accordance with the manner as laid down under Article 3 of the AD Agreement and Annexure II to the AD Rules, 1995.

H.2 Examination of Current injury to the domestic industry and Causal Links:

H.2.1 Submissions by the domestic industry

64. In their various submissions regarding injury and causal links the domestic industry has *inter alia* submitted:

- i. That the entire purpose of the review inquiry is not to see whether there is a need for imposition of anti-dumping duty but to see whether in the absence of continuance of the duty dumping would continue and the domestic industry would suffer injury;
- ii. That after the imposition of anti-dumping duty on imports of product under consideration from China; Malaysia, Philippines, Taiwan and Vietnam started dumping the product under consideration into India. The domestic industry has filed an application seeking imposition of anti dumping duties on imports from these countries and the Designated Authority is at present conducting investigation though the scope of product under consideration in other petition under investigation includes much higher tonnage machines as well;
- iii. That the demand for the product under consideration has declined over the injury period. Auto sector growth has declined by about 16%, due to which the machines used in this sector are idle. Resultantly, these machines are being used for packaging and other sectors. Thus, while decline in demand in auto sector has led to lower demand in this sector, at the same time, it has triggered a decline in demand in other sectors as well;
- iv. That low volume of imports during the current period is due to (a) imposition of anti dumping duty on one hand and (b) ability of major Chinese producers to export from other countries by setting up facilities in other countries;
- v. That the performance of the domestic industry has not improved despite existence of anti-dumping duty due to continued presence of dumped imports from China PR and other countries in the Indian market;
- vi. That the Domestic Industry enhanced its capacity in the years 2011-12 and further in 2012-13 in anticipation of growth in the market keeping in view the projections. However, unfortunately, demand for the products being produced by the consumers saw a significant decline, as a result of which demand for product under consideration declined significantly in the last four years;
- vii. That with continuous presence of dumped imports in the Indian market the domestic industry, in order to sustain in the market, were left with no option but to sell the goods at sub-optimal prices. The domestic industry was prevented from raising its prices in proportion to increase in costs;
- viii. That the Imports were significantly undercutting the prices of the domestic industry. Further, the imports were depressing the domestic prices;
- ix. That the performance of the domestic industry deteriorated in terms of production, domestic sales, capacity utilization, profits, return on investments, cash flow. Consequent impact of dumping on the domestic industry has been significantly adverse.
- x. That the domestic industry has suffered injury during the relevant period. The mere fact that injury to the domestic industry in the current period is because of dumped imports from other countries does not imply that injury to the domestic industry from China is unlikely in the event of cessation of anti dumping duty;

- xi. That the imports from China are lower than import price from countries under investigation at present and third countries. This clearly establishes that the domestic industry shall suffer significant intensified injury in the event of cessation of anti dumping duties.
- xii. That PUC is a capital goods item and therefore, the domestic industry is required to plan its capacity expansion keep future outlook. All future projections at that point in time were showing promising future outlook. However, demand for the product has declined significantly and therefore the domestic industry is now suffering injury both from dumping from other sources as also decline in demand.
- xiii. That if there is no demand for a particular type, it follows that the domestic industry shall not produce the product. If there is a demand for product in the country in future, the domestic industry shall cater to the same appropriately;

H.2.2 Submissions by producers/exporters/importers other interested parties

65. The other interested parties, in their submissions, have argued

- i. That no injury or continued injury has been caused to the domestic industry on account of the alleged dumped imports from China PR.
- ii. That DA should examine whether there are continuous imports during the POI from China PR, thereby causing any injury to the Domestic industry. As per the information in the petition the Imports have declined from 949 to 42 machines in present POI. Though the demand of the subject product has significantly increased during present POI in comparison to POI of original case, in comparison to base year i.e., 2010-11 the demand has declined from 3,634 to 2,794 machines. The decline in demand is about 23%.
- iii. That the capacity of the domestic industry has gone up by 647% during present POI in comparison to POI of original case and increased by 34% in comparison to base year 2010-11 while the demand has declined by about 23%. Further DI production has declined to 12% during present POI. Capacity utilization of DI has declined during the POI because of huge increase in plant capacity.
- iv. That the sales volume of the domestic industry in domestic market during present POI has significantly increased as compared to POI of original case. But in comparison to base year 2010-11 it was declined by 18%. However, during the same period demand was declined by 23%. Therefore, there is no continued injury to the domestic industry due to alleged dumped imports.
- v. That as per the petition net sales realization of domestic industry has been higher than non injurious price. Therefore, there is no continued material injury to the domestic industry according to its own claims.
- vi. That information available in the petition shows that the performance of the domestic industry showed declining trends when the alleged imports from China PR were almost negligible and nonexistent and Chinese imports are attracting AD duties as high as 174%. Even the third country import prices (major countries such as Vietnam and Taiwan) were much higher than the prices offered by domestic industry. If the domestic industry was still suffering material injury, then the reason for that has to be something other than imports of subject goods into India. Thus, there is no nexus between imports of PUC into India and performance of domestic industry.
- vii. That injury, if any, is due to other reasons such as decline in demand, huge surplus capacity with the petitioner vis-à-vis Indian demand etc and any effort to attribute injury or likely injury on account of other reasons to imports from China PR should be turned down by the Authority.
- viii. That DA should make type wise comparison in order to determine injury and dumping margins.

66. In their comments to the first disclosure statement issued by the Authority the CPMIA has argued that the domestic prices are unaffected by the landed price of PUC claimed by the petitioner as is evident from the disclosure statement. It has been further argued that that the domestic industry's performance has increased significantly even though the demand for the product has shown some declines over the years. The selling price of the domestic was higher than the non injurious price as per disclosure statement which establishes there was not any price injury to the domestic industry.

H.2.3 Examination by the Authority

67. In the light of the various submissions made by the domestic industry the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of injury on account of dumped imports from the subject country.

68. Rule 11 of Anti-dumping Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the

consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....” In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

69. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, the Authority considers indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. in accordance with Annexure-II of the rules supra.

70. For the purpose of current injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any.

71. The Authority notes that the subject goods are at present attracting anti-dumping duty from the subject country and anti-dumping investigations have been initiated for alleged dumping of the plastic processing machines with a wider capacity ranges from Malaysia, Philippines, Taiwan and Vietnam. The authority has, therefore, considered the volume and price impact of imports from the subject country along with other sources for determination of injury and causal link, including the likelihood scenario, if the anti-dumping duties are withdrawn in respect of the subject country. Accordingly, the volume and price effect of dumped imports have been examined to assess the impact of current as follows:

(a) Volume effect of dumped imports and impact on the domestic industry

(i) Import Volume & Share of the subject country

72. The Authority notes the arguments of other interested parties that there is no export of the subject goods from China during the POI. For examination of the volume and prices of the imports from various sources the Authority has relied upon the transaction wise data from DGCI&S and individual transactions have been examined based on the product descriptions to identify the product under consideration. As per this examination the summarised import data for subject goods during the injury period are as follows:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI (Oct12-Dec13)	POI (Annualized)	Share in Imports (POI) %	Jan-Jun 14 (Post POI) Annualized
Subject country China PR	Nos.	73	23	26	13	10	1.06%	40
Countries under investigation	Nos.	194	315	374	488	390	39.97%	368
Malaysia	Nos.	102	87	107	134	107	10.97%	122
Thailand	Nos.	19	0	0	11	9	0.90%	2
Vietnam	Nos.	0	77	226	248	198	20.31%	174
Philippines	Nos.	73	151	41	95	76	7.78%	70
Other Countries	Nos.	1235	1090	637	716	573	58.97%	482
Total Import	Nos.	1502	1428	1037	1,217	974	100.00%	890

73. The above data indicates that contrary to the claims of the other interested parties, there are imports of subject goods from China PR during the injury examination period, including the POI though the numbers have declined. However, there is significant import during the same period from Malaysia, Thailand, Vietnam and Philippines against which separate ant-idumping investigations are in progress.

(ii) Demand and Market Share

74. The demand and market share of the domestic industry and the subject country in the subject goods in India has been assessed taking into account the production and sales of the domestic industry and imports.

Demand	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI (Oct12- Dec13)	POI (Annualized)	Jan-Jun 14 (Post POI) Annualized
Sales of Domestic Industry	Nos.	1,990	1,940	1,737	2,026	1,621	1934
	Trend	100	97	87		81	97
Sales of Other Indian Producers	Nos.	199	194	174	203	162	193
	Trend	100	97	87		81	97
Subject country	Nos.	73	23	26	13	10	40
	Trend	100	32	36		14	55
Countries under investigation	Nos.	194	315	374	488	390	368
	Trend	100	162	A92	251	201	190
Other Countries	Nos.	1235	1090	637	716	573	482
	Trend	100	88	52	58	46	39
Total Demand/ Consumption	Nos.	3,691	3,562	2,948	3,446	2,757	3,017
	Trend	100	97	80		75	82

75. The above data indicates that during the period of investigation the demand and sales of domestic industry for product under consideration have started declining since 2012-13 and there is a significant fall in demand by about 25% in POI compared to the base year. Volume of imports of product under consideration from the subject country has also declined over the years. However, there is a sudden drop in imports from the subject country in 2011-12 apparently due to the impact of antidumping duty as trend in imports from other sources do not show any significant drop in that year. There is a drop in sales of the domestic industry as well as other domestic producers by about 20% compared to the base year which seems to be due largely to the impact of decline in demand.

76. As far as the demand scenario is concerned, the domestic industry has submitted that the demand of the subject goods have been adversely affected by the general economic slowdown and specifically the demand glut in the auto component industry sector during the last few years, which is one of the largest users of these machines. However, this being a global phenomenon, the plastic processing machine industry everywhere is under pressure and therefore, dumping has started from several sources to use up these capacities. A significant part of the demand has been occupied by dumped imports from several sources, including the subject country.

77. The general trends in demands have been examined along with the trend in market share of various players in the domestic market.

Market Share	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI (Annualized)	Jan-Jun 14 (Post POI) Annualized
Sales of Domestic Industry	%	54%	54%	59%	58.8%	64%
Sales of Other Indian Producers	%	5%	5%	6%	5.9%	6%
Subject Country	%	2%	1%	1%	0.4%	0.5%
Countries under investigation	%	5%	9%	13%	14.2%	14%
Other Countries	%	33%	31%	22%	20.8%	16%
Total Demand/ Consumption	%	100%	100%	100%	100%	100%

78. The above data indicates that the market share of the domestic industry has increased during the POI as compared to the base year though in absolute term the sales have substantially declined. This aberration is due to the decline in demand. The volume of import from the subject country and its market share during the injury investigation period is insignificant. The market share vacated by the subject country, after imposition of the duty, has been occupied by the countries under investigation.

79. Since the imports from the subject country are very insignificant, the injury examination in terms of volume parameters for assessing the current injury to the domestic industry will be misleading and inappropriate. The authority notes that this being a sunset review investigation the volume of import during the injury investigation period may not

reflect the true picture of the likely situation of imports and condition of the domestic industry in the event of revocation of the duty.

(b) Price effect of dumped imports and impact on domestic industry

80. The impact on the prices of the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject country have been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression. For the purpose of this analysis the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed value of dumped imports of subject goods from the subject country.

81. The non-injurious prices have been determined for the domestic industry as per the consistent practice of the Authority by appropriately considering the cost of production for the product under consideration during the POI. Since the cost and prices of the machines vary depending upon the clamping force, separate Non-injurious prices have been determined for individual capacities for a fair comparison. Accordingly, price undercutting and underselling effects have been analysed at individual capacity level as follows:

(i) Price undercutting effect

82. Price undercutting has been determined by comparing the weighted average landed value of dumped imports from the subject country over the entire period of investigation with the weighted average net sales realization of the domestic industry for each machine (based on clamping force tonnage). For this purpose landed value of imports has been calculated by adding 1% handling charge and applicable customs duty to the value reported in the DGCI&S import data.

83. In order to determine the net sales realization of the domestic industry, any rebates, discounts, commissions, etc. offered by the domestic industry and the central excise duty paid have been deducted from the total sales realization. For the purpose of price underselling determination the weighted average landed price of imports from subject country has been compared with the Non-injurious selling price of the domestic industry determined for the POI.

Clamping Force (MT)	No. of Machines	Net Selling price Rs/Machine	Landed Value Rs/Machine	Price undercutting (Rs./Machine)	Price undercutting (%)
120	8	****	****	****	
125	1	****	****	(****)	
128	2	****	****	(****)	
150	1	****	****	****	
380	1	****	****	****	
Total/ Weighted average	13	****	****	****	30-40%

84. The above data indicates price undercutting, without taking into account the antidumping duty in force, is significant for several product types and the weighted average undercutting level is also significantly positive.

(ii) Price underselling effect

85. The price underselling is an important indicator of assessment of injury; thus, the Authority has worked out non-injurious prices of the subject goods for each product types and compared the same with the landed values of the imported goods at product type level to arrive at the extent of price underselling. For examining the underselling effects of the dumped imports the landed value of imports, without taking into account the antidumping duty in force, has been compared with the Non-Injurious Price determined for the corresponding product types as follows:

Clamping Force (MT)	No. of Machines	NIP (Rs./ Machine)	Landed Value Rs/Machine	Price underselling (Rs./Machine)	Price underselling (%)
120	8	****	****	****	
125	1	****	****	****	
128	2	****	****	****	
150	1	****	****	****	
380	1	****	****	****	
Total/ Weighted average	13	****	****	****	25-35%

86. The above data shows that the landed values of the dumped imports are significantly below the non-injurious prices of the domestic industry for most of the product types and the weighted average margin is also significant.

(iii) Price Suppression, Depression effects

87. To examine whether the domestic prices are suppressed or depressed due to the presence of dumped imports from subject country the trend of weighted average sales realization of the domestic industry has been compared with the cost of sales and the landed values at weighted average level.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI (Annualized)	Jan-Jun 14 (Post POI) Annualized
Cost of Sales	Rs./No.	****	****	****	****	****
Trend	Index	100	112	125	125	120
Net Sales Realisation	Rs./No.	****	****	****	****	****
Trend	Index	100	103	112	111	106
Landed Value of Imports without ADD	Rs./No.	17,92,987	21,50,412	21,80,647	13,95,407	27,13,504
Trend	Rs./No.	100	120	122	81	151

88. The above data indicates that while the weighted average cost of sales have increased significantly in the injury investigation period the weighted average selling price has not increased at the same rate indicating price suppression.

89. However, the Authority notes that the cost and prices of the subject goods vary significantly depending upon the capacity and other configurations and therefore, any comparison based on weighted average basis may not provide any meaningful understanding of the situation.

H.3. Examination of other economic parameters of the domestic industry

90. Annexure-II to the Anti-dumping Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of like product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

91. The various injury parameters as above relating to the domestic industry have been examined as follows:

(a) Actual and potential impact on capacity, production, capacity utilization and sales

92. The table below shows the capacity, production, capacity utilization and sales of the domestic industry for the product under consideration during the injury investigation period.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI (Oct12-Dec13) (Annualized)	Jan-Jun 14 (Post POI) Annualized
Capacity	Nos	3,650	4,200	4,600	4,600	4,600
Production	Nos	2,260	2,229	2,053	1,997	2,380
Capacity Utilization	%	62	53	45	43	52
Sales Volume						
Domestic	Nos	1,990	1,940	1,737	1,621	1,934
Export	Nos	****	****	***	****	****
	Trend	100	121	123	149	190
Total sales	Nos	****	****	***	****	****
	Trend	100	99	99	88	106

93. The Authority notes that after imposition of antidumping duty the domestic industry has enhanced its capacities in 2011-12. Domestic industry has submitted that the demand for plastic processing machines between 2004-05 and 2010-11 was quite significant and registered good growth during this period. As per the demand projections based on the outlook of various user industries given in Plast-India Report of 2012 the demand for plastic processing machines was expected to reach a level of about 1,50,000 machines per year by 2020. Considering the growth in the industry that was taking place and the potential growth for the product in the Country, major PPM producers in India expanded their capacities with significant fresh investments. However, unfortunately, because of general economic slowdown demand for the products being produced by the users of these machines, specifically auto-component sector saw a significant decline, as a result of which demand for product under consideration declined significantly in the last four years. Consequently, production and domestic sales were affected. There is a significant improvement in the production, sales and capacity utilization of the domestic industry in the post POI period.

(b) Actual and potential impact on profit/loss, cash flow, return on capital employed, inventory, productivity

94. Performance of the domestic industry with respect to the profitability parameters are as follows:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI Annualised	Jan-Jun 14 (Post POI) Annualised
Profit/ Loss	Rs. Lacs	****	****	****	****	****
Trend	Index	100	43	21	19	12
Profit/ Loss before Tax & Interest	Rs. Lacs	****	****	****	****	****
Trend	Index	100	50	26	23	17
Cash Profits	Rs. Lacs	****	****	****	****	****
Trend	Index	100	49	31	28	24
Capital Employed	Rs. Lacs	****	****	****	****	****
Trend	Index	100	138	166	182	171
Return on capital employed	%	****%	****%	****%	****%	****%
Trend	Index	100	36	16	13	10

95. The above data indicates that though the domestic operations of the domestic industry have remained profitable during the entire injury investigation period the net profit of the Company and the return on capital employed has declined sharply since 2012-13. The cash profit has also declined significantly during the injury period.

(c) Actual and potential impact on Employment and Wages

96. The data on employment and wages given below indicates increase in employment and wages though the productivity remains more or less same. The Authority notes that the domestic industry produces plastic processing machines of wide range of capacities and some of them are not included in this investigation. Therefore, the information on employment and wages may not provide a very clear picture of the condition of the industry with respect to the product under consideration.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI (Annualized)	Jan-Jun 14 (Post POI) Annualized
Employment	Nos.	****	****	****	****	****
Trend	Index	100	107	108	107	110
Wages	Rs. Lacs	****	****	****	****	****
Trend	Index	100	128	142	156	177
Productivity	Nos./Day	6	6	6	6	7
Trend	Index	100	100	100	100	105

(d) Actual and potential impact on Inventories

97. Inventory holding of the domestic industry has not been significantly impacted and has remained constant as can be seen from the table below.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI (Oct12-Dec13)	POI (Annualized)	Jan-Jun 14 (Post POI) Annualized
Inventory	Nos.	****	****	****	****	****	****
Trend	Index	100	200	120	360	360	280

H.4 Causal Link

98. The Rules mandates the Authority to examine the causal links between the dumped imports and the injury caused to the domestic industry on account of the dumped imports. The Authority has examined whether other known factors could have caused injury to the domestic industry. The following issues have been brought to the notice of the authority and examined as per information available for the non-attribution analysis:

(i) Imports from Third Countries

99. The Authority notes that imports of the subject goods are entering the Indian market from several countries and imports from some of these countries are significant. The Authority has initiated an antidumping investigation against few countries on the basis of an application filed by the domestic industry. Though the scope of the product under consideration in that investigation is wider, it covers the product under consideration in this investigation also. The import data of the product under consideration from these countries indicate that those imports accounted for about 40% of total imports during POI. Since these are allegedly at dumped prices the performance of the domestic industry could have been affected because of the cumulative effects of these imports. Imports from the other countries not alleged to be dumping account for about 58% of the imports and at higher prices.

(ii) Contraction in Demand

100. The Authority notes that there was a significant decline in demand of the products in the domestic market since the base year. The domestic industry has however, contended that the subject goods are majorly used in electrical, packaging, medical, home appliances and auto sector. Auto sector growth has declined by about 16% during this period, due to which the machines used in this sector are either idle or being used for packaging and other sectors. Thus, while decline in demand in auto sector has led to lower demand in this sector, at the same time, it has triggered a decline in demand in other sectors as well.

(iii) Pattern of consumption

101. No information has been supplied by any interested party to indicate that there is any significant change in the pattern of consumption of product under consideration *vis-a-vis* other competing products affecting the conditions of the domestic industry.

(iv) Conditions of competition

102. The Authority notes that the investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices are responsible for the claimed injury to the domestic industry.

(v) Developments in technology

103. No information has been supplied by any interested party to indicate that there is any significant change in technology in injection moulding or development of new generation machines affecting the domestic industry.

(vi) Export performance of the domestic industry

104. The volume of exports of the domestic industry has increased during the injury investigation. However, the injury analysis in the previous section is based on the domestic performance of the domestic industry. Prices and profitability in the domestic and export markets have been segregated by the Authority for the purpose of assessing injury to the domestic industry.

I. Conclusion on Injury and causal Links

105. The above analysis indicates that the performance of the domestic industry has marginally deteriorated during the injury investigation period on account of decline in production, sales and capacity utilisation; decline in profits and return on investments. Subject goods imported from the subject country, though very small in number, continue to significantly undercut the prices of the domestic industry and also have significant underselling effect on the domestic industry's selling prices. However, the volume of imports from the subject country being too low at the moment and antidumping duty being in force during the POI the volume and price impact of dumped imports does not seem to be significant or material during this period. As noted earlier, combination of various factors, such as significant volume of imports from third sources allegedly at dumped prices; dumped imports from the subject country; and decline in domestic demand, appear to have affected the performance of the domestic industry during the investigation period.

J. Magnitude of Injury and injury margin

106. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority in terms of Annexure III to the AD Rules has been compared with the landed value of the exports from the subject country for determination of injury margin during the POI and the injury margin so worked out is as follows:

Clamping Force (MT)	No. of Machines	NIP (Rs./Machine)	Landed Value Rs/Machine	Injury Margin (Rs./Machine)	Injury Margin (%)
120	8	****	****	****	
125	1	****	****	****	
128	2	****	****	****	
150	1	****	****	****	
380	1	****	****	****	
Total/ Weighted average	13	****	****	****	25-35%

K. Likelihood of continuation or recurrence of injury

107. The Authority notes that this is a sunset review investigation and the focus of this investigation is to examine the likely scenario of injury if the duties are to be removed, even if there is no current injury and/or causal link. In the previous section on likelihood of continuation or recurrence of dumping it has been established that dumping is likely to recur from the subject country in the event of withdrawal of the duties. Since the current imports for subject country is negligible and does not seem to have significant impact on the performance of the domestic industry the Authority proceeds to examine the likelihood of recurrence of injury on account of dumped imports, if the duties are revoked.

K.1 Submissions by the domestic industry

108. The petitioner has claimed that the cessation of anti dumping duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and consequent injury. It has been further claimed that the entire purpose of the review investigation is not to see whether there is a need for imposition of anti-dumping duty but to see whether in the absence of such duty, dumping would continue or recur; and whether the domestic industry would continue to suffer material injury or the injury to the domestic industry would recur if duties are removed. In this regard the petitioner has further submitted as follows:

- That after the imposition of anti-dumping duty on imports of product under consideration from China, other countries namely, Malaysia, Philippines, Taiwan and Vietnam have started dumping the product under consideration into India. The domestic industry has filed an application seeking imposition of anti dumping duties on imports from these countries and the Designated Authority is at present conducting investigation. Though the scope of product under consideration in the second investigation covers much higher tonnage machines, it also covers the subject goods within its scope. Domestic industry is hopeful that the investigation will establish existence of dumping from these countries, causing injury to the domestic industry;
- That the product under consideration continues to be exported to India at dumped prices from the subject country and both dumping margin and injury margin in the current POI are positive and significant. The imports are undercutting the prices of the domestic industry despite anti-dumping duty in force. The landed price of imports is not only below selling price of the domestic industry but also cost of production of the domestic industry;
- That in the event of cessation of anti dumping duty, the landed value of imports from China will be materially below the selling price of the domestic industry. Therefore, the Indian producers would significantly loose volumes in the event of cessation of anti dumping duties;
- That the Chinese producers are not able to export the product without resorting to dumping. And if Chinese producers resort to dumping, the domestic industry shall suffer;
- That China is forecast to account for over 40% of all additional global demand up to 2015 as gains in developing nations become the driving force for plastics processing equipment market growth. China is a largest producer and exporter of the product under consideration and the Chinese producers are highly export centric;
- That the market for the product under consideration has seen some decline in the demand in India. Further, the Chinese producers are also faced with the problems of decline in demand for the product in their domestic market. Thus, in the event of cessation of anti dumping duties, the Chinese producers would rush to the Indian market, given significant demand for the product in the country. Cessation of anti dumping duty will therefore result in significant demand for the Chinese product and same would cause aggravated injury to the domestic industry;

- That the prices at which subject goods are being imported are substantially lower than the price at which the goods are being sold in the domestic market. Therefore, in case of expiry of duty, exporters would further channelize their output in the Indian market as they are already holding excessive capacities and are in fact selling subject goods to third country at substantially lower prices;
- That the Indian market is highly price sensitive. The consumers decide their procurement, with the price being the foremost consideration. Such being the case, availability of such low priced imports from subject country in the market is definitely causing an adverse impact on the Domestic Industry.

109. In its comments on the first disclosure statement the domestic industry has submitted that the instant case being the sunset review investigation, the quantum of duty should remain same as has been recommended by the Designated Authority in the original investigation for the following reasons

- i. The volume of imports from the subject country has declined to low levels and the dumping margin and injury margin determined on the basis of such low volumes will not be reflective of the likely dumping margin or injury margin in the event of revocation of duties. The anti-dumping duty based on such margins will not be able to curb dumping and consequent injury to the domestic industry.
- ii. The producers and exporters have deliberately chose not to respond to the present investigation as they were very well aware that it would have led to higher dumping margins and injury margins. The exporters/producers in subject country have very conveniently put forth their opposition to the investigation through the Association while not providing any information on their price.
- iii. Imposing anti-dumping duty on the basis of the margins determined in the original investigation, when the producers and exporters have cooperated and provided their data would be more appropriate and reflective to their actual price and would be able to curb dumping.
- iv. The exporters and producers should not be rewarded with the lower anti-dumping duty which is the result of their non cooperation.
- v. The Rules provide for a determination of whether the anti dumping duties should be extended further. This implies a decision on whether or not to extend the duties further. While the Designated Authority in practice has also utilized this opportunity to modify the quantum of anti dumping duties, such opportunity is not available where the case is based on likelihood of dumping.
- vi. The practice being followed by third countries such as Canada, US and Europe is to decide whether or not to extend the anti dumping duties. These countries do not at all alter the quantum of anti dumping duties even if there are significant imports in the POI and the dumping margin & injury margin (EC) is quite lower than existing anti dumping duties.
- vii. There is past precedence available wherein the Designated Authority has extended the same quantum of duty as has been recommended in their respective original investigations in spite of dumping margin in review cases being lower than what was determined in the original investigations.

110. Domestic industry has further submitted that anti dumping duty may be imposed as percentage of the CIF value of imports of the subject goods from the subject country (ad valorem form of duty) as the product is already attracting ad valorem form of anti dumping duty at present. Further, the product under consideration includes a number of product types, corresponding to different clamping forces. The associated costs and prices of machines with different clamping forces vary depending upon the clamping force and configurations. There is a significant differentiation of the product in terms of its capacity and prices. Therefore, antidumping duty in terms of reference price or fixed duty would not be appropriate in this case.

K.2 Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties

111. The other interested parties, in their submissions, have argued that the claim of likelihood of recurrence of injury to the petitioner is based on mere conjectures. The other interested parties have inter alia argued

- That the only ground advanced by the petitioners in support of their claim of likelihood of injury is excess capacity in China and attractiveness of the Indian market. It has not been even demonstrated how any such excess capacity, of course if any, would be diverted to India in the absence of duties.
- That mere claim of excess capacity is grossly deficient and stands demolished in the light of factual figures supplied by CPMIA. In fact, it was incumbent of the petitioner to show that how any such excess capacity would be diverted to India in the event of expiry of anti dumping duties which is absolutely missing in the petition. No evidence whatsoever has been submitted by the petitioner in support of their claims.
- That there are no evidences to support their claim as to how injury to the petitioner would recur in case the duties are discontinued. Price attractiveness is only a tenuous proposition on the basis of which the user industry in India cannot be saddled with additional burden of duties for a period of another five years.

- That it is also admitted fact in the application itself that the sales of the subject goods are not only a function of prices but other factors also play an important role such as the evolutions in the machine feature/energy saving efficiency etc. Therefore, the argument of price-attractiveness is self-defeating and cannot form the basis for extending the period of duties in terms of section 9A (5).
- That there exists no spare capacity in China PR and the domestic demand for this product in China is very strong. Also, the third country exports from China PR are at a very high price than the NSR and NIP of the domestic industry. Chinese producers are operating at an above optimal level in terms of capacity utilisation already and there is not even an iota of proof to show that subject goods would be diverted to India at dumped prices if the duties are revoked.
- That the likelihood examination needs to be seen on the basis of fact as it exists and not on the basis of any exaggerated and unsubstantiated misapprehensions of the petitioner.
- That the Indian demand showed a consistent decline whereas the domestic industry has substantially increased its capacities mainly targeting export market. The excess capacity vis-à-vis Indian demand available with the domestic industry is close to 40% and the impact of the same on the fixed cost of the domestic industry should not be attributed to alleged imports from China PR.

112. CPMIA, in its comments on the first disclosure statement, has argued the disclosure statement shows that the domestic industry could not provide any evidence to substantiate likelihood of dumping and injury in the context of expiry of existing anti dumping duties whereas the data provided by CPMIA, which was offered for verification, shows no likelihood of dumping and injury in the event of expiry of current duties. The Chinese producers are operating above optimal levels and they are achieving a much higher price in third country markets. Since the petitioner's data itself shows decline in domestic demand in India, it cannot remain lucrative for the Chinese exporters even by a figment of imagination. Therefore, the anti dumping duties on subject goods may be allowed to expire as the present case before the Authority based on facts clearly shows no likelihood of dumping and injury in the event of expiry of existing measures.

L. Comments of interested parties on the second disclosure statement issued on 14th September, 2015 with regard to injury and likelihood of injury:

113. The Authority issued a second disclosure statement on 14th September, 2015 disclosing the essential facts of the case before the Authority and inviting the comments of all interested parties. The authority notes that in their comments on the second disclosure statement all the parties have mostly re-iterated their respective positions with respect to various issues concerning this investigation. The issues have been dealt in the respective sections adequately and for the sake of brevity are not being repeated here.

M. Views of the Authority on Likelihood of continuation or recurrence of injury:

114. The Authority has noted the views expressed by the domestic industry and other interested parties to the investigation with regard to the likelihood of continuation or recurrence of injury to the domestic industry in the event of the withdrawal of antidumping duty and further notes that the industry continues to suffer material injury because of a combination of factors including the dumped imports from the subject country, though low in volume.

115. The Authority notes that though the current import volumes are low from the subject country the volumes of imports from other countries under investigation are significant. The Authority also notes that a clear likelihood of continuation/recurrence of dumping has been established in the previous section based an objective examination of various factors. Accordingly, for examination of the likelihood scenario of continuation or recurrence of injury to the domestic industry the following factors have been examined:

(a) Level of current and past dumping margins:

116. Level of current as well as historical dumping margins as an indicator of likelihood of continuation of the trend and therefore, potential to cause injury indicates that margins of dumping both in the original as well as present investigation for subject goods are significant though the volume of import from the subject country during the current POI is low because of the impact of antidumping duty in force. This indicates that antidumping duty on the subject country have been successful in preventing large scale dumped imports from the subject country leading to certain improvements in the performance of the domestic industry before deteriorating again because of several factors, including demand, as discussed earlier.

117. Authority further notes that despite the domestic industry holding the capacity to meet the domestic demand, significant volume of import is taking place from certain other countries at much lower prices and these imports are also under investigation. Therefore, there is a very high possibility that once the duties are removed imports will start from China PR at comparable prices. At these prices price undercutting and underselling to the domestic industry's prices will be significant to preventing it to recover remunerative prices.

(b) Price attractiveness of Indian market

118. The Authority notes that though price is not the sole deterministic criteria for purchase decision for products like this, being a capital good, where features and energy efficiencies etc. also play important role, price remains a major consideration. When the goods are of comparable features, price plays an important role. No evidence has been provided by the interested parties to establish that the goods exported from China are not comparable in features to the goods supplied by the Indian producers within their respective capacity ranges. Therefore, the current price levels from China, the magnitude of the antidumping duty, and the current domestic price levels for comparable product types indicate that Indian market will remain attractive for the producers in the subject country to adjust their prices once the duties are revoked and still continue to undercut the prices of the domestic industry. Thus, with the revocation of anti-dumping duty, there is strong likelihood of significantly increased imports of the subject goods from China at prices lower than domestic industry's remunerative price leading to recurrence or intensification of injury to the domestic industry.

(c) Global demand – supply scenario

119. The information submitted by the domestic industry as well as the Chinese Association, though not substantiated with evidences, indicate that there is a clear demand supply mismatch in the Chinese market, capacities exceeding the demand. The volume and trend of imports from other countries under investigation also indicates that there are excess capacities in those countries. Particularly, in a scenario of a depressed demand for the downstream product-lines for which these machines are used, there is clear possibility of aggressive market entry strategies being applied by global players to retain their market share and production lines intact even at dumped prices and the price level will be dictated by their market entry strategies leading to adverse impact on the domestic prices.

(d) Post POI import trends

120. The import of post POI period has also been analysed to see the trends for assessment of likelihood of increased imports and consequent injury. The data presented in the previous section indicates that there is a significant increase in volume of imports from the subject country in the post POI period though the duties were in force while there is only a marginal improvement in the demand. There is a significant import from the countries under investigation during the post POI period. This would indicate a strong likelihood of increased imports from the subject country if the duties are revoked.

(e) Overall assessment of likelihood of continuation or recurrence of injury

121. The Authority notes that the domestic industry is already faced with a low capacity utilisation due to increased imports from several sources at alleged dumped prices coupled with glut in demand. At the current production and price levels the domestic industry is already facing significant decline in its financial result. Therefore, further increase in imports from the subject country at dumped prices, in the event of revocation of duty, will further affect the domestic industry's capacity utilisation and profitability. Therefore, injury to the domestic industry, which still continues to be affected because of combination of several factors including a low demand situation, is likely to be intensified if the duties are revoked.

N. Conclusions:

122. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority, as recorded in this finding, the Authority concludes that there is continued dumping of the subject goods from China though the volume of imports is low and performance of the domestic industry has deteriorated in the current injury period due to the impact of the dumped imports from the subject country and alleged dumped imports from countries under investigation coupled with decline in demand in the recent years. The dumping is likely to continue and the performance of the domestic industry is likely to deteriorate, should the present anti dumping duty is revoked.

O. Indian industry's interest and other issues

123. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the subject goods to the consumers.

P. Recommendations:

124. The Authority notes that this sunset review investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information and verifiable evidence on various aspects of dumping, injury and causal links and likelihood of continuation of dumping and injury in the event of cessation of the duties. Having conducted the investigation as per the procedure prescribed and having established that dumping and injury are continuing and are likely to continue, or recur, if the duties are revoked, the Authority considers it necessary and appropriate to recommend extension of anti-dumping duty on imports of subject goods, from the subject country, in the form and manner described hereunder.

125. Having regard to the lesser duty rules followed by the Authority, the Authority recommends extension of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury so determined in this finding for the period under investigation, so as to remove the injurious effects of the dumped imports on the domestic industry. Accordingly, antidumping duty as a percentage of the landed value of the goods, as indicated in Col 9 of the duty table given below, is recommended to be imposed on all imports of subject goods originating in or exported from the subject country for a further period of five years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government. Landed value of imports for this purpose shall be the assessable value as determined by the customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

Duty Table

Sl. No.	Sub Heading or Tariff Item	Description of Goods	Specification	Countries of origin	Countries of Export	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit of Measure
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	8477.1000	Plastic Processing or Injection moulding Machines	Clamping Force equal to or more than 40 tonnes and equal to or less than 1000 tonnes	People's Republic of China	People's Republic of China	Any	Any	29	%
2	-Do-	-Do-	-Do-	People's Republic of China	Any, other than People's Republic of China	Any	Any	29	%
3	-Do-	-Do-	-Do-	Any, other than People's Republic of China	People's Republic of China	Any	Any	29	%

126. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

127. The Authority may review the need for continuation, modification or termination of the definitive measure as recommended herein from time to time as per the relevant provisions of the Act and the Rules, and Public Notices issued in this respect from time to time. No request for such a review shall be entertained by the Authority unless the same is filed by an interested party as per the time limit stipulated for this purpose.

A. K. BHALLA, Designated Authority